(1600/YSH/MMN)

(प्रश्न 41)

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस प्रश्न की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले वर्ष के पूरे सेशन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 से 7 प्रश्न इस सदन में रखे गए हैं। मैं झारखण्ड प्रदेश से आती हूँ और झारखण्ड प्रदेश को कुपोषण के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त है और मैं जिस जिले का प्रतिनिधित्व करती हूँ, वह जिला पूरे भारतवर्ष में चौथे नम्बर पर आता है। ऐसे में इस प्रश्न की गंभीरता बनती है। मैं अपने मूल प्रश्न पर जाने से पहले इस विषय पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। झारखण्ड में समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के वर्ष 2021 के सर्वे के अनुसार पिछले छ: महीने में एक बार भी 55 प्रतिशत से ज्यादा पोषक आहार नहीं दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आपका प्रश्न क्या है?

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पर ही आ रही हूँ। मैं यह चाह रही थी कि मैं बता सकूँ कि वहां की वस्तुस्थिति क्या है, क्योंकि वहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कुपोषण ने भयावह रूप ले रखा है। इसलिए मैं इस विषय को बताना चाहती हूँ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको अभी बोलने की इजाजत नहीं मिली है।

… (व्यवधान)

(1605/RPS/VR)

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): अध्यक्ष महोदय, शून्य से छ: वर्ष की आयु वाला हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। वहां पर पिछले कई दिनों से सिर्फ इन बच्चों को ही नहीं, किशोरियों और गर्भवती माताओं को भी कई दिनों से पोषाहार नहीं मिला है। ऐसे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या मंत्रालय द्वारा इस सन्दर्भ में कोई अध्ययन किया गया है कि बच्चों, किशोरियों और गर्भवती माताओं को इस योजना का पूर्णरूपेण लाभ मिल रहा है? मैं अध्ययन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं, क्योंकि धरातल पर कहीं उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है और इसलिए आज वहां सबसे अधिक कुपोषण की स्थिति है।

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जो आरोप इस सदन में प्रस्तुत किया, वह अपने आप में अति गंभीर है। यह आरोप गंभीर इस दृष्टि से भी है कि प्रदेश की सरकार पोषण अभियान के सन्दर्भ में जो सूचना केन्द्र सरकार को भेजती है, केन्द्र सरकार उसी पर निर्भर होकर, आगे की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाती है। प्रदेश सरकार ने हमारे विभाग को यह सूचना दी थी कि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का खलल नहीं है, जो बच्चे और महिलाएं लाभार्थी हैं, उनको व्यवस्थाओं का पूर्णत: लाभ मिल रहा है, लेकिन आज मैंने सदन में माननीय सदस्य का जो कथन सुना है, उसकी गंभीरता को देखते हुए, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार से इस बारे में जवाब मांगने का हमारा प्रयास रहेगा।

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): अध्यक्ष महोदय, मैं दो चीजें जोड़ना चाहूंगी। इसमें जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं काम कर रही हैं, वे दिन-रात मेहनत कर रही हैं कि इस अभिशाप से मुक्ति मिले। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आज केन्द्र सरकार उनको मात्र 4500 रुपये देती है, जो न्यूनतम मजदूरी दर से भी बहुत कम है, इसलिए उनका मानदेय थोड़ा बढ़ाया जाए। साथ ही, झारखण्ड राज्य में कुपोषण सेंटर, जो अस्पताल हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। मेरे जिले में 3015 बच्चे कुपोषित हैं। वे बच्चे अति कुपोषित बच्चों की श्रेणी में आते हैं और वहां मात्र 50 बेड्स हैं। क्या इन कुपोषण सेंटर्स में सीट्स बढ़ाने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगी?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि पिछले साल 13 जनवरी को एक कन्सॉलिडेटेड गाइडलाइन हर प्रदेश की सरकार को दी गई है। हमारा संकल्प है कि कुपोषित बच्चों की संख्या कम हो और इस प्रकार के सेंटर्स की हमारे समाज में जरूरत न पड़े। इस सन्दर्भ में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगी कि हर माननीय सदस्य से यह आग्रह किया गया है कि 'दिशा' की मीटिंग में विशेष रूप से पोषण अभियान और आंगनवाड़ी व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में चिन्ताएं स्वयं माननीय सदस्य करें तो जिला प्रशासन इस विषय को अधिक गंभीरता से लेता है। पहली बार भारत सरकार ने जिला, प्रदेश और केन्द्र की सरकार में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की व्यवस्था की है, जिसमें हमारे सांसदगण भी सम्मिलित हैं, जो न्यूट्रिशन की दृष्टि से कैसे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सकते हैं, इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि किस प्रकार से आज आंगनवाड़ी बहनें अपना योगदान दे रही हैं, मैं आंगनवाड़ी बहनों के सम्मान में कहना चाहती हूं कि आप जिस राशि का उल्लेख कर रही हैं, उसे हम सैलरी नहीं, ऑनरेरियम कहते हैं, क्योंकि वे सेवा की उपाधि में आंगनवाड़ी से जुड़ती हैं। यह विषय सुप्रीम कोर्ट तक सेटल हो चुका है और उनके सम्मान में ऑनरेरियम बढ़ाने का संकल्प और समाधान, दोनों ही नरेन्द्र मोदी सरकार ने दिया है। पहले 150 रुपये से आज आप जो 4,500 रुपये की बात कर रही हैं, वह भारत सरकार के सौजन्य से ही संभव हुआ है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हमारे डिस्ट्रिक्ट में कभी 'दिशा' कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाते हैं, तो वहां कैसे पता चलेगा? माननीय मंत्री जी कहती हैं कि 'दिशा' मीटिंग में पता कीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं, उनके सामने बताएंगे।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे ।

… (व्यवधान)

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रश्न पर सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत शिशुओं का टीकाकरण भी कराया जाता है और किशोर वय लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि हम 15 से 18 साल के लोगों के लिए जो कोविड टीकाकरण शुरू कर चुके हैं, उसको और बढ़ावा देने के लिए, खासकर किशोर वय लड़कियों के लिए इसमें इम्युनाइजेशन का कोई प्रावधान मंत्रालय रखना चाहेगा, जिसके माध्यम से कोविड टीकाकरण को हम लोग बढ़ावा दे सकें।

(1610/SPS/SAN)

फिलहाल कॉलेज और स्कूल हर जगह पर फिजिकल शुरू नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में शायद आपके आगे आने से इस टीकाकरण को हम बढ़ावा दे सकते हैं। क्या इसके बारे में मंत्रालय ने कुछ सोच रखा है?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : प्रीतम जी ने अप्रतिम सुझाव दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। वह स्वयं एक सम्मानित डॉक्टर हैं। हां, मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगी कि आंगनवाड़ी और आशा की जो हमारी बहनें हैं, वे समन्वय के माध्यम से टीकाकरण में चिन्हित जो बच्चे या परिवार हैं, उनके संदर्भ में जानकारी जिला अधिकारी को अवगत कराती हैं। प्रीतम जी का सुझाव है कि आंगनवाड़ी व्यवस्थाओं में हमारी जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, उनको भी टीकाकरण के इस अभियान से जोड़ा जाए। मैं उन्हें बतलाना चाहूंगी कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से यह व्यवस्था वर्तमान में हर जिले में स्थापित कर दी है। निश्चित रूप से किशोरी बालिकाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है।

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Sir, ICDS is a wonderful programme aiming to enhance the development and survival of children from the vulnerable sections of our society. However, various problems have been reported by the anganwadi workers, like lack of proper storage facilities, non-availability of separate kitchens, inadequate and irregular supply of food rations, and poor quality of food as well as the problems of fuel.

I want to know from the hon. Minister what kind of measures the Government is taking to address these problems.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I would like to, through you, tell the hon. Member that it is true that the system that has been pronounced in our country from the 1970s onwards, has had many challenges operationally. In fact, today as a part of the Government of India’s efforts, we have ensured convergence of 18 Ministries under the Poshan Abhiyan.

The hon. Member has enunciated her angst with regard to infrastructural challenges, such as water, toilets or storage spaces. I would like to bring to the attention of the hon. Member that with regard to infrastructural challenges as well, the Government of India, under the aegis of the Secretary of Women and Child Development Ministry, does engage regularly with our State Department representatives so that these infrastructural challenges can be adequately met not only through capital expenditure but also through convergence of efforts, such as under programmes like MGNREGS.

Sir, with your permission, a senior leader in the House has lamented the fact that he cannot participate in the DISHA meetings in his home State. Sir, with your kind permission, I would also like to highlight to him that in this very august House, for the past two years, it has been my endeavour to encourage the State of West Bengal to join the Poshan Abhiyan. Sir, I am happy today to, through you, inform the august House that the Government of West Bengal has finally conceded and joined Mission Poshan.

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दिनांक 13.01.2021 की भारत सरकार की गाइडलाइन्स में केन्द्र से राज्य सरकार के आईसीडीएस में फण्ड दिया गया है, जिसमें बच्चों को फ्री राशन दिया जाता है। कई सरकारें इन गाइडलाइन्स का पालन नहीं कर रही हैं। केन्द्र सरकार का फण्ड होने के बावजूद हमारे महाराष्ट्र में आज भी उन्हें ड्राई रॉ राशन दिया जा रहा है। ऐसी सरकारें केन्द्र की गाइडलाइन्स फॉलो नहीं करती हैं और फण्ड केन्द्र का इस्तेमाल करती हैं। जब पिछली बार मैंने मंत्री महोदय से इसका क्वेश्चन पूछा था तो मंत्री महोदय ने कहा कि हम उन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं और कैसे कार्रवाई कर रहे हैं? अगर उनका फण्ड रोकना चाहते हैं या वे गाइडलाइन्स का पालन नहीं करते हैं और केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स को अपमानित करते हैं तो आप इसमें आगे क्या प्रावधान ला रहे हैं?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि विषय अपमान का नहीं है, संविधान का है। इसके संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि अगर प्रदेश की सरकार नियमानुसार पैसा खर्चा करेगी, तत्पश्चात् भारत सरकार की ओर से निश्चित रूप से आवंटन होगा। महोदय, आपके माध्यम से पिछले सत्र में भी माननीय सदस्या ने इस विषय को उठाया था। यह गम्भीर विषय है। मैं दोबारा इस सदन में कहना चाहूंगी कि 13 जनवरी की हमारी जो गाइडलाइन है, उसमें हमने विशेष आग्रह किया है कि आप टेक होम राशन को ड्राई राशन के रूप में वितरित नहीं कर सकते हैं।

महोदय, इसमें दूसरी बात यह है कि आप अगर पोषण अभियान के अंतर्गत कोई भी प्रोक्योरमेंट करते हैं तो सीवीसी की गाइडलाइन्स और जनरल फाइनेंस रूल्स का उल्लंघन करके देश में कहीं भी प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता है। अगर कानून का उल्लंघन होगा, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जिसमें यह भी एक विषय है कि पैसा आबंटित करने में फिर हम सक्षम नहीं हो पाएंगे, फिर दोष प्रदेश की सरकार का होगा।

(1615/RAJ/SNT)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Hon. Minister, Smriti Irani Ji, I would like to express my gratitude on behalf of our party and women folk for sending favourable recommendations of DISHA committee to the Law Department which came from Government of Andhra Pradesh under the leadership of our Chief Minister, Jagan Mohan Reddy Garu. Thank you, Madam.

I would like to ask whether the Government considered reorienting anganwadi workers to closely engage with the parents in order to promote responsive parenting under ICDS.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, it is quite a pleasure at times to hear appreciation from people who are not politically aligned to you. However, this compliment is deservedly the right of the hon. Prime Minister whose vision was to converge the efforts between different Ministries under the POSHAN Abhiyaan.

Insofar as the hon. Member's query as to whether parents are to be integrated in terms of their feedback or their engagement with the anganwadi systems, yes, we, through the angandwadi systems and especially through POSHAN Abhiyan do community based interventions and events with parents, with community members to ensure that this is a dynamic and robust engagement through the angadwadi systems, for the angadwadi systems which serve the very community in which it is established in through tax payers' money.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : पहला प्रश्न महिला मंत्री और महिला सदस्यों के नाम समर्पित हो गया, इसलिए माननीय सदस्यों को अगली बार बुलाएंगे।

क्वैश्चन नम्बर 42, श्री सुनील कुमार सिंह जी।

(प्रश्न 42)

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, इसलिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी ने अपने उत्तर में सरकार द्वारा मुकदमेबाजी के मामले में कमी लाए जाने वाले उपायों का विस्तार से विवरण रखा है। वर्तमान में लंबित 50 प्रतिशत मामले रेल और वित्त मंत्रालय से संबंधित हैं, जिनके लिए रेल और वित्त मंत्रालयों ने सभी स्तरों पर न्यायालय मामलों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अनुदेश जारी किए हैं। Legal Information Management and Briefing System, web portal एवं application के द्वारा सभी मामलों को मॉनिटर किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 100वीं रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य में सरकारी मुकदमों के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु लिटिगेशन लोकपाल की स्थापना की अनुशंसा की गई थी, तथा 126वीं रिपोर्ट में सरकारी विभागों के अंतर्गत एक शिकायत निवारण तंत्र के गठन की अनुशंसा की गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री किरेन रिजीजू : सर, सुनील कुमार सिंह जी ने जो एप्रिशिएट किया है, हम ने उसका डिटेल में जवाब देने का प्रयास किया है। सरकार और प्रधान मंत्री जी की यह मंशा साफ है कि आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके, हर मामले को सुलझाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने राज्य के बारे में लॉ कमीशन की रेकमेंडेशन का जिक्र किया है, उसका इस सवाल से सीधा-सीधा संबंध नहीं है, फिर भी मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम राज्य सरकारों से तालमेल करके यह चाहते हैं कि कोई भी कार्य जो सरकार की दृष्टि से बहुत जरूरी है, आम जनता के फायदे के लिए सरकार का हर विभाग ऐसा कदम उठाए, चाहे वे करप्शन के केसेज हों या आम सिविल केसेज हों, जल्दी से जल्दी उनमें सुलह हो जाए, इसके बारे में लगातार प्रयास जारी है।

(1620/VB/SRG)

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि लम्बे समय से बड़ी संख्या में मुकदमे पेंडिंग हैं। केन्द्रीय अधिनियमों के तहत गठित जो विभिन्न अधिकरण, आयोग, प्राधिकरण हैं, जैसे रेलवे दावा अधिकरण, आयकर अपील अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, राष्ट्रीय कम्पनी वित्तीय अभिकरण, दूरसंचार विवाद समाधान अपील अधिकरण, विद्युत अपील अधिकरण, केन्द्रीय प्राशासनिक अभिकरण आदि अनेक अधिकरण हैं, इनमें सदस्यों की काफी रिक्तियाँ हैं। क्या इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए सरकार ने कोई निर्णय लिया है? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा ताकि कार्यों के निष्पादन में तेजी आए।

श्री किरेन रिजीजू : माननीय अध्यक्ष जी, कोर्ट के ऊपर दबाव कम हो और कोर्ट के बाहर जो भी व्यवस्था है, उसमें केसेज के सुलह के लिए ट्राइब्यूनल्स क्रिएट किए गए हैं। माननीय सदस्य ने इसके बारे में जानने की जो इच्छा जताई है, मैं कहना चाहता हूँ कि हर विभाग के अन्दर एक ट्राइब्यूनल क्रिएट किया गया है और ट्राइब्यूनल्स की जो कम्पोजिशन है, उसका एक स्टैब्लिश्ड सिस्टम बनाया हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट के जजेज के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन होता है, वह कमेटी नाम रेक्मेंड करती है, फिर वह सरकार के पास आता है, उसके बाद एप्वाइंटमेंट की प्रक्रिया होती है। मेरे मंत्रालय से संबंधित अपीलेट ट्राइब्यूनल है- इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। इसके बारे में मैं सीधे-सीधे बता सकता हूँ कि यह रेकॉर्ड है कि पिछले दो सालों में लगभग 90 हजार केसेज से घटकर पेंडेंसी को 60 हजार के आसपास लेकर आए हैं। इसके लिए मैंने इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के चेयरमैन और सारे मेम्बर्स को बधाइयाँ भी दी हैं। मैं लगातार रिव्यू भी करता रहता हूँ। इसी प्रकार से इस देश में जितने भी ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, सभी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और वैकेंसी के बारे में आप जो पूछ रहे थे, तो उसमें भी भर्ती की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): I have gone through the detailed reply that has been given by the hon. Minister. While I appreciate the efforts being taken by the Government to reduce the litigation, I am having one question as well as a suggestion. In this Parliament I think the hon. Minister introduced The Mediation Bill which has been referred by the hon. Speaker to the Standing Committee. The Bill is being debated. The way in which it was piloted, it is really going to have a very big impact on the judicial system of our country. There is no doubt about it. How it is workable is yet another question. It is being debated in the Parliamentary Standing Committee. My suggestion is this. You are going to devise a policy. This policy is within the Government and the Government Boards. But the Mediation Bill is having a universal impact, it covers third party also. Any policy which does not have any statutory binding, as the hon. Minister knows, is only a policy because if it is breached, nobody can question it. I have a question here. In the Mediation Bill, is any specific provision going to be incorporated with the same motto and the same objective? If you do that, it will really reduce litigations in this country. I expect a positive and an affirmative reply from the hon. Minister.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, hon. Member Shri Raja Ji has a rich experience of the governance system. We have many constraints in terms of settling the cases, and the total amount of pendency in our country is rising very fast. The Government is very much concerned about the rising number of cases. That is why, we are talking about alternative dispute resolution mechanisms. So, Mediation Bill which has been introduced and which has gone to the Standing Committee, and which will come back, will be deliberated upon in detail and the Committee will come out with more concrete suggestions, if any.

But I am very confident that the Mediation Bill has been prepared in such a way that there is very little scope for criticism. Rather people will appreciate it or if there are any, they will add value to the provisions in the Mediation Bill. The basic purpose of this Mediation Bill is to ensure that the pre-litigation in our country takes a wider scope because mediation is part of the Indian ethos and Indian traditions, and for ages, for millennia, mediation has been practiced in our society. That is why, Raja Ji's suggestion is very welcome. It is going to be a very comprehensive policy. Within that, all the provisions are taken of. I do not want to tell in detail about the provisions, but if you go through the provisions of the Mediation Bill, it is going to be appreciated across the sections of this hon. House as well as by the people of this country.

(1625/AK/VB)

I am sure that when we pass the Mediation Bill from this august House, it will bring in lots of reforms in our society, especially it will give relief to the small-time people who do not have the capacity or resources to go to the court and manage the entire process. Thank you.

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): Thank you, Sir. On one hand there are luxurious litigation and superfluous cases, and on the other hand there is a huge vacancy of Judges in the High Courts and Tribunals as well as stagnation in the judicial capacity. Why is it that the Government is unable to provide affordable justice by regulating the exorbitant legal fees charged by the advocates and thereby actually denying justice to the commoners and the '*aam*' litigants?

SHRI KIREN RIJIJU : Sir, the question posed by my dear friend Pradyut Bordoloi ji is very important and serious in nature also, but at the same time there are constraints.

Sir, you know very well that it is very difficult for the Government to put a cap or regulate the court fees or the fees of the advocates. I have stated in some of the public forums also that in our country it is very sad for the Law Minister to say that some of the advocates are so expensive that it is very difficult and beyond the common man's affordability.

I have discussed with the Bar Council of India and with all the stakeholders that we should make sure that advocates and good lawyers are available to the needy people, but at the same time the legal aid programme, outreach

programme launched by the Government of India through the Supreme Court, NALSA, and the State Legal Service Authorities up to the Talukas are going with the motto that we must provide easy and accessible services to the common people. At the same time, I also insist about the provisions of providing free legal aid and *pro bono.* Some advocates should take up the cases free of cost. The hon. Supreme Court Judges also have been appealing that advocates, especially young advocates should inculcate this culture of *pro bono* to provide free legal aid or at minimum cost, and the Tele-law and some other provisions launched by the Government of India are actually reaching out to the people.

I share the concern of the hon. Member, and I am going to start it as a big campaign on the advice and blessings of the hon. Prime Minister. We must ensure that nobody is denied justice just because he cannot afford a good lawyer. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कल्याण बनर्जी जी, आप बैठे-बैठे ही बोलें। आपके पैर में चोट है, इसलिए आप बैठकर ही बोलें।

माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप बैठकर बोलने की कोशिश करें। राज्य सभा खाली पड़ी है, ऊपर की गैलरी खाली पड़ी है। इसलिए सभी से मेरा आग्रह है कि हमने जो कोविड गाइडलाइंस बनाई हैं, उनका पालन करें। आप लोग राज्य सभा में भी बैठें, ऊपर की गैलरी में भी बैठें। मैं सदन के सभी फ्लोर लीडर्स से यह आग्रह करना चाहता हूँ।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): हम सभी आपके नजदीक ही बैठना चाहते हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, आपके पैर में चोट है, इसलिए आप बैठकर ही बोलिए।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): The hon. Law Minister has said so many things. I appreciate everything, but one point still remains, namely, the vacancies are not being filled up. You are saying that you are taking steps with inquiry, re-inquiry and so on. Where did you fill up the vacancies of the High Court Judges or vacancies in the Tribunals? You have given reference of the Income Tax Tribunal. What about the Central Administrative Tribunal? Nothing is functioning.

I am not making any complaint and do not take it otherwise. You should not get emotional thinking that I am mentioning it, but I am concerned about the fact that the vacancies are not getting filled up. Kindly do it.

(1630/SPR/PC)

SHRI KIREN RIJIJU: My good friend, Shri Kalyan Banerjee has asked certain questions and he has also made certain remarks, especially with regard to the appointment of the Judges. It is very difficult for me to pinpointedly answer the queries which he has asked. I have stated in the discussion which took place last time in this august House that the Government has the bounden duty to carry out some due diligence while appointing the Judges. We have a prescribed system here.

I know what the hon. Member is referring to. He is referring to a particular High Court, and a particular name, about which I am not ready to divulge the names here nor am I here to indulge in this particular thing. But if you can pick up the reports of the past many decades, you will know how many Judges have been appointed since I took over as the Minister of Law and Justice of this country. Since last July until now, do you know how many Judges have been appointed in the Supreme Court and in different High Courts of the country? The hon. Chief Justice of India has publicly stated and appreciated that the process has been the fastest ever since the last few decades. That is why, let us appreciate that if there are any constraints and delay, it is not because the Government does not want to appoint Judges at a fast pace but because there is a provision in the Memorandum of Procedure. The Collegium and the Government are working in tandem and our effort is to fill up all the vacancies as fast as possible, but there are certain vacancies which would always remain because there is a process – when somebody retires, how the name comes from the Collegium, from the High Courts, etc/ During this process - certain time is taken. I do admit that but the system is such that I cannot avoid the system. Thank you.

(ends)

(Q.43)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, I would like to thank the hon. Minister for giving very comprehensive and detailed replies to the question I have asked. My question to him, through you, is very specific to the construction of a new Greenfield Port at Bavanapadu, which is in my constituency. I would like to know the status of this Port from the hon. Minister. What would be the contribution to it from the Government of India? Are there any permissions still pending regarding the approval of the Port?

SHRI SARBANANDA SONOWAL: I am very much thankful to Shri Ram Mohan for bringing this particular, very important question before this House. For your information, the Andhra Pradesh Government is developing a Greenfield port and whatever measures needed for awarding of the contract for the construction of the port were already taken up. As per the information provided by Maritime Board of Andhra Pradesh, in the later part of this month, the contract could be awarded. I believe that you need not have to worry because your Government is very much serious in this particular matter.

Regarding the financial support, if the proposal comes from the Government of Andhra Pradesh, then, definitely, SagarMala programme will always be a part of it.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): My second question is more into the SagarMala project. Already there are certain proposals which are under consideration and under the due process of construction. There are also some changes which are proposed. There are new proposals also. So, I would like to know if we want to include new projects in the SagarMala project, what is the process that we have to follow.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: For the information of the august House, let me inform the procedure. Whatever principle has been decided to develop the SagarMala programme, particularly for the development of the ports, management of the ports and new ports, terminals, enhancement of connectivity and community development, enhancement of tourism jetties, and fishing harbours, all these aspects are there in the SagarMala programme. So, in this regard, if we receive the proposal connected to the principal point from the State Government, we will definitely look into the matter positively.

(1635/UB/KDS)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, Kochi has a huge coastal line right from Chellanam to Cherai. We are blessed with numerous harbours, ports, container terminals and the prestigious Cochin Shipyard Limited which the hon. Minister visited a few months back and reviewed the projects including the INS Vikrant which is the first indigenous aircraft carrier built in India.

During the last budget, the hon. Finance Minister announced to modernise major harbours into state-of-the-art harbours and develop all the basic infrastructure for modern harbours. Cochin was one among those harbours on which, right from where the fish are caught and transported to the storage facility, including washrooms and all the major infrastructure, a Detailed Project Report of Rs. 140 crore was submitted by the Cochin Port Trust. Two of the harbours which were announced have already commenced the work. So, what is the status of the Cochin harbour? I would like to know whether the Government would take necessary steps to expedite this project.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Regarding the Cochin Fishing Harbour, the tentative cost is Rs. 300 crore. In convergence with the Department of Fisheries, a special purpose vehicle has already been formed for harbour and a revised DPR is now awaited. After receiving all this, my Ministry will definitely look into the matter. It is a very important project because Sagarmala Project always encourages the construction of fishing harbour, encourages our fishermen, creates avenues for the employment opportunities and for people to earn livelihood. That is why, hon. Prime Minister is always very much keen to develop the Coastal Economic Zone. All the people living in the coastal States must have proper facility to get themselves employed and also to get better facility to earn their livelihood. With this noble objective, this particular programme is now under implementation. These are some of the projects which are under development. This is the latest position.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, the Draft National Logistics Policy 2019 indicated ‘measures will be taken to reduce logistics cost to 10 per cent from 14 to 15 per cent’. On the east coast, most of the international cargo is landing at the Columbo Port and almost 60 per cent of the cargo loading and unloading is happening at the Columbo Port.

Smaller ships have to go to Columbo Port to bring goods to India and the Indian economy is losing out to a large extent because of this. Having transhipment hub ports in places like Thoothukudi and developing it will really help our economy. We made repeated requests to the Government for the transhipment hub. I would like to know the status of it.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, this is a very, very important question that the respected Member has raised in the House because the issue of draft depth is a very, very critical issue for Indian coastline right from Gujarat to West Bengal. We have a total 7,500 km coastline. These are the major challenges that we are facing. That is why dredging is a mandatory initiative on our part to maintain the draft so that our cargo vessel can come and operate.

(1640/KMR/CS)

So, this is a very important matter, a matter of serious concern, and the Ministry is seriously considering it. We are now looking forward to developing a transhipment hub in the country. There are some areas which have been under survey. I will definitely be able to let the august House know within a short span of time how the Government is very aggressive on this particularly to get this particular facility provided to the Indian exporters and importers so that in the near future whatever export-import cargo is transported through different destinations can be easily done here for a better growth of our national economy. Thank you.

(ends)

(Q. 44)

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Respected Speaker, Sir, the initiative of Government of India to bring in chip-based e-passport is welcome. However, we have some concerns. Hon. Minister has given detailed answers regarding chip-based e-passports. I wish to know the hon. Minister's response on the following points as well. What measures have been taken to ensure data security of Indian citizens who are going to be issued with chip-based e-passports; and will it be violation of individual's right to privacy?

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, the purpose of issuing e-passports is to make it easier and smoother to travel, and also to ensure better security of the data of the passport holder. What the e-passport has is the data on the sheet like a regular passport as well as the data with the photograph on an inlay sheet which is put in the back cover of the passport.

In terms of the data security, the data is put into the chip through a personalisation process. This, then is printed using a specialised printer. Then there is establishment of a public key infrastructure which will do a digital signature. That digital signature is of the issuing country. It is like a certifying authority. There is a company which is specialised which will do this on behalf of Government of India. That digital signature will be sent for recognition to other Governments. Along with that, there will be other digital keys which will verify the passport at every stage - when the chip is made, when the inlay is made, when ISP Nashik is putting the inlay in the passport, when the passport office is loading the data or when the Embassy is loading the data, and when the passport is issued. In addition to that, of course, we are testing it in a testbed so that it is secure, we can show to ourselves and to other countries also that it is secure. So, there will be multiple layers of security. I think because it will be both on paper as well as chip, the average citizen will find that the passport data is much more integral and more protected than it would be in other circumstances.

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, my second question is, whether chip-based e-passport system will reduce the time taken for issue of Indian passports when compared to present system, and would strengthen Indian passport when compared to passports issued by other nations.

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, I would like to inform the hon. Member through you that the entire world is moving now to chip-based passports. So, we also have to move. We are very confident. We have already started the process. I have stated in my reply that we have issued Letters of Intent for 4.5 crore chips and antennae to be procured. We expect that once we award the contracts, which will take a little time, within six months we will be in the process of issuing the passports. We will do it in this financial year.

(1645/RCP/KN)

In terms of the speed of issuing passports, once it becomes routinised – I think, the hon. Member would appreciate that actually the speed of passport issual has become much faster – we have every confidence that we will be able to keep to the same scheduling and the same speed.

माननीय अध्यक्ष : श्री रविन्दर कुशवाहा – उपस्थित नहीं।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I have been listening attentively to the hon. Minister but he has not fully addressed the concerns either of my hon. colleague or myself on the question of security. The Ministry has declared that they are going to be embedding this in the passport with a Radio Frequency Identification (RFID) chip. That is embedded and that is going to be in the passport as the Minister has explained. You know, there have been global studies that have indicated that these RFID tags can be so-called skimmed. If there is anybody entering with that passport to any location, within a few feet of that person, people can skim the data, copy it onto another chip or another RFID card. There have been examples given. For example, the American Civil Liberties Union has published a report on precisely this danger saying that terrorists, ID thieves, Government agents, marketeers, retailers, anybody could do this with the appropriate technology available. So, the worry we have is this. Are we exposing our citizens to greater danger? Are we putting ourselves in a position where if the data is skimmed, vital information about our citizens can fall into the hands of others? A passport is an essential document but you have to give it in a number of places. Anybody can take it off and copy this chip. I am wondering what kind of measures can be taken to ensure that this does not happen before we actually introduce a document that could put our own citizens in danger. Thank you, Sir.

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, I would like to inform the hon. Member that we are very, very cognizant of the danger of the skimming vulnerability. So, in fact, one of the reasons why the sample passports are going through a testbed process is to ensure that very casually – because it will be a sheet at the back – if you go through, let us say, an immigration counter, that unless you actually handover the passport, the data will not be captured. Until we are sure of that, naturally we will not introduce it.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Through RFID, it can be captured… (*Interruptions*)

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Again, I would like to underline to the hon. Member that until we are sure that the skimming danger is adequately addressed, naturally we will not be going forward. But we have every confidence; that will be the case. We are very cognisant of that.

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Thank you so much, Speaker, Sir. I appreciate that India is taking positive steps and the Finance Minister has announced in her Budget Speech that e-Passports will come. Even in the detailed answer the Minister has said that one of the benefits of the e-Passport is that the immigration process will be smooth for the Indian passport holders. But the irony is that wherever an Indian passport holder or an Indian goes, they are treated like third-class citizens, especially in our own country. When you travel to UAE, there is a special counter for UAE citizens who can just walk through. If we go to Malaysia, there is a separate counter for Malaysian citizens where they can walk through. If you go to European Union, the European Union citizens can walk through. In India, we are made to wait to stand in a queue, and look like criminals. Anything what you have, it does not speed up the process. This is my genuine request; whether you put a chip in it, put anything, the process is the same. In what way for a common Indian the process is going to be changed?

The second part of my question is this. When you are going to introduce this e-Passport, will it be uniform across the country or will certain States like Gujarat or Delhi be selected and will the States of the South like Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka be ignored?

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, first of all, the first question of the hon. Member pertains to the Bureau of Immigration. I think, the Member's characterisation of the situation at airports is quite unfair. I do more airport travelling probably than any other Member of the House. … (*Interruptions*) It is because of that I am not blind. I also look at what is happening in other counters. I think, all the Members should be fair enough to recognise that airport processes have improved. I grant you; there is room for improvement. There is room for improvement in the airport and in the BOI counters. It is a valid concern but please do not sort of give it such a sweepingly negative characterisation. That is not fair.

(1650/RK/GG)

The second issue is even more unfair. On the passport side we have never discriminated in favour of any State or against any State. I resent that. I think that is completely uncalled for, and I would urge the hon. Member not to make such comments.

(ends)

प्रश्न 45

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी, दोनों की लीडरशिप में भारतीय सेना को सैल्युट करना चाहता हूँ। देश की सीमा सुरक्षा के साथ-साथ लद्दाख जैसे बॉर्डर एरिया में एजुकेशन में भी काफी कॉन्ट्रिब्युशन इंडियन आर्मी की ओर से किया जा रहा है। ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल भी चलाए जाते हैं। लद्दाख में सैनिक स्कूल अभी तक नहीं खुला है। मेरे प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से दिया है। पूरे देश भर में जो सौ नए सैनिक स्कूल खोले जाने हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, कॉमन गाइडलाइन क्या है? यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। लद्दाख जैसे विशेष क्षेत्र में, खास कर पिछले सत्तर सालों में हमने जो सफर किया। वहां पर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, एलओसी और एलएसी लगते हैं। क्या ऐसे राज्य के लिए कोई विशेष प्रायोरिटी है? क्योंकि कॉमन गाइडलाइन में जाते रहेंगे तो बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाते हैं। लद्दाख में सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने के लिए क्या कोई विशेष प्रायोरिटी माननीय मंत्री जी देंगे? यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

1652 बजे (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन पीठासीन हुए)

श्री किरेन रिजीजू: माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य लद्दाख से आते हैं। जामयांग शेरिंग नामग्याल वहां के बहुत ही होनहार सांसद हैं। लद्दाख के लोगों के प्रति भी हम लोग सब जानते हैं। मैं उनके प्रति आदर प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत ही देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं।

जो ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम इंडियन आर्मी चलाती है, उसके तहत जितने भी स्कूल्स, खास कर बॉर्डर एरियाज़ में चलाए जाते हैं, उसके तहत लद्दाख में कुछ स्कूल्स हैं, मैं उनके नामों का जिक्र करूंगा। एक आर्मी पब्लिक स्कूल लेह में है। उसके अलावा आर्मी गुडविल स्कूल्स हैं, वे खारू, द्रास, बरोंडा, हरका बहादुर, परतापुर, त्याक्सी और बुदखन में हैं। इन इलाकों में आर्मी पब्लिक स्कूल्स इस वक्त चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त रीसेंटली भारत सरकार ने एक प्रपोज़ल अप्रूव किया है कि सौ सैनिक स्कूल्स एक साथ देश में खोले जाएंगे। उसके लिए एक प्रक्रिया है। अनफॉर्चुनेटली लद्दाख से नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए किसी एनजीओ, वहां के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी एग्ज़िस्टिंग इंस्टिट्यूट की तरफ से कोई एप्लिकेशन नहीं आई है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर इस प्रक्रिया में कोई जगह खाली रह जाती है तो लद्दाख के लिए भी सैनिक स्कूल के बारे में भारत सरकार की तरफ से पॉज़िटिवली सोचा जाएगा।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): सर, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है। माननीय किरेन जी लद्दाख के बारे में और भी अच्छी तरह से जानते हैं। सर, मैं बॉर्डर स्टेट के लिए इसलिए विशेषता मांग रहा हूँ क्योंकि जिस तरह आप सब जानते हैं, हुंद्रमान, द्रास, हारदास, तूरतुक एरिया जो हैं, ये सारे एलओसी में आते हैं। उसी तरह से खोपरांग, दिमजोक, त्रिशूल, चुमुर, कोरजोख और तेगाजोंग बहुत दुर्गम क्षेत्र है।

1654 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

एक तो वहां पर पिछले सत्तर सालों में डेवलपमेंट नहीं हुआ। दूसरा बॉर्डर पर तनाव की स्थिति रहने के कारण वहां के पैरेंट्स टेंशन में रहते हैं तो बच्चे का अपब्रिंगिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं कि देश के अलग-अलग सैनिक स्कूलों में बॉर्डर के इन रेज़िडेंट्स के बच्चों को विशेष रूप से रिलैक्सेशन या प्रायोरिटी दे कर देश की मेन स्ट्रीम के साथ अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेने का प्रावधान हो।

मैं आपके माध्यम सैकेंड सप्लिमेंट्री क्वेश्चन में जानना चाहता हूँ कि अभी माननीय मंत्री जी ने गुडविल स्कूल्स के नाम लिए हैं, इन स्कूलों में टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन टीचर के क्वालिफिकेशन और एक्सपीरिएंस पर निर्भर होता है।

(1655/RV/PS)

टीचर्स को रिक्रूट करने के लिए जो बोर्ड-ऑफ-ऑफिसर्स होता है, क्या उसमें केवल आर्मी ऑफिसर्स ही होते हैं? क्या उसमें एडुकेशनिस्ट्स को या स्टेट गवर्नमेंट के एडुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से या लोकल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स का भी उसमें 'से' है? यदि नहीं है तो भविष्य में उनका भी 'से' रखने के बारे में क्या आप सोच रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदय, टीचर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेन्ट होता है और जब हम सैनिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल या आर्मी गुडविल स्कूल की बात करते हैं तो उसमें टीचर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो बच्चे सैनिक स्कूल या आर्मी स्कूल से पास-आउट होते हैं, उनका एक कैरेक्टर होता है, उनकी एक पहचान होती है। इसके साथ-साथ उनसे बहुत अपेक्षा भी होती है कि आर्मी स्कूल से आए हैं तो वे डिसीप्लीन्ड होंगे। इसके लिए जो टीचर्स रिक्रूटमेंट है, उस पर खास ध्यान दिया गया है। टीचर्स रिक्रूटमेंट में जो वैल्यू एडुकेशन है, और ग्लोबल आउटलुक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि inter-disciplinary approach, identified teachers of approved Sainik Schools, ये सारा कुछ होता है और इसके अलावा जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा, ताकि सैनिक स्कूल्स, आर्मी गुडविल स्कूल्स, आर्मी पब्लिक स्कूल्स वगैरह में जितने भी टीचर्स हों, वे टॉप क्लास के टीचर्स हों।

(इति)

(प्रश्न 46)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सर, यूनानीपैथी का इस देश में एक हिस्टोरिकल महत्व है। जब ब्रिटिश हमारे मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे तो वर्ष 1910 में उन्होंने इसे अन-साइंटिफिक कह कर इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हकीम अज़मल खाँ साहब ने मूवमेंट चलाया और वर्ष 1913 में दिल्ली के अन्दर ही तिबिया कॉलेज की बुनियाद रखी गयी, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। पिछले दिनों जो कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन्स बनाया गया, इस देश के अन्दर यूनानी के करीब 52 अन्डर-ग्रेजुएट कॉलेजेज हैं, और 15 पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेजेज हैं। उसमें यूनानी, सिद्धा और सोया-रिग्पा पैथी को इकट्ठा करके एक बोर्ड बनाया गया है। आयुर्वेद का एक अलग बोर्ड है। यह जो बोर्ड बनाया गया है, उसे भी सिद्धापैथी के लोग हेड कर रहे हैं, जिसके सिर्फ 12 कॉलेजेज हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अलग से यूनानी का बोर्ड बनाएंगे? आयुर्वेद में सर्जरी की परमिशन दी गयी है। पहले, यूनानी में भी यह परमिशन दी गयी थी, लेकिन शायद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके लिए कोर्ट में गया है। अगर यह वहां से वैकेट होता है तो आयुर्वेद के साथ-साथ क्या माननीय मंत्री जी यूनानी के पोस्ट ग्रेजुएट्स को सर्जरी का मौका देंगे?

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय सांसद कुंवर दानिश अली जी ने जो सवाल इस सदन में लाए हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

आयुष के बारे में आप सबको मालूम है कि पिछले सात सालों के अन्दर आयुष ने जो तरक्की की है, जो सफलता प्राप्त की है, सिर्फ इस देश के अन्दर नहीं, बल्कि सारी दुनिया में जो सफलता प्राप्त की है, इसके पीछे हमारे परम आदरणीय प्रधान मंत्री, देश के आदर्शवादी नेता नरेन्द्र मोदी जी हैं। मोदी जी द्वारा दी गई शक्ति, साहस और उनके निष्ठावान कदम के जरिए आज आयुष ने दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। The WHO has announced that it will set up a Global Centre for Traditional Medicine in India. This will be the one and only centre in the world.

(1700/SMN/MY)

So, that is the reason for recognising and considering the strength of Ayurveda, Unani, Sowa-Rigpa, Siddha, Homoeopathy, Yoga and Naturopathy. इसलिए, हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। सर्जरी के बारे में आपका जो सवाल है, इस सिलसिले में कदम उठाया गया था। यह विषय अभी सबजूडिस है, यह आपको भी मालूम है। विशेष रूप से हमें यह विषय हमेशा मन में रखना जरूरी है। हम सबको मिलकर ही हिन्दुस्तान की शक्ति को पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए काम करना होगा। आज डब्ल्यू.एच.ओ. ने जो निर्णय लिया है, यह निर्णय ऐसे ही नहीं लिया है, बल्कि इसके लिए रिसर्च और अध्ययन हुआ है। उन्होंने सारी दुनिया के आँकड़ों का अध्ययन किया।

(pp. 22 – 30)

पिछले दिनों हमारे आयुष क्षेत्र से जुड़े हुए अलग-अलग जो महापुरुष हैं, जो योग गुरू हैं, जो हीलर्स हैं, जो प्रैक्टिशर्न्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो रिसचर्स हैं, इन सभी देशवासियों के मेहनत का यह फल है। सारे विषय को आगे बढ़ाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा नेतृत्व दिया, उसकी वजह से आज योग को पूरी दुनिया ने अपना लिया है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक इसको स्वीकार किया है। मैं अपने आदरणीय सांसद जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इस विषय पर विश्वास रखिए, किसी को भी अलग नजरिए से नहीं देखा जाएगा।

आज मैं आपकी जानकारी के लिए विशेष रूप से यह आँकड़ा देना चाहता हूँ। आज हमारे युनानी के 22 इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अलग-अलग प्रांतों में काम कर रहे हैं। तीन कोर लोकेशन सेन्टर्स हैं। इसके साथ ही डॉ. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और One extension centre हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप घड़ी पर भी देख लिया कीजिए। बारह बजे प्रश्न काल समाप्त हो जाता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप उनका पूरा जवाब सुनिए। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो जवाब भी सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जैसे आप हर्षवर्धन जी को सुनते थे, वैसे ही आप इनका भी सुनिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप पूरा उत्तर दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: हमारे नए-नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने इजाजत दी है, इसलिए आप बोलें। आप उधर क्यों देखते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपके पैर में चोट है, इसलिए आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहूँगा कि आज हमारे सेटेलाइट इंस्टीट्यूट्स भी बन रहे हैं। इसके साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर कलैबरेटिव रिसर्च भी चल रहा है। आज यूनानी ने काफी तरक्की की है। Unani is an integral part of the AYUSH family.

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि आप सब आने वाले दिनों में इस विषय को और बढ़ावा देने के लिए सहयोग करें।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

RE: ATTACK BY ASSAILANTS AT A TOLL GATE IN UTTAR PRADESH

1704 hours

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रिया कि कल शाम आपने फोन करके मेरी खैरियत और मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या हुआ। आपने मुझे बताया कि आपने पुलिस के आला ओहदेदारों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रूक्न पार्लियामान के जान पर टोल गेट के पास जो कातिलाना हमला किया गया, उसके बारे में आपने बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

स्पीकर सर, मैं मुख्तसर से यहाँ पर यह बात कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ़ प्रदेश में इक्तिदार पर है। यह बात मैं आप तमाम को गोश गुज़ार कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं, जो गाोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते हैं।

(1705/CP/SNB)

आखिर ये कौन लोग हैं, जो इतना रैडिकलाइज़ हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर ऐतमाद नहीं रहा? ये अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं। जो इतनी नफरत करते हैं, आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इस पर सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, यह सबके लिए छोड़ रहा हूं।

मैं दो मर्तबा का विधायक हूं और चार मर्तबा का सांसद हूं। इस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। आखिर ये नौजवान कैसे रैडिकलाइज़ हुए? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ये सैय्यद कुतुब की किताब पढ़कर रैडिकलाइज़ हुए, अब्दुल्ला अजान की किताब पढ़कर रैडिकलाइज़ हुए या ऐमन अल जौहरी की किताब पढ़कर रैडिकलाइज़ हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि जो इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एमएचए में है, उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक सेल बनाइए। ये रैडिकलाइज़ हो चुके हैं, तो भारत में इससे राइट विंग, कम्युनलिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा।

मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए-1 ने की थी, आप वही करने जा रहे हैं। आपको इससे नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा। देश की सालमियत को खतरा पैदा हो रहा है। मैं आपके जरिए सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यह रैडिकलाइज़ेशन किया है, आप इस पर गौर करिए। आप इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते हैं? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की ताईद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा। मैं इसे सरकार पर छोड़ता हूं।

सर, चौथी बात यह है कि रैडिकलाइज़ेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर कांग्रेस के एक बड़े नेता से सुना कि दौलत के ऐतबार से दो भारत हैं। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है। भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है। भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, दो भारत हैं। एक भारत मोहब्बत पर, जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और दूसरा भारत नफरत पर बन रहा है। क्या आप दौलत के भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत के भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत के भारत की मिसाल देंगे, तो उसमें आपको मेरी ज़ुबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस दो भारत को समझने की जरूरत है।

सर, मुझे खत्म करने दीजिए। आप मेरी बात सुनिए। मैंने करीब से, 6 फीट से गोलियां देखीं। मुझे बोलने दीजिए। हो सकता है कि कल का दिन मैं न देखूं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा, तो कहां बोलूंगा? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहूंगा कि आप देखिए कि हरिद्वार, रायपुर और प्रयागराज में मेरे बारे में क्या-क्या कहा गया? इस पर आईबी की रिपोर्ट है। आप क्यों उसको छिपा रहे हैं? देखिए, मैं मौत से डरने वाला नहीं हूं। हम सबको इस दुनिया से जाना है। मैंने यह कह दिया कि मैं इस वतन में मेरी मां की कोख से पैदा हुआ, तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आँख बंद हो जाएगी तो इंशाअल्लाह औरंगाबाद की जमीन में मुझे दफनाया जाएगा। मैं आपसे, सरकार से अपील करना चाह रहा हूं कि जो बातें कही गई हैं, उन्हें देखिए। मुझे जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे हरगिज नहीं चाहिए।

मैं वर्ष 1994 से पॉलिटिक्स में हूँ। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं इस दुनिया में घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता हूं। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठानी है। मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी की भी हो, उनके खिलाफ बोलना है। अगर गोली लगती है तो मुझे कुबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगी, तो मुझे मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष : आपकी चिंता हमें है, इसलिए आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान अखलाक, पीलू से बढ़कर नहीं है। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिये सरकार से अपील करना चाहूंगा कि इस नफरत को खत्म करिए। इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहता हूं। आप मुझे 'ए' कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो।

जब देश के प्रधान मंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजीशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेक्युलर पार्टियों के लोगों ने कहा कि ओवैसी, तुम क्यों बोले? मैंने कहा, नहीं देश का प्रधान मंत्री मेरा है। सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। चार मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से चार-चार गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डरकर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरा मन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह।

(1710/NK/RU)

उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों को जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, कमजोरों को दबाने वाले को जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे जेड कैटेगरी सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, आप इंसाफ कीजिए। उस पर यूएपीए लगाइए, इनके दिमाग कौन हैं, दो लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम था कि मेरठ की तरफ से उस टोल गेट पर आ रहा हूं, छह फीट के फासले से गोली चलाते हैं, यह सरकार के हवाले है। आप इंसाफ करना चाहें तो इंसाफ कर सकते हैं। मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा।

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم اسپیکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ کل شام آپنے فون کرکے میری خیریت دریافت کی کہ کیا ہوا۔ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے پولس کے اعلیٰ عہدہ داروں سے بات چیت بھی کی۔ میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری کو ایک رکن پارلیمان کی جان پر ٹول گیٹ پر جو

قاتلانہ حملہ کیا گیا آپ نے اس کے بارے میں بات کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

محترم اسپیکر صاحب، میں مختصر میں یہاں پر بات کہنا چاہوں گا کہ مختلف سیاسی پارٹیاں، مختلف پردیش میں اقتدار پر ہیں۔ یہ بات میں آپ تمام کو گوشِ گزار کر رہا ہوں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، جو گولی پر بھروسہ کرتے ہیں بیلیٹ پر نہیں کرتے ہیں، آخر یہ کون ہوگ ہیں؟ جو اتنا ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ ان کو اس آئین پر اعتماد نہیں رہا؟ یہ امبیڈ کر کے بنائے ہوئے آئین کے خلاف ہیں۔ جو اتنی نفرت کرتے ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ میں اس پر سیاسی گفتگوں نہیں کروں گا، یہ سب کے لئے چھوڑ رہا ہوں۔

میں دو مرتبہ کا وِدھایک ہوں اور چار مرتبہ کا سانسد ہوں۔ اس طرح سے سیاست آگے بڑھ رہی ہے کہ ٹول گیٹ پر گاڑی رُکتی ہےاور 4 راونڈ گولیاں چلائی جاتی ہے۔ آخر یہ نوجوان کیسے ریڈیکلائز ہوئے؟ میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سید قطب کی کتاب پڑھ کر ریڈیکلائز، عبد اللہ اذان کی کتاب پڑھ کر ریڈیکلائزہوئے یا ایمن الظواہری کی کتاب پڑھ کر ریڈیکلائز ہوئے؟ اس لئے میں نے سرکار سے 2015 میں کہا تھا کہ جو انٹرنل سیکیوریٹی ڈیپارٹمنٹ ایم۔ایچ۔اے۔ میں ہے اس میں تمام مذاہب کے لوگوں کا ایک سیل بنائیے۔ یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، تو بھارت میں اس سے رائٹ وِنگ، کمیونلزم اور ٹیررزم بڑھے گا۔

میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو غلطی این۔ڈی۔اے۔1 نے کی تھی ، آپ وہی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو اس سے نقصان ہوگا۔ آپ کی سرکار کو نقصان ہوگا۔ ملک کی سالمیت کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ میں آپ کے ذریعہ سرکار سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ ریڈیکلائزیشن کیا ہے ، آپ اس پر غور کیجیئے۔ آپ ان پر یو۔اے۔پی۔اے۔ کیوں نہیں لگاتےہیں؟ اگر کوئی اسپیچ دیتا ہے، اگر کوئی فیس بوک پر کسی کرکٹ میچ پر کسی ٹیم کی تائید کرتا ہے تو یو۔اے۔پی۔اے۔ لگتا ہے۔ ایک سِٹنگ ایم۔پی۔ کے اوپر یو۔اے۔پی۔اے۔ نہیں لگے گا۔ میں اسے سرکار پر چھوڑتا ہوں۔

سر چوتھی بات یہ ہے کہ ریڈیکلائزیشن کی جب بات ہوتی ہے، ہم نے یہاں پر کانگریس کے ایک بڑے نیتا سے سُنا کہ دولت کے اعتبار سے دو بھارت ہیں۔ نہیں سر، بھارت کی دولت محبت ہے۔ بھارت کی دولت پیسوں کی دولت نہیں ہے۔ بھارت کی دولت محبت ہے۔ ہاں، دو بھارت ہے۔ ایک بھارت محبت پر جو پچھلے کئی سالوں سے آباد ہے اور دوسرا بھارت نفرت پر بن رہا ہے۔ کیا آپ دولت کے بھارت کی مثال دیں گے یا محبت کے بھارت کی مثال دیں گے؟ اگر محبت کے بھارت کی مثال دیں گے تو اس میں آپ کو میری زبان کو روکنے کے لئے گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دو بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

سر، مجھے ختم کرنے دیجیئے۔ آپ میری بات سنئیے۔ میں نے قریب سے 6 فیٹ سے گولیاں دیکھیں۔ مجھے بولنے دیجیئے۔ ہو سکتا ہے کل کا دن میں نہ دیکھوں؟ اگر میں یہاں نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا؟ آپ مجھے پلیز بولنے دیجیئے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھئےکہ ہری دوار، رائےپور اور پریاگراج میں میرے بارے میں کیا کیا کہا گیا؟ اس پر آئی۔بی۔ کی رپورٹ ہے۔ آپ کیوں اس کو چھپا رہے ہیں؟ دیکھئے میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ہم سب کو اس دنیا سے جانا

ہے۔ میں نے یہ کہہ دیا ہے میں اس وطن میں میری ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا تو زمین پر لٹایا گیا۔ جب میری آنکھ بند ہو جائے گی تو انشا اللہ حیدرآباد کی زمین میں مجھے دفنایا جائے گا۔ میں آپ سے سرکار سے یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو باتیں کہی گئیں ہیں، انہیں دیکھئے۔ مجھے زیڈ کیٹیگری سیکیوریٹی نہیں چاہئیے۔ مجھے ہر گز نہیں چاہئیے۔

میں سال 1994 سے سیاست میں ہوں۔ میں آزاد زندگی گزارنا چاہتاہوں۔ میں اس دنیا میں گھُٹن کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ مجھے زندہ رہنا ہے تو اپنی آواز اُٹھانی ہے۔ مجھے زندہ رہنا ہے تو سرکار کسی کی بھی ہو، ان کے خلاف بولنا ہے۔ اگر گولی لگتی ہے تو مجھے قبول ہے، مگر میں گھُٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آئین میں اگر ملک کے غریبوں کو مظلوموں کو اقلیتی سماج کو سیکیوریٹی ملے گی تو مجھے ملے گی۔

نہیں سر، ملک کے غریب بچیں گے تو میں بچوں گا۔ اوویسی کی جان اخلاق، پیلو سے برھ کر نہیں ہے، اوویسی کی جان اس وقت بچے گی جب غریب کی جان بچے گے۔ اس لئے میں آپ کے ذریعہ سرکار سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس نفرت کو ختم کیجیئے اور اس پر غور کرئیے۔ میں سیکیوریٹی نہیں لوں گا۔ میں زیڈ کیٹیگری سیکیوریٹی نہیں چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اے کیٹیگری کا شہری بنائیے تاکہ میری اور آپ کی زندگی برابر ہو۔

جب ملک کے وزیرِ اعظم پر سیکیوریٹی بریچ ہوا، اپوزیشن کی طرف سے میں نے کہا تھا کہ غلط ہوا۔ سب سیکولر پارٹیوں کے لوگوں نے کہا کہ اوویسی تم کیوں بولے؟ نہیں ملک کا وزیرِ اعظم میرا ہے۔ سیکیوریٹی بریچ ہوئی تو ایکشن لینا چاہئیے۔ چار مرتبہ کے ایم۔پی۔ پر کوئی 6 فیٹ کے فاصلے سے چار۔چار گولی چلاتا ہے۔ مجھے بھی موت آنی ہے، ہم سب کو موت آنی ہے۔ مگر میں ان گولی چلانے والوں سے ڈر کر خاموش نہیں بیٹھنے والا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اتر پردیش میں پرامن پولنگ ہوگی انشا اللہ۔

اتر پردیش کی عوام گولی چلانے والوں کوجواب بیلیٹ سے دیگی، نفرت کا جواب محبت سے دیگی، کمزوروں کو دبانے والوں کو جواب حصہ داری سے دیگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے زیڈ کیٹیگری سیکیوریٹی نہیں چاہئیے، میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں، آپ انصاف کیجیئے۔ اس پر یو۔اے۔پی۔اے۔ لگائیے، ان کے دماغ کون ہیں، دو لوگ ریکی کرتے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ میرٹھ کی طرف سے اس ٹول گیٹ پر آ رہا ہوں، 6 فیٹ کے فاصلے سے گولی چلاتے ہیں، یہ سرکار کے حوالے ہے۔ آپ انصاف کرنا چاہیں تو انصاف کر سکتے ہیں۔ مگر ریڈیکلائزیشن آپ کو نقصان پہنچائے گا اور اس سے رائٹ وِنگ ٹیررزم بڑھے گا۔

(ختم شد)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I endorse the feeling of Shri Owaisi. The incident which took place on the UP poll convoy of Shri Owaisi is highly condemnable and, at the same time, very sad also.

I also urge upon the Government to take swift action to find out the culprits and bring them before the law. We should not allow things to be in this way. Of course, there may be differences of opinion but it should not go to this extent.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): अध्यक्ष महोदय, यह पूरे सदन की भावना है कि हमारे मित्र, सांसद और अजीज़ दोस्त सही-सलामत वहां से निकल गए, इसके लिए हम भगवान का धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी लम्बी आयु हो, ये देश और समाज के काम में लंबे समय तक सेवाएं देते रहें।

राज्य सरकार ने इस पर तुरंत गहराई से कार्रवाई की, आरोपी पकड़े भी गए हैं, उनके व्हिकल को भी जब्त किया गया है, जो उन्होंने हथियार इस्तेमाल किया था वह भी पकड़ा गया है। इस विषय पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई चल रही है।

माननीय गृह मंत्री जी आज दिल्ली में नहीं है, वह सोमवार को इस विषय पर विस्तार से सदन को अवगत कराएंगे।

OBSERVATION RE: UPHOLDING THE DIGNITY OF CHAIR AND MAINTAINING DECORUM OF THE HOUSE

1713 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सदन के अंदर और सदन के बाहर अध्यक्ष पीठ पर की जाने वाली टिप्पणी इस सदन की मर्यादा के लिए उचित नहीं है। इस सदन की मर्यादा उच्च कोटि की है, जिसका सभी माननीय सदस्य सम्मान करते हैं। आसन का प्रयास रहता है कि सदन का जो भी सभापति रहे, वह निष्पक्ष रहे, वह निष्पक्षता से काम करता है, सदन को नियम-प्रक्रियाओं से संचालित करता है। अध्यक्ष पीठ पर बैठने वाला माननीय सदस्य या माननीय सदस्या को अध्यक्ष के रूप में निहित सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

मेरा आग्रह है कि आसन के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी न सदन के अंदर करनी चाहिए न सदन के बाहर करनी चाहिए, न माननीय सदस्यों को करनी चाहिए, न किसी अन्य व्यक्ति को सामान्य रूप से कभी भी सदन के बारे में या सदन के आसन के बारे में टिप्पणी न करना ही उचित रहेगा। यही हमारे संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा है।

मुझे आशा है कि आप सभी इस पर सहमत होंगे। मैंने पिछले दिनों घटी घटनाओं पर विशेष रूप से संज्ञान लिया है, इसे गंभीरता से लिया है। मैं माननीय सदस्यों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम सदन के बाहर आसन पीठ पर सोशल मीडिया और मीडिया में टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप सदन के सदस्य हैं, कभी आसन से आपकी कुछ तकरार हो सकती है, कुछ बातें हो सकती हैं, आप मुझे चेम्बर में आकर बता सकते हैं। वहां मैं आपकी बात सुनूंगा, यह चेम्बर भी आसन पीठ का ही एक हिस्सा है। मैं सभी माननीय सदस्यों का हमेशा सम्मान करता हूं, हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि उनको पर्याप्त समय और अवसर मिले।

(1715/SK/SM)

कभी मुझे लगता है कि किसी दल के नेता को आपत्ति होती है कि उन्हें समय कम मिलता है। यह सदन सबका है। मैं आबंटित समय से ज्यादा समय देता हूं और प्रयास करता हूं कि सबको बोलने का पर्याप्त अवसर मिले।

मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि आप देर रात तक ठिठुरती ठंड में संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए सदन में बैठते हैं। अगर आप उचित समझते हैं तो हमें एक मर्यादा बनानी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए।

मुझे एक माननीय सदस्य ने लिखकर दिया है कि जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो कोई माननीय सदस्य उनके सामने से गुजर जाते हैं और यह वीडियो क्लिपिंग में आ जाता है। हमारी प्रक्रिया में कुछ चीजें आपने, हमने और सबने तय की हैं ताकि सदन की मर्यादा बनी रहे। हमारे पूर्व अध्यक्षों और पूर्व माननीय सदस्यों ने इस आसन की गंभीरता और मर्यादा को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है, इसलिए हम विश्व में कह सकते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

कोई भी माननीय सदस्य हो, जब भी कोई घटना या बात होती है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से बात करता हूं। माननीय सदस्यों की मर्यादा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, मैं इसकी हमेशा कोशिश करता हूं।

मुझे आशा है कि आप सब इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करेंगे। क्या सदन सहमत है? यह उचित है या नहीं, आप क्या मानते हैं? आप बताएं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपके साथ हम सबके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपका हम सब सम्मान करते हैं। हमारी जो भी मांग या चाहत होती है, हम बिल्कुल खुलकर आपके सामने पेश करने में सक्षम होते हैं। हम आपके साथ बराबर सहयोग करेंगे।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I fully share your sentiment wholeheartedly. We are certainly of the opinion that the prestige of the House should always be kept at a level. We should all remain committed to the principles, ideas and philosophy of this House. The sanctum sanctorum of this House is something else than the other issues. This constitutional place is the chair of the hon. Speaker in the system of conducting the House. We should all remain committed to see that it is well established and can show a path to the whole of the world.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी व्यथा सुनकर थोड़ा सा हिल गया हूं। हम विधायक थे, हमने देखा है हम सदन में अपनी सीट पर बैठने से पहले आपके आसन को नमस्कार करके बैठते हैं। यह परंपरा है, प्रथा है। हम विधान परिषद् और विधान सभा में भी नमस्ते करके बैठते हैं। अगर उठते हैं तो भी नमस्ते करके बाहर जाते हैं। इस तरह से सदन में आते और जाते समय करते थे। यह संस्कार महाराष्ट्र में आज भी है।

हां, ऐसा होता है कि हर चीज हमारे मन की नहीं हो सकती है। वहां बैठने के बाद कुछ चीजें पता चलती हैं जैसे समय की पाबंदी होती है, कभी बोलना पड़ता है और कभी चुप भी रहना पड़ता है। चेयर के लिए आदर की भावना है, इसे हम न्यायालय की नज़र से देखते हैं। वहां बैठने वाले व्यक्ति को, उस आसन को आदर की भावना से देखना बहुत महत्वपूर्ण है।

मुझे लगता है कि आगे चलकर कहीं ऐसा हादसा हुआ है तो गलत है, जिस कारण आपको ठेस पहुंची और आपको सूचित करना पड़ा। मैं खुद भी देखता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य आते -जाते रहते हैं। जैसे कोई बात कर रहा है, अगर मैं बीच में से जाता हूं तो कैमरे में मेरा ही सिर आता है। मुझे सोचना चाहिए कि दूसरी जगह से जाएं या किसी को क्रॉस न करें। मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। आजकल क्लिपिंग देते हैं तो बीच में जाने वाले का सिर आ जाता है, जो कि ठीक नहीं लगता है।

आपने आज जो व्यथा और चिंता जताई है, मैं सोचता हूं व्यथा नहीं चिंता जताई है। हम सबको देखना चाहिए कि गरिमा बनी रहे। जब हम अपने सदन की गरिमा रखेंगे, चेयर की गरिमा रखेंगे, उसका आदर करेंगे तो ही लोग हमारा आदर करेंगे। अगर हम आपका आदर नहीं करेंगे तो हमारा आदर कौन करने वाला है?

मैं आपकी चिंता से सहमत हूं। आगे चलकर सभी लोग नियमों का पालन करें, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं।

(1720/MK/KSP)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Mr. Speaker, Sir, I fully endorse the concerns expressed by the Chair. We have high regards for the Chair. The office of the Speaker in our country has been placed in an exalted position. Any inconvenience caused to the Chair by hon. Members is not at all acceptable. As you put it, if at all we have any difference, it can be settled; your heart is always open; you invite us for negotiations; we often come to your chamber and issues are being settled. We feel sorry if any Member has passed any comments on the Chair. On behalf of our party, we assure that we would cooperate with you to uphold the dignity of the House.

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): स्पीकर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस हाउस की इज्जत हैं और उस इज्जत को बरकरार रखना हम सभी मेम्बर्स की जिम्मेवारी है। You are the Master of the House and I want to repeat something which a Speaker of the British Parliament, which is the mother of democracy said. When the Prime Minister rose up and spoke some things, he said directly to the Prime Minister, 'I am the Master; while I am the Speaker, I am the Master of the House'.

Sir, you are the Master of the House. We look to you as the Father of this House and we assure you, Sir, we will always respect you, we will always respect the Chair. अगर, कोई भी गलती हमसे हो गई है, तो उसको माफ कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपकी और इस कुर्सी की इज्जत करते रहेंगे। क्योंकि, हम लोगों की तभी इज्जत है, जब आपकी इज्जत है। इसलिए, मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात की तरफ से आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम हर समय आपकी और इस कुर्सी की इज्जत रखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अध्यक्ष जी, आसन की गरिमा और पीठ की मर्यादाओं को हमेशा ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे सभी सदस्यों को हमेशा निर्देशित किया है कि कहीं से भी पीठ और आसन के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी या ऐसा बर्ताव न हो, जिससे आसन के मान-सम्मान में कोई कमी आए। हमारा निरन्तर यही प्रयास रहता है। चाहे कभी वेल में जाने की बात हो या सदन की जितनी भी मर्यादाएं हैं, जितने भी रूल्स हैं, उनको पालन करने की बात हो, तो बहुजन समाज पार्टी निरन्तर उन सभी आदेशों का पालन करती रही है, जो हमें पीठ से दिया जाता है। आपको जो ठेस पहुंची है, उससे पूरे सदन को पीड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी कल इस परिसर में हुआ, जिससे आपको ठेस पहुंची है, वह आइंदा यहां कभी नहीं दोहराया जाएगा। मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि पूर्व की तरह हम लोग निरंतर इस सदन की और आसन की गरिमा को बनाए रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदय, आपने जो बातें सीधे हाउस के सामने रखी हैं, उनका पूरा पालन करते हुए कहना चाहता हूं कि आपने सत्रहवीं लोक सभा में सबको एकोमोडेट करके अपने बच्चे जैसा रखा है। अभी सीनियर माननीय सदस्य ने बताया है कि आप टीचर हैं तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं, आप फादर हैं तो हम लोग सन हैं। इस चेयर को हम लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। अभी तक दिया है और आने वाले समय में भी देंगे। कल जो कुछ भी हुआ, उसको हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया था । जो कुछ अन्दर हुआ, इनसाइड में हम लोगों ने एवं कुछ अन्य मेम्बर्स ने जानने की कोशिश की। बाहर के बारे में हमें पता है। आगे इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपनी वैल्यू कम नहीं करनी चाहिए। देश की 130 करोड़ जनता ने चुनकर हाउस में 543 मेम्बर्स को भेजा है। हरेक मेम्बर्स को 15 से 20 लाख लोगों ने अपना वोट देकर इधर भेजा है। इधर हम लोग कुछ भी इस तरह से करेंगे तो देश में भी उसकी एक्सेप्टिबिलिटी नहीं है। जो कुछ भी हुआ, आगे से हम लोग आपकी बात को ध्यान में रखते हुए आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।

(1725/KKD/SJN)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, today, we stand here with a lot of pain and distress about what happened yesterday in Parliament. It is a very unfortunate incident. I think, rules are made to be followed, and the rules are equal for every Member here. It is a tradition. I myself have been a Member for over a decade, and we have, fortunately not seen such kinds of extreme behaviour earlier.

I, on behalf of all of our colleagues, would say that we are really saddened about what happened yesterday. We commit to a good behaviour. We are the role models. When people look up to us as MPs, we represent over 20 lakh people, as a voice of 20 lakh people. So, what had happened is very unfortunate. I think, we all need to introspect; and all of us in all our party meetings, shall discuss this issue and make sure that no such unruly behaviour ever happens from any of us towards any Member, towards each other, of course, not the Chair.

Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I stand here with full anguish. I was a witness to a number of incidents and also that of yesterday. Unfortunate incidents do happen, and responsible Members of this House and responsible political parties of this House do express their anguish. But the manner in which you have stated it before us today, is something, which has forced us to ponder.

Rules are there; regulations are there; and whenever a Member gets elected to this House, the first day when he registers himself by showing his elected paper which he gets from the District Magistrate of his District, is provided with all the books, rules and regulations about what is to be followed. Subsequently, he is also taught. About two days' time is given where etiquettes are also told to him. But the best thing is, we observe others inside the House how the Members behave; and it is by observation that we learn many things. Very few Members actually read the rules and regulations. But it is only by observation that we conduct ourselves, and we always try to behave in a proper manner so that it becomes an example for others outside the House.

But the manner in which -- with the new technology like social media that is there -- in our anxiety to express ourselves, our anger, at times put us in difficulty; and that has happened yesterday.

I have marked many a time that not only some Members cross the floor but they also turn their back to the Chair and also gossip when some hon. Member is speaking in his turn inside the House. Is it necessary that one has to go and tell him or her that this is not the way to behave inside the House? These are certain etiquettes that we learn from how others are behaving. But that is not happening here.

Therefore, it was a very sad day yesterday. But it is good that most of us are opening up our mind here, and I believe that this will be a lesson for everyone including me to understand why that has happened the other day, and we have to correct ourselves.

Thank you, Sir.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I would like to echo the sentiments and the feelings that all of my colleagues have expressed today.

On behalf of the Telugu Desam Party, hearing you speak today, we are very sorry that you had to feel that way and express yourself in this manner.

I assure you that from our party's side, we will maintain our composure and we will follow all the rules, and give the utmost respect to you, Sir.

Earlier, in the previous term, Shrimati Sumitra Mahajan was the mother of this House; and as Mr. Farooq Abdullah rightly mentioned, you are the father of the House. We will provide all that respect to you, Sir.

Thank you.

(1730/RP/YSH)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I also, on behalf of my party and on my own behalf, fully endorse the views expressed by the hon. Speaker.

Sir, I am also a witness to yesterday's proceedings. I would like to appreciate the magnanimity which you have shown. The way in which you have presented the matter before the House even without mentioning the name, we have to appreciate you for that. We were all present yesterday. It is quite unfortunate. We all know that we all are being governed by the rules and regulations. It is not only the rules, regulations and directions but also the conventions and precedents of this House, from the days of Mavalankar and all these seven decades of our experience, that has built-up this House, the decorum and etiquettes of the House. The seriousness of this House is because of the precedents and conventions. Questioning the authority of the Chair can never be allowed. It is quite unfair. We may be having differences of opinion on the allocation of time. It is not an easy task. By having 543 number of Members present in this House, such a big House, with so many political parties and so many diversities, conducting the proceedings from the Chair is not an easy task. I can very well say this with my limited experience. Definitely, when conducting such a proceeding, we have to cooperate with the Chair. Whatever happened yesterday was quite unfortunate. The entire House is endorsing the views and the anguish expressed by the hon. Speaker. Definitely, we will try our level best to conduct the proceedings in the best way possible so as to maintain the decorum of this House.

Thank you very much, Sir.

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सत्र में पहली बार आपको इतना व्यथित देख रहा हूँ। निश्चित रूप से आपकी वेदना का पूरा असर पूरे सदन पर है। सभी दल के नेताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं और मुझे लगता है कि सभी आपकी भावनाओं के साथ हैं। भारत बड़ा लोकतंत्र हैं और संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। लोक सभा की कार्यवाही संचालन में आसन्दी का महत्व है। सदन के लिए नियम-प्रकिया है। उनके अंतर्गत ही आसन्दी काम करती है और आसन्दी की हमेशा कोशिश रहती है कि वह निर्लिप्त रहे, निष्पक्ष रहे और उसी भूमिका से सभापति तालिका के जो सदस्य हैं, वे भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ही नहीं, बल्कि पूरा सदन इस बात के लिए आपकी हमेशा प्रशंसा करता है कि चाहे दल हो, चाहे दल के नेता हों, चाहे सामान्य सांसद हों, चाहे प्रश्न काल हो, चाहे शून्य काल हो या चाहे किसी बिल पर डिस्कशन हो, आपकी हमेशा यह कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक प्रतिनिधि बोलें, अपनी बात रखें, अपने क्षेत्र के विषय उठाएं और यह बात सभी पार्टियों के सांसद सेन्ट्रल हॉल में बोलते हुए दिखाई भी देते हैं। कल जो कुछ हुआ, वह निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। वह किसी को भी अच्छा नहीं लगा और उसके कारण आपके भी मन में वेदना है। मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा कि सभी सदस्यों को आपकी भावना का ख्याल रखना चाहिए। संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी निश्चित रूप से जो हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, उनका पालन होना चाहिए। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल के सदस्यों की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम सब आसन्दी के सम्मान के लिए जो आवश्यक होगा, उसे जरूर करेंगे।

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1734 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं – कुमारी राम्या हरिदास, श्री के. सुरेश जी, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी, श्री एम. के. राघवन जी, श्री मणिक्कम टैगोर जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी, एडवोकेट ए. एम. आरिफ़ जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है, लेकिन मैं समय-समय पर उनके विषयों को अर्थात मंगलवार को लेने का प्रयास करूंगा।

(1735/NKL/RPS)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1735 hours

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 2 से 9, श्री वी. मुरलीधरन जी।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Sarbananda Sonowal, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of AYUSH for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Giriraj Singh, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Panchayati Raj for the year 2022-2023.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Panchayati Raj for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Shripad Yesso Naik, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2020-2021.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2020-2021.

(2) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mumbai Port Trust, Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2020-2021.

(3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2020-2021.

(iii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2020-2021.

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Shipping Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Shipping Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963:-

(i) G.S.R.664(E) published in Gazette of India dated 27th September, 2021, approving the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) (Amendment) Regulations, 2021.

(ii) G.S.R.519(E) published in Gazette of India dated 30th July, 2021, approving the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion Amendment) Regulations, 2021.

(iii) G.S.R.511(E) published in Gazette of India dated 28th July, 2021, approving the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) (Amendment) Regulations, 2021.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Prof. S.P. Singh Baghel, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2020-2021.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the India Centre for Migration, New Delhi, for the years 2018-2019 and 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the India Centre for Migration, New Delhi, for the years 2018-2019 and 2019-2020.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of External Affairs for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Ajay Bhatt, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Electronic Limited, Bengaluru, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the Bharat Electronic Limited, Bengaluru, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the BEL Optronic Devices Limited, Pune, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the BEL Optronic Devices Limited, Pune, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Electronic Limited, Bengaluru, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Bharat Electronic Limited, Bengaluru, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the BEL Optronic Devices Limited, Pune, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the BEL Optronic Devices Limited, Pune, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (a) & (b) of (1) above.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 43 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007:-

(i) The Armed Forces Tribunal (Account Cadre Posts) Recruitment Rules, 2019 published in Notification No. S.R.O.11(E) in Gazette of India dated 12th June, 2019.

(ii) The Armed Forces Tribunal (Group-A posts) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. S.R.O.04(E) in Gazette of India dated 23rd April, 2018.

(iii) The Armed Forces Tribunal (Group-B Gazetted and non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. S.R.O.05(E) in Gazette of India dated 23rd April, 2018.

(iv) The Ministry of Defence, Armed Forces Tribunal, Group-C posts (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 2013

published in Notification No. S.R.O.2(E) in Gazette of India dated 10th June, 2013.

(4) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Bhagwant Khuba, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Fertilizer and Chemicals Travancore Limited, Kochi, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Fertilizer and Chemicals Travancore Limited, Kochi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Madras Fertilizer Limited, Chennai, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Madras Fertilizer Limited, Chennai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Mumbai, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Dr. Bharati Pravin Pawar, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the HLL Mother and Child Hospital Limited, Lucknow, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the HLL Mother and Child Hospital Limited, Lucknow, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the HLL Infra Tech Services Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the HLL Infra Tech Services Limited, Thiruvananthapuram, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Pernem, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Pernem, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi, for the year 2020-2021.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2020-2021.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2020-2021.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the New Delhi Tuberculosis Centre, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the New Delhi Tuberculosis Centre, New Delhi, for the year 2020-2021.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysuru, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Speech and Hearing, Mysuru, for the year 2020-2021.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, for the year 2019-2020.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, for the year 2019-2020, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, for the year 2019-2020.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, for the year 2019-2020, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, for the year 2019-2020.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, Raebareli, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, Raebareli, for the year 2019-2020.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(16) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 69 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021:-

(i) The National Commission for Allied and Healthcare Professions 1st (Removal of Difficulties) Order, 2021 published in Notification No. S.O.3115(E) in Gazette of India dated 3rd August, 2021.

(ii) The National Commission for Allied and Healthcare Professions Rules, 2021 (14 of 2021) published in Notification No. G.S.R.346(E) in Gazette of India dated 27th May, 2021, together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R.506(E) dated 26th July, 2021.

(17) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (16) above.

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2020-2021.

(19) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (18) above.

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur, for the year 2020-2021.

(21) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (20) above.

(22) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940:-

(i) The New Drugs and Clinical Trials (Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.14(E) in Gazette of India dated 13th January, 2022.

(ii) The Medical Devices (Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.19(E) in Gazette of India dated 18th January, 2022.

(iii) The Medical Devices (Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.918(E) in Gazette of India dated 31st December, 2021.

(iv) The Drugs (Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.20(E) in Gazette of India dated 18th January, 2022.

(v) The Drugs (2nd Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.30(E) in Gazette of India dated 20th January, 2022.

(vi) The New Drugs and Clinical Trials (2nd Amendment) Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.21(E) in Gazette of India dated 18th January, 2022.

(vii) The Drugs (6th Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.839(E) in Gazette of India dated 29th November, 2021.

(viii) The Drugs (7th Amendment) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.848(E) in Gazette of India dated 9th December, 2021.

(23) A copy of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Fifth Amendment Regulations, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. Stds/SC/A-1.34/N-1 in Gazette of India dated 15th November, 2021 under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006.

(24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

(25) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 58 of the National Medical Commission Act, 2019:-

(i) The National Medical Commission, Autonomous Boards (Manner of Appointment of Fourth Member and the Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements of President and

Members) Amendment Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.282(E) in Gazette of India dated 20th April, 2021.

(ii) The National Medical Commission, (Manner of Appointment and Nomination of Members, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Amendment Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.283(E) in Gazette of India dated 20th April, 2021.

(iii) S.O.2008(E) published in Gazette of India dated 24th May, 2021, regarding appointment of President, Medical Assessment and Rating Board and President, Ethics and Medical Rating Board.

(iv) S.O.2036(E) published in Gazette of India dated 28th May, 2021, regarding appointment of Secretary, National Medical Commission.

(26) A copy of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.345(E) in Gazette of India dated 25th May, 2021 under Section 34 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.

(27) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (26) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Dr. (Prof.) Mahendra Munjapara, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2020-2021.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2020-2021.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
10वां से 13वां प्रतिवेदन

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित चार प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी (सत्रहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का 10वां प्रतिवेदन।

(2) 'सेन्ट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी (सत्रहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का 11वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी (सत्रहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का 12वां प्रतिवेदन।

(4) 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी (सत्रहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का 13वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

श्री सुशील कुमार सिंह(औरंगाबाद): अध्यक्ष जी, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) 'वर्ष 2011-12 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन संख्या 3 के पैरा 2.5 पर आधारित मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्रा.) लिमिटेड द्वारा भारत सरकार की ओर से न्यासी क्षमता में धारित एस्क्रो खाते से अनाधिकृत निकासी' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 5वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) 'चुनिंदा सीपीएसयू में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(3) 'पावर ग्रिड कारपारेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन तथा पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्रिड प्रबंधन (वर्ष 2014 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 18 पर आधारित)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(4) 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(5) 'भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण (वर्ष 2015 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 12 पर आधारित)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'घाटे में चल रहे सीपीएसयू की समीक्षा' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 7वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

Statements

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to lay on the Table the Statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by Government on the Observations/Recommendations contained in the following Action Taken Reports of the Public Accounts Committee:-

(1) Fourth Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Project Management Practices in Gauge Conversion and New Line Projects'.

(2) Thirty-third Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Loss of Revenue due to Short Levy of Tax, Incorrect Classification of Excisable Goods and non-fulfillment of Export Obligation'.

(3) Sixty-second Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Special Economic Zones'.

(4) Sixty-third Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Non-Lapsable Central Pool of Resource (NLCPR) Scheme'.

(5) Seventy-fourth Action Taken Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Supply Chain Management of Rations in Indian Army'.

(6) Ninth Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Excesses Over Voted Grants and Charged Appropriations (2010-11)'.

(7) Seventy-ninth Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Adarsh Co-operative Housing Society, Mumbai'.

(8) Eighty-fourth Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Excesses Over Voted Grants and Charged Appropriations (2012-13)'. 6

(9) Eighty-sixth Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Performance Audit of Dual Freight Policy for Transportation of Iron Ore Traffic in Indian Railways'.

(10) Ninety-ninth Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Sub-urban Train Services in Indian Railways'.

(11) One Hundredth Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Commercial Publicity in Indian Railways'.

(12) One Hundred and First Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Shared Mobile Infrastructure Scheme'.

(13) One Hundred and Seventh Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Unfruitful Expenditure on Establishment of Specific Pathogen Free Shrimp Seed Multiplication Centre – (NFDB)'.

(14) One Hundred and Sixteenth Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Excesses Over Voted Grants and Charged Appropriations (2013-14)'.

(15) One Hundred and Seventeenth Action Taken Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Excesses Over Voted Grants and Charged Appropriations (2014-15)'.

(16) One Hundred and Twenty Eighth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Implementation of Public Private Partnership-Indira Gandhi International Airport, Delhi'.

(17) Sixth Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Excesses Over Voted Grants and Charged Appropriations (2015-16)'.

(18) Eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Accounting of Projects in Indian Railways'. 7

(19) Nineteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Delay in Commissioning of CCTV Surveillance System, Irregular LTC Claims and Avoidable Expenditure on Hired Servers'.

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति

334वां प्रतिवेदन

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, 'महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों' के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के तीन सौ सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 334वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

BUSINESS OF THE HOUSE

1738 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, with your permission, I rise to announce that the Government Business during the week commencing Monday, the 7th of February, 2022 will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's order paper:- [*it contains* further discussion on the Motion of Thanks on the President's Address]
2. General Discussion on Union Budget 2022-23.

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON BIOLOGICAL DIVERSITY (AMENDMENT) BILL – EXTENSION OF TIME

SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): Sir, I beg to move the following motion:-

> "That this House do extend by one month from this date the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021. "

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को इस तारीख से एक माह के लिए बढ़ाती है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1739 बजे

माननीय अध्यक्ष : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल रखे जाने के लिए माननीय सदस्यों को अनुमति प्रदान की जाती है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे इसे सभा पटल पर रख दें और अगले वीक में मैं कोशिश करूंगा कि उनको पढ़ने का मौका दूं।

Re: Rejuvenation of Luni river in Rajasthan

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं आपका ध्यान मेरे पश्चिमी राजस्थान के संसदीय क्षेत्र पाली से होकर गुजरने वाली लूनी नदी की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह नदी पाली शहर सहित अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहती हुई गुजरात के कच्छ की खाड़ी में गिरती है। लूणी नदी की लंबाई लगभग 511 कि.मी. है। अधिकारियों द्वारा नदी के दोनों तरफ वनीकरण का निर्णय किया गया है ताकि मृदा और जल संरक्षण के जरिए भू जल संर्वधन और अन्य वानिकी कार्यो को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में लूणी नदी पर रिवर फ्रंट व इको पार्क बनाकर न केवल सौन्दर्यीकरण होगा साथ ही साथ इको डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रम भी होंगे।

महोदय , राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र पाली में लूनी नदी सिंचाई का स्रोत है | यह नदी पश्चिम राजस्थान वासियों के लिए जीवनदायी है जिसकी लोग पूजा भी करते है। लूणी नदी के क्षेत्र से हैंडीक्राफ्ट के लिए लकड़ी, जलाऊलकड़ी, चारा व अन्य वन उपज भी मिलेगी। वर्षों से बालोतरा व पाली की ओद्योगिक इकाईयों के प्रदूषण की मार झेल रही लूणी नदी का जीर्णोद्धार क्षेत्रवासियों की आजीविका में वृद्धि करने का एक माध्यम भी बनेगी |

मै माननीय मंत्री जी का धन्यवाद् ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होने देश की प्रमुख नदियों के जीर्णोधार हेतु अनेक आवश्यक कदम उठाए है | महोदय, केंद्र सरकार की ओर से गंगा की तर्ज पर देश की 13 प्रमुख नदियों के जीर्णोद्धार का कार्य भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) को दिया है। इसी तर्ज पर लूणी नदी के जीर्णोधार हेतु डीपीआर बनाकर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को भेजी गई है |

महोदय, आपके माध्यम से मेरा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से निवेदन है कि हमारी इस मरूगंगा के नाम से विख्यात “लूणी नदी “ के जीर्णोधार हेतु जल्द आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें |

(इति)

Re: Water conservation measures to replenish ground water in Dausa parliamentary constituency, Rajasthan

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा):मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा अधिकांश भाग डार्क जोन हैं I जल जीवन मिशन के लिए गहरे वोर किये जाने से आस पास कृषको के कुए सुख चुके हैं जिसके कारण किसानो में संघर्ष की स्थिति उत्पन हो रही हैं. एक तरफ अटल भू जल योजना २०२० से स्वीकृत हुईI इसका उदेशय भूमिगत जल का मूल्यांकन करने से किसानो में जागरूकता के साथ साथ आक्रोश पैदा हो रहा हेI डार्क जोन को पुनः जल सर्जन करने की आवशयकता हैं I

अतः आपसे अनुरोध हैं कि वर्षा जल संचय करने पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हैं I ईस्टर्न कैनाल योजना को मंजूर करना हमारी सरकार का लक्ष्य होना चाहिए तभी उक्त व्यवस्था सारगर्भित हो सकेगीI

(इति)

Re: Need to develop Chhokarwara to Bharatpur road in Rajasthan a four lane National highway

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय मै आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र भरतपुर की सड़क छोकरवाडा से धौलपुर तक वाया भुसावर, बयाना, बंदबारेटा, वाड़ी, बसेड़ी की सड़क की ओर आकर्षित करना चाहती हूंI

महोदय छोकरवाडा से बयाना होते हुए धौलपुर तक की इस सड़क की लम्बाई लगभग 105 किमी है। बयाना के बंसी पहाड़पुर में विश्व प्रसिद्ध लाल पत्थर की मण्डी है, यह लाल पत्थर पूरे देश की ऐतिहासिक इमारतो में लगा है एवं सौभाग्य से वर्तमान में भव्य राम मन्दिर के निर्माण में भी इस पत्थर का उपयोग हो रहा है। महोदय इस सड़क पर वाहनों का आवागमन बहुत ज्यादा है, जिससे इस सड़क की स्थिति बहुत खराब हो रही हैं तथा अनेक स्थानों पर इस सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण आम.जन को इस सड़क पर जाम के साथ साथ बड़ी दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है। महोदय, मेरा माननीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि यदि इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित कर चार लेन का बना दिया जाए तो व्यापारियों के साथ.साथ आम.जन को भी इससे काफी लाभ मिलेगा।

(इति)

Re: Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Amreli in Gujarat

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): अध्यक्ष महोदय ,आपको एक अति महत्वपूर्ण विषय से अवगत करवाना चाहता हूँ कि अमरेली में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को लेकर मैं पिछले कई वर्षों से प्रयत्नशील हूँ, मेरे अथाह प्रयास के फलस्वरूप केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को लेकर सभी औपचारिकतायें पूरी हो चुकी है परन्तु पहले Challenging Method Committee की बैठक नहीं होने के कारण अमरेली में केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुल पा रहा था जिसको मेरी जानकारी के अनुसार हाल में पूर्ण किया गया, फिर अब कुछ समय पूर्व यह बैठक पूर्ण हुई और उसके बाद भी अभी तक अमरेली में केंद्रीय विद्यालय को खोले जाने का अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। मेरे द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन से संपर्क किये जाने पर यह पता चला है की अभी वहां पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाने में कुछ और समय लगेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली की जनता केन्द्रीय विद्यालय को लेकर अति उत्साहित है, इसलिए क्षेत्र के निवासियों को केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र मिलना चाहिए जिससे कि अमरेली के बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकें। अतः मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करके अमरेली में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की औपचारिकतायें पूर्ण की जाये।

(इति)

Re: Need to establish a Government Degree College in Kaimur district, Bihar

श्री छेदी पासवान (सासाराम): विदित हो कि बिहार के कैमूर जिलान्तर्गत अधौरा प्रखण्ड का इलाका सामाजिक, आर्थिक, एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, जहॉं आदिवासीयों एवं कमजोर वर्ग के लोगो की बड़ी आबादी है, जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करते है। इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण उच्च शिक्षण में नामांकन का प्रतिशत काफी कम है, जिससे इस पिछड़े इलाके के छात्र/छात्राएं उच्च शिक्षा के अवसर से वंचित रह रहे हैं। इन्हे उच्च शिक्षा का अवसर सुलभ कराना राजधर्म की अपेक्षा है।

अतः विशेष आग्रह है कि बिहार के कैमूर जिलान्तर्गत प्रखण्ड अधौरा में सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने हेतु शीघ्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा यथोचित कारवाई करने की कृपा की जाए।

(इति)

Re: Conversion of tribal people to Christianity in the country

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आदिवासी-जनजाति क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूॅं, महोदय धर्मांतरण एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, आदिवासी-जनजातियों के प्राचीन गौरव, एकता और परम्परा को गिने चुने लोगों के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, मेरा क्षेत्र बॉसवाड़ा-डूॅंगरपुर, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, झारखण्ड आदि में आदिवासी लोगों की बड़ी आबादी को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने हेतु एक विशेष टीम सक्रिय है, इसे रोकना अनिर्वाय है। नही तो जो लोग धर्म परिवर्तिन कर ईसाई धर्म अपनाते है तो उन्हे आरक्षण आदि की सुविधाएं समाप्त कर देनी चाहिए और अल्पसंख्यक के नाम पर जो दोहरा लाभ ले रहे है उसे भी तत्काल समाप्त करने की आवश्यकता है। जो लोग आदिवासी-जनजाति को धर्मपरिर्वतन में लगे है उस पर तत्काल अंकुश लगाने हेतु मा0 गृह मंत्री जी से मॉग करता हूँ।

(इति)

Re: Need to establish a Central University in Maharashtra

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): The enactment of the Central Universities Act,2009 was done with the aim to establish and incorporate universities for teaching and research in various States. Currently, there are 16 Universities under this Act for different States but there is no university for the State of Maharashtra. The State of Maharashtra being one of the most developed States of India and also an educational hub has been devoid of a Central University. I, therefore, request the Government to establish a Central University in Maharashtra for encouraging multidisciplinary learning by promoting creative and critical thinking for holistic development. This shall be a right direction in achieving the goal to provide better opportunities of learning and research in higher education through a full-fledged university which will not only provide education but also aid in creatmg human capital. It will foster excellence in teaching, research and innovation in pure and applied areas of learning and generate direct and indirect employment.

(ends)

Re: Need to lower the age for administration of booster dose of Covid vaccine

श्री रामदास तडस (वर्धा): सदन के माध्यम से मा.स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह है कि कोरोना महामारी को जड़ से समाप्त करने हेतु टीकाकरण अभियान अभूतपूर्व सफलता हासिल कर रहा हैं, इसलिये मैं माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, सभी डॉक्टर, मेडिकल कर्मचारी, फ्रंट लाईन वर्कर्स का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सदन के माध्यम सें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कोरोना महामारी का फैलाव रोकने हेतु "बूस्टर डोज़" की लगाने की उम्र सीमा कम की जाय और दोनो टीका लेने वाले सभी को "बूस्टर डोज " जल्द लगवाने हेतु सरकार के माध्यम से निर्णय लेने की कृपा करे जिससे सभी लोगों को बूस्टर डोज़ लग सके |

(इति)

Re: Establishment of a Central University in lower Assam region

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): One cannot dispute the fact that higher education plays a significant role in the development of human resources and society in general. However, the progress of higher education has not been optimum in the country particularly in Assam. Higher education produces high level of professionals.

Assam has a literacy rate of about 73% as per 2011 census. According to Gross Enrolment Ratio of Higher Education (2021), Assam's rate is 17.3% and national rate is 27.1%. The huge gap is due to lack of basic amenities and state of the art educational infrastructure in Assam. As Swami Vivekananda said, "A nation is advanced in proportion to education and intelligence spread among the masses".

To shrink the gap of 9.8% GER, there is a need to enhance the infrastructure of higher education in the state. In this regard, I would like to mention that lower Assam region is devoid of any major educational institutions. Many move out of the state for higher education thereby causing huge brain drain.

Therefore, I urge upon the Hon'ble Minister of Education to consider establishment of a Central University in lower Assam region, especially in and around Barpeta. Doing so will create educational hub in the region.

(ends)

Re: Deputation of Cadre officers

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): The Department of Personnel & Training proposals to amend Rule 6 of IAS (Cadre) Rules-1954 related to deputation of cadre officers would undermine the Co-operative federalism and morale of the All India Service Officers. Many state governments and political parties have spoken out against the changes, opposing the proposal of the Centre. The amendments in the IAS Cadre rule will lead to the Central government having greater control in the central deputation of all three All India Services (IAS). The Centre will have the power to depute civil servants to Central ministries without taking any approval from the state governments. Proposed amendments will induce fear psychosis among All India Service Officers in implementing policies of those State governments where political dispensation is different from ruling party at Centre. Hence, the proposed Amendment may be dropped for upholding the Co-Operative Federalism of India and the morale of AIS officers.

(ends)

Re: Need to include Irular and Narikuravar communities in the list of Scheduled Tribes

SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI): The Irular and Narikuravar Communities are in the OBC list of Union Government of India. Actually they are depressed communities living under below poverty condition. They are not having any permanent income source. They are unable to get even elementary education. Very few people from the communities got school and college education. However, they are unable to get government jobs due to the lack of community certificate. The above said communities may be included in the Scheduled Tribes list for their upliftment.

(ends)

Re: Booster shots to bankers

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Our country currently has 12 public sector banks, 22 private sector banks, 44 foreign banks,56 regional rural banks,1485 urban cooperative banks & 96000 rural cooperative banks which employ more than 15 lakh employees. Since the beginning of the corona pandemic, the banking sector has been working continuously to sustain our economy and carrying out essential services. More than 2,000 bankers have lost their lives in the first two waves of the pandemic. The banks have served every section of the society in both urban and rural areas during these challenging times & have played a crucial role in ensuring that there is no disruption in our financial system. Unfortunately, the recognition of bank employees as Frontline Covid Warrior (FLW) was delayed, denying the opportunity of getting vaccinated along with other FLWs in the first instance, which could possibly have averted the loss of precious lives. In order to prevent any further casualty to the bank employees, I request the Government to consider bankers as the frontline workers for administering booster shots amid rising COVID-19 cases across the country & the onset of the third wave. In addition to this, special status should be given to bankers for availing public transport, including suburban railways under essential service category.

(ends)

Re: Alleged increasing incidents of attack on minorities

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): The spirit of Indian secularism is going to be in doldrums as the attack on the life and property of minorities are increasing day by day. News coming from various states are worrisome and government of India’s efforts to address it is the need of the hour. Government should convene an all party meeting to discuss this burning issue and evolve a programme of action.

(ends)

Re: Need to run MEMU trains on Sikar-Jaipur route and also provide stoppage of long distance trains at Sikar and Jaipur Railway stations

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान, मेरे संसदीय क्षेत्र के रेलवे से संबंधित विषयों की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र सीकर से हजारों मजदूर,व्यापारी और किसान सीकर एवं जयपुर के बीच सुबह. शाम नियमित यात्रा करते हैं। लेकिन सीकर-जयपुर के बीच सुबह- शाम कोई नियमित ट्रेन नहीं चलती है, जिससे उनको अधिक किराया देकर बसों में यात्रा करनी पड़ती है। इसके अलावा मेरे संसदीय क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़, पलसाना, गोविंदगढ़, श्रीमाधोपुर, गोविंदगढ़, और चौमू स्टेशनों पर लंबी दूरी की अनेक ट्रेनों का स्टॉपेज नही है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि सीकर-जयपुर के बीच सुबह.शाम मेमो ट्रेनें चलाई जाए तथा उपरोक्त स्टेशनों पर लंबी दूरी की ट्रेनों का स्टॉपेज करवाने की कृपा करें ताकि क्षेत्र के आम जन को रेलवे की सेवाओं का फायदा मिल सके।

(इति)

Re: Construction of roads and bridges under Road Connectivity Project for LWE affected Areas in Jamshedpur parliamentary constituency, Jharkhand

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला अति पिछड़ा एवं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित के साथ-साथ 115 आकांक्षी जिलों में शामिल हैं। विदित है कि पूर्वी सिंहभूम जिला उग्रवाद प्रभावित हैं एवं नक्सल गतिविधियों से आक्रांत रहने के चलते दुर्गम क्षेत्रों में अभी भी सड़कों का अभाव है। यह भी विदित है कि इन क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा के लिए एवं पुलिस बल की उन क्षेत्रों में उपस्थिति बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रो के लिए सड़क संपर्क योजना (RCPLWE) के तहत सड़कों एवं पुलों के निर्माण करने के लिए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य मामले के द्वारा चयनित सड़कों की सूची उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जिला के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार को प्रेषित की गई थी और उक्त सूची को ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजी है।

अतः अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध है कि जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रो के लिए सड़क संपर्क योजना, वामपंथी उग्रवाद (RCPLWE) के तहत सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु भेजी गई सूची को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

(इति)

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT’S ADDRESS – Contd.

माननीय अध्यक्ष : अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि सदन की गरिमा बनाए रखें और माननीय अधीर रंजन चौधरी जी, जो सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी बात को शालीनता के साथ सुनें।

माननीय अधीर रंजन चौधरी जी ।

1739 hours

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you, Sir.

Sir, since the Constitution came into force, in consonance with the traditional protocols of Indian Parliamentary democracy, each year, before the commencement of the Session, *Mahamahim Rashtrapatiji* used to deliver the Address to both the Houses of Parliament assembled together.

(1740/MMN/SPS)

So, it heralds the first Session of this new year, 2022. It is incumbent upon the President under Article 87 of our Constitution to address the Parliament and we all maintain it as a solemn occasion since the first President of our country, Dr. Rajendra Prasad Ji addressed the same on the 31st January, 1950.

Sir, the President has spelt out the programmes, the policies and the accomplishments of this Government in the previous years along with the impending policies and programmes so that we can have a bird’s eye view in regard to the Government’s programmes and policies. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, कांग्रेस दल के नेता भाषण दे रहे हैं। अब आप बोलिए।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, already, we have gone through the Address. It consists of 82 paragraphs. I will certainly try, without any qualm and compunction, to find out the objectives and intentions of this Government and also the lacunae, deficiencies and shortcomings which are also visible in this Address. That is why, I rise to dwell on the Presidential Address. Our hon. Prime Minister is also coming to attend this House. It is a great opportunity for all of us. Now the question is: how do you define the intent and objectives of this Government, which have been enshrined in this Address?

It has been stated that my Government is celebrating the sacred occasions of the 400th Prakash Parv of Guru Tegh Bahadur Ji, the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo, the 150th birth anniversary of V.O. Chidambaram Pillai and the 125th birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose with grandeur. From this year onwards, the Government has started the Republic Day celebrations from January 23, the birth anniversary of Netaji.

Now the question is: should we confine ourselves to the celebration of sacred occasions and anniversaries in memory of those grand souls? Or, should we inculcate the ideas preached by them and to imbibe the teachings of those great personalities to build the nation and to build the future of our country? That is the moot point so that we can have a real introspection and to peep into these core ideas of those great souls of our country, such as the 400th Prakash Parv of Guru Tegh Bahadur Ji who was depicted as a *hinde chadder*. "शीश दिया पर सि ना उचरी, धर्म हेतु साका जिन किया शीश दिया पर सिरर न दिया।" He is a *shaheed*, a *veer* who has sacrificed his life but not sacrificed his ideal. That is the motto of Guru Tegh Bahadur Ji's life.

(1745/VR/RAJ)

Are we emulating that that motto or not? He had defended Hinduism but never opposed the idea of Islamism or Muslims. We should not equate all the Muslims of our country with Aurangzeb as much as we should not equate all the Hindus of our country with Jaichand. Sometimes, we are confusing the mind of the common people by bogus depictions of the history. History is the remembrance of the past. We cannot hide the truth of our history even if we strive hard to distort it. That should be kept in mind.

I would like to quote Mr. V.O. Chidambaram Pillai. He said: "That quality relationships are built on principles especially the principle of trust." We should follow his idea. The great saint Rishi Aurobindo said and I quote: "All problems of the existence are the problems of harmony. Ever since the dawn of history, man has been actuated by the persistent dream of triple harmony – harmony within man, social harmony between man and man, and the harmony between the man and the world around him." Whether we are pursuing that idea of harmony or not, that needs to be considered.

According to Bhagwan Birsa Munda, "यदि हमें देश का वास्तविक विकास करना है, तो हमें सभी धर्म और जाति के लोगों को साथ लेकर चलना होगा।"

Swami Vivekananda taught us that each must assimilate the spirit of the others yet preserve his own individuality, and to grow according to his own law of growth. Communal harmony is the basic principle of peaceful existence of a country as diverse as India. Whether we are pursuing those great ideas or not, that needs to be considered.

Here, you are talking about Subhash Chandra Bose ji. Yes, we must appreciate it from the core of our heart. The entire country pays its regards, homage or tribute to the great soul of our country. He is the tragic hero of the world, whose date of birth is known but date of expiry is riddled with controversies. Yet we all celebrate his birth anniversary. He exhorted the people of our country that with the advent of the Mohammedans, a new synthesis had gradually worked out. Though they did not accept the religion of the Hindus, they made India their home and shared in the common social life of the people their joys and their sorrows through mutual cooperation. A new art, and a new culture was evolved. Whether heavens would have fallen upon us, if we follow the guidance given to us.

हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिन मनाते हैं, लेकिन जर्मनी से सिंगापुर तक, मतलब यूरोप से एशिया तक आने के लिए जिस पनडुब्बी का इस्तेमाल किया गया था, उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर जा सकती है। समुद्र के नीचे से 90 दिनों का वह सफर था। उनके साथी आबिद हसन थे।

(1750/VB/SAN)

क्या हम उनको कभी याद करते हैं? ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज़ खान और इंडियन नैशनल आर्मी के जाँबाज सिपाहियों ने 'दिल्ली चलो' के नारे से, हिन्दुस्तान की ओर आगे बढ़ते हुए, हिन्दुस्तान की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई थी। हमें उन सबको भी याद करना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें यह भी याद करना चाहिए कि नेता जी ने वर्ष 1942 के अपने रेडियो मैसेज में क्या कहा था? वर्ष 1942 में रेडियो एड्रेस में उन्होंने यह कहा था:

> "I would request Mr. Jinnah, Mr. Savarkar and all those leaders who still think of a compromise with the British to realise once for all that in the world of tomorrow, there will be no British Empire. All those individuals, groups or parties who now participate in the fight for freedom will have an honoured place in the India of tomorrow. The

supporters of British imperialism will natural become non-entities in a free India."

उस महान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को महात्मा गांधी जी 'Prince of the Patriot' कहते थे। उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा के समय यह कहा था:

'In the holy war of Independence, Bapuji, I am seeking yours blessings.'

यही हमारे हिन्दुस्तान का परिचय है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का सम्मान करते समय आप होलोग्राम जरूर लगाते हैं। लेकिन वह होलोग्राम अमर जवान ज्योति को हटाकर क्यों? अमर जवान ज्योति और वॉर मेमोरियल में पहले जो ज्योति जलाई जाती थी, उस समय यह तय हुआ था कि अगर दोनों ज्योतियाँ जलें, तो कोई हर्ज नहीं है। Simultaneously दो ज्योतियाँ जल सकती हैं। लेकिन उस समय पर नेताजी का होलोग्राम लगाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वे भी तो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे। वर्ष 1971 में जो लड़ाई हुई थी, जिसके कारण बांग्लादेश आजाद हुआ था और जिस लड़ाई के कारण पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई थी, उसका नाम सभी जानते हैं। वह दिवंगत आत्मा हैं- स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। आप चाहते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नामो निशान न रहे, इसके लिए उसको यहाँ से हटाया जाए।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह से आप किसी की छवि को धूमिल नहीं कर सकते हैं। किसी की छवि को मिटाना कभी संभव नहीं होगा और यह मानकर चलना सही होगा। अगर कागज में कोई नाम लिखा होता है, तो वह मिट जाता है, अगर पत्थर पर कोई नाम लिखा होता है, उसे भी मिटाया जा सकता है, लेकिन अगर दिल में कोई नाम रह जाता है, तो किसी के द्वारा उसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है।

इंदिरा जी हिन्दुस्तान के आम लोगों के दिल में बसी हुई एक महान नेत्री भी थीं और अभी भी हैं। हो सकता है, उनके खिलाफ कुछ आलोचनाएं जरूर हुई होंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनकी कर्मवीरता, उनका जो बलिदान हमारे देश के लिए है, उनको हम भूल जाएं। हम उनकी कुर्बानी को भूल जाएं, हम उनके परिवार की कुर्बानी को भूल जाएं, यह कभी नहीं हो सकता है।

आज हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कमजोर किसी ने किया, तो उनका नाम इंदिरा गांधी है। इतिहास तो यही बताता है। लगभग 93 हजार पाकिस्तानी फौजियों को बंदी बनाकर और शिमला एकॉर्ड करके पाकिस्तान को उन्होंने हिन्दुस्तान के सामने घुटने टेकने को मजबूर किया था। यह तो इतिहास है। लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं कि उनके नाम का जिक्र किया जाए। इसलिए चलो, उनको हटाया जाए, उनकी ज्योति को हटाया जाए।

इस समय आपको सीख देने के लिए नेताजी की पुत्री ने क्या कहा है?

(1755/PC/SNT)

नेता जी की पुत्री ने कहा है :–

> “My father dreamt of an India where all religions coexist peacefully. The statue should not be the only tribute to Netaji, we must also honour his values.”

यह कौन कहता है? Anita Bose Pfaff said hours after the announcement was made by Prime Minister, Modi Ji. मैं एक और बात यहां रखना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी को देखते हुए मुझे लगता है कि एक और बात प्रधान मंत्री जी के सामने रखनी चाहिए। वह यह है कि when Netaji was planning to liberate the Northeast of the country through INA, it was VD Savarkar who offered full military cooperation to the British masters. While addressing 23rd session of Hindu Mahasabha at Bhagalpur in the year 1941, he said:

> “The war which has now reached our shores directly constitutes at once a danger and an opportunity which both render it imperative that the militarization movement must be intensified and every branch of the Hindu Mahasabha in every town and village must actively engage itself in rousing the Hindu people to join the army, navy, the aerial forces and the different war-craft manufacturing.”

किस के लिए मदद की? ब्रिटिश के लिए। … (व्यवधान) यह सावरकर जी के भाषण में है। … (व्यवधान) मैं आपकी सुविधा के लिए बताता हूं। श्री वी. डी. सावरकर का यह भाषण आप ‘समग्र सावरकर वंगमाया’, हिन्दू राष्ट्र दर्शन, वॉल्युम-6, महाराष्ट्र प्रांतिक हिन्दू सभा, पुणे, 1963 के पेज नंबर 460-61 पर देख लीजिए। … (व्यवधान)

Netaji Subhas Chandra Bose bluntly accused the Hindu Mahasabha of being more interested in the downfall of the Congress than the Independence of India. In March 1940 editorial, he wrote that the Hindu Mahasabha had colluded with the British in the Calcutta Municipal election at the expense of Indian parties.

मैं यह इन्ट्रोस्पेक्शन के लिए कह रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि इतिहास को सामने रखकर हम सब इससे कुछ सीख लें। … (व्यवधान) सिर्फ एनिवर्सरी और सेलिब्रेशन मनाने से काम नहीं बनने वाला है। हमें असलियत ढूंढनी है, गहन अध्ययन करना है और अच्छी सोच के साथ हमें आगे चलना है। देखिए, यह एक नया जमाना आ गया है, a new era of toxic cocktail of Hindutva with populism, a new alchemy achieved by Prime Minister, Modi Ji, who is viewed by his supporter, rather I may say by his sycophants … (*Interruptions*)

मोदी साहब, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीन दिनों से चर्चे चल रहे हैं – मोदी, मोदी, मोदी, मोदी, मोदी, मोदी। आपका नाम जितनी बार यहां उच्चारित हुआ है, उल्लेख हुआ है, अगर सही ढंग से राम, राम, राम, राम पुकारते तो भगवान राम सीधे पार्लियामेंट में आ जाते। ... (व्यवधान) हर बात में सिर्फ मोदी, मोदी, मोदी, मोदी। ... (व्यवधान) पता नहीं मोदी जी का नाम लेने की क्यों ऐसी होड़ लगी है? लगता है कि मोदी जी, मोदी जी करने से मोदी जी ज्यादा खुश होंगे, किसी को कुछ मिलने का मौका आएगा। लेकिन बात यह है, असलियत यह है कि मोदी जी, मोदी जी कहते हुए जो समय बर्बाद हुआ है, उस समय अगर आप चर्चा में शामिल हुए होते, तो आप खुद बोल सकते थे। ... (व्यवधान)

मोदी जी, आपके सपोर्टर्स सोचते हैं कि आप एक प्रोविडेंशियल हैं। You have added new adjectives with democracy – ethnic democracy and electoral democracy to transform India into a Hindu Raj. BJP's populist politics and promises made to the poor during election campaign did not translate into policies. इसी कारण मेरे लीडर श्री राहुल गांधी आप लोगों की तीखी आलोचना करते हुए, हिन्दुस्तान को आप दो हिस्सों में बांटते हैं, इसका आपसे ज़िक्र किया है। आपके बीच खलबली मच चुकी है। आप बात नहीं समझते हैं, लेकिन आपके बीच खलबली मच जाती है। आप गाली-गलौच करने लगते हैं, लेकिन हिन्दुस्तान सही मायनों में दो हिस्सों में बंट जाता है।

(1800/SRG/KDS)

गरीब और अमीर के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं। 80 और 20 के प्रतिशत में आप हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं। नफरत एक बुरी चीज होती है। हमें इसे नहीं पालना है। दिल की कालिख को निकाल दीजिए। न इसका न उसका, न तेरा न मेरा, यह वतन सबका है। इसे बचा लीजिए, इसकी रक्षा कर लीजिए। यही हमारी राय है।

महोदय, जब वर्ष-2019 के चुनाव हुए थे, 2019 election campaign marks a transition in India towards electoral authoritarianism precisely because electoral competition was no longer a level playing field, not only due to the Ruling Party's financial resources, but also of the role of the media and the bias of the institution in-charge of election process. यह मेरी नहीं, बल्कि ऑथर Jaffrelot की राय है।

I quote Jane Warner Muller, `populists are against pluralism because they claim that they represent all the people, making political oppositions not only redundant, but also illegitimate and even anti-national.' The thesis of Edward Shills adds that `populist, since he is the people, stands above institutions; his legitimacy prevails over other power centres - even when they embody legality because legality cannot compete with his legitimacy.'

In the book, `How Democracy Dies', Steven Levitsky and Daniel Ziblatt consider one of the indicators of authoritarian behaviour is that rulers endorse violence by their supporters by refusing to unambiguously condemn it and punish it. मोदी जी, आप यह करते हैं। आपने इसे कैसे किया? गोडसे की पूजा होती थी। अभी भी कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं, जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। उस विषय को लेकर जब हमने सदन में आपके सदस्य के खिलाफ यह बात रखी थी, तो आपने यह बयान दिया था कि मैं क्षमा नहीं कर सकूंगा, लेकिन बाद में आपने कुछ भी नहीं किया। आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से खून-खराबा और दंगे-फसाद हो रहे हैं, खुली जुबान से आपको इस दिशा में कुछ बात रखनी चाहिए। हमें आपसे बोलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप सदन में आते ही नहीं हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि Modi Ji on an average has spoken 3.6 times a year in Parliament; 22 times in six years, not more than Shri H.D. Deve Gowda who was PM for two years. In contrast, Shri Atal Bihari Vajpayee spoke 77 times in six years when he was Prime Minister. Manmohan Singh Ji who was called `Maun' Mohan Singh by Modi Ji in 2012 spoke 48 times in Parliament during his tenure in office. मौन कौन है? श्री मनमोहन सिंह जी मौन नहीं हैं। मोदी जी बाहर बात करते हैं, लेकिन सदन के अंदर बात नहीं करते हैं। आप आज आए, हम लोग धन्य हो गए।

In order to circumvent Parliament, Modi Ji has often followed the Ordinance route. हमारे समय में भी ऑर्डिनेन्स हुए थे, लेकिन हमारे समय में जो ऑर्डिनेन्स हुए थे, उनसे कई गुना ज्यादा ऑर्डिनेन्स अब निकलने लगे हैं। आप मेजॉरिटी में हैं, आपके पास बहुमत है, फिर भी आप ऑर्डिनेन्स को हथियार बनाकर सदन चलाना चाहते हैं। ऐसा करने के पीछे आपका इरादा क्या है, यह हमें पता चलता है।

मोदी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। अगर हो सके तो आप अपने जवाब में मेरी बात का जिक्र जरूर करिएगा। During a celebration of 75th year of our birth as an independent democratic nation, PM was lamenting. आप यह कहते थे कि ज्यादा अधिकार मांगना और कर्तव्य-पालन न करना, देश को कमजोर करता है।

(1805/CS/AK)

हम इसका व्याख्यान चाहते हैं। Too much preoccupation with rights and too little emphasis on duties has weakened India. क्योंकि आपकी यह बात सुनकर 1936 का रशियन कांस्टिट्यूशन याद आता है। रशियन कांस्टिट्यूशन में 1936 में यह फैसला हुआ था कि आम लोग should be assigned to the mother land. They cannot enjoy the civil right or political right because it is Soviet Union. लेकिन हमारे देश में, हमने तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज अपने संविधान में डाली हैं।

इस संविधान को इस देश के लोगों ने बनाया है। देश के बड़े-बड़े नेताओं ने यह संविधान बनाया है। हम इस संविधान की मूल भावना को बयान करना चाहते हैं। हम लोगों ने क्या किया, रेकग्नाइज किया, क्या रेकग्नाइज किया? Let me seize the opportunity of citing a few immortal words of our Constitution. It states : "We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic Republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity in our Constituent Assembly this Twenty-Sixth day of November, 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution". … (*Interruptions*)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सर, ये गलत बोल रहे हैं।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): इसका मतलब यह है कि यस, हम लोगों ने कभी यह नहीं कहा।… (व्यवधान) हम लोगों ने कभी यह नहीं कहा कि : "We, the Hindus of India having solemnly resolved …". हम लोगों ने यह नहीं कहा : "We, the Muslims of India having solemnly resolved …". हम लोगों ने क्या कहा : "We, the people of India having solemnly resolved …". इस 'वी' को आप हटाना नहीं। यह मसला आपका नहीं, मेरा नहीं, यह हम सबका है। किसी को लगता है कि हिन्दू खतरे में है, किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है, जरा धर्म का चश्मा उतारकर देखो यारों, हिन्दुस्तान खुद खतरे में है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपका आरएसएस always disagrees with the Constitution and its insistence on accountable governance and empowered citizenry. Even Vajpayee ji also constituted a high-profile Commission to review the working of the Constitution.

मुझे लगता है कि एक-एक समय जब आता है, कभी आपको यह लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनना चाहिए, कभी आपको लगता है कि मुसलमान मुक्त भारत बनना चाहिए, अभी क्या यह लगेगा कि अधिकार मुक्त भारत बनना चाहिए। यह मेरा डर है, क्योंकि यह डर आप पैदा करते हैं। जब आप कहते हैं कि too much preoccupation with rights and too little emphasis on duties has weakened India. आपको लगता है कि इंडिया कमजोर होता जा रहा है। अगर आपको लगे कि इंडिया कमजोर होता जा रहा है, आप बताइए, हिन्दुस्तान को शक्तिशाली करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। सब आपकी मदद करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गाँधी जी भी कहकर गए हैं कि हम सब देश की रक्षा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं।

आपने अब तक क्या किया, यह आप सदन में आकर नहीं बताते हैं कि चाइना ने हमारे हिन्दुस्तान की कितनी जमीन को हड़प करके रखा है।... (व्यवधान) क्या यह हमें जानने का अधिकार नहीं है? ... (व्यवधान) यह हमें जानने का अधिकार नहीं है।... (व्यवधान) हम बार-बार सदन में गुहार लगाते हैं। आप लद्दाख में जाइए, 'वाई' जंक्शन, चाइनीज फौज ने यह 'वाई' जंक्शन कैप्चर करके रखा है। आप जानते हैं कि यह 'वाई' जंक्शन क्या है, it is 18 kms. inside the Indian territory. This means that they are denying access to the Indian Army on 900 sq. kms. of area. Could you imagine it? 'Y' Junction is also the main route to approach the Tololing point.

(1810/SPR/KN)

Do you know 18 friction points are still existing? 18 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जहां चीनी फौजों ने हमें घुसने नहीं दिया। यह क्या है? This junction can directly influence Indian movement on DSDBO road. If this road is cut, all its forces in Depsang and Daulat Baig Oldie airways can be cut off. इसलिए मैं कहता हूं कि कोई मिस्टेक अगर कभी हुई थी, तो उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि देश की रक्षा करनी है, देश को बचाना है।

मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आप निर्णय लेने की जिम्मेवारी हमारी फौजों पर छोड़ दीजिए, इसमें पॉलिटिकल बात मत रखिए, पॉलिटिकल डिसिजन न लीजिए। हमारी फौजों पर जिम्मेवारी छोड़ दीजिए। जब गलवान में घटना घटती है, हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं और दो दिन के बाद आप प्रधान मंत्री होने के नाते कहते हैं कि गलवान में कोई नहीं घुसा। किसी ने कहीं कब्जा नहीं किया, तो सबसे ज्यादा सुविधा किसको होती है– चीनी सरकार को। वह तुरंत चले जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने खुद कहा है कि गलवान में चीनी फौज ने अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि हिन्दुस्तानी फौज अतिक्रमण करके चाइनीज एरिया में घुसी है। It is implied तो हमें कमजोर होना पड़ा। आप देखिए, हमारे रक्षा मंत्री ने लड़खड़ाते हुए कह दिया कि हाँ, अतिक्रमण हुआ है। जब प्रधान मंत्री जी का बयान आ गया, डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट से उनका बयान हट गया। आप उत्तराखंड में चलिए। बाराहोती में क्या हुआ? हमारी सरहद पर आकर चीनी फौजों ने हमला कर डाला। आप सिक्किम में चले जाइये, अरुणाचल में चले जाइये। मैं नहीं, आपकी पार्टी के एमपी तापिर गाव ने खुद कहा है कि अरुणाचल में चीनी फौजें हमारी सीमा में घुस कर हमारे बच्चे को उठा कर ले गईं। यह मैं नहीं कहता, मैं आपको तापिर गाव की ट्वीट पढ़ कर सुनाता हूं। It says: "Chinese PLA has abducted Shri Miram Taron, a 17-year old of Zido village yesterday, the 18th January 2022 from inside Indian territory, Lungta Jor area (China built 3-4 kms. road inside India in 2018) under Siyungla area (Bishing village) of Upper Siang district of Arunachal Pradesh." यह मैं नहीं कहता, आपकी पार्टी के एमपी, वहां के अध्यक्ष तापिर गाव खुद कहते हैं। आप इसको न नहीं कर सकते। हमारे कानून मंत्री किरेन रिजीजू जी भी वहां से है। उनकी भी हिम्मत नहीं है कि इसको न करें। क्योंकि जो हुआ है, वह हुआ है। लेकिन यह कैसे हो रहा है, इसको रोका कैसे जाएगा, इस विषय पर हम क्या सोचते हैं? यह हम सब को प्रधान मंत्री जी आप जानकारी दीजिए। चीनी अतिक्रमण के बारे में आप हमें थोड़ा अवगत कराइये, क्योंकि हम सब लोग बेचैन हैं।... (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): उन्होंने पब्लिकली और स्टेटमेंट में बयान दिया है कि बॉर्डर एरिया में, जहां डिफाइन नहीं है, यह सब को मालूम है, वह वहां हंटिंग के लिए गए थे और वहां जाते समय उसको मालूम नहीं है कि बॉर्डर कहां है? क्योंकि डिमार्केटेड लाइन नहीं है, तो वहां उनको पकड़ा है। उसने खुद कहा है कि चाइना इंडियन टेरिटरी में घुस कर पकड़ कर ले गया। उन्होंने खंडन किया है कि ऐसा नहीं है। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि आप मिस-कोट मत करो। यह सदन बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बात यहां रिकॉर्ड होती है। इसलिए आर्मी ने भी इसका क्लेरिफाई कर दिया है, इसलिए मिस-कोट न करें।… (व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मेरी जो बात है, इस बात को घुमा-फिरा कर कहने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब जानते हैं। सारी दुनिया में यह चर्चा हो रही है कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस रहा है। हमारे सीमा में घुस कर बिल्डिंग बना रहा है, पैंगोंग त्सो में ब्रिज बना रहा है। यह पेंटागन खुद कहता है, मैं क्या कहूं, मैं एक छोटा-मोटा आदमी हूं। यह सब कहते हैं।… (व्यवधान)
श्री किरेन रिजीजू : आप इंडियन आर्मी पर विश्वास नहीं करते हैं? आप विदेशी सोर्स का विश्वास करते हैं क्या? आप इंडियन आर्मी के सोर्स को कोट करो।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप कह दीजिए कि यह गलत है। आप कह दीजिए कि हमारी फौज चीनी टेरिटरी में घुस गई थी, जिसके कारण चीनी फौजों ने उसको मार डाला। आप कह दीजिए, इसमें हर्ज क्या है? देखिए, मैं आप लोगों पर कोई इल्जाम नहीं लगाता हूं। यह हम सब की चिंता है। हमारी चिंता इसलिए है, क्योंकि धीरे-धीरे हमारे साथ… (व्यवधान)
श्री किरेन रिजीजू : सर, यह बहुत सीरियस, संवेदनशील मुद्दा है और लोक सभा में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है। हर चीज सोच-समझ कर कहनी चाहिए। यह सीरियस भी है और सेंसटिवि भी है। हर स्टेटमेंट, जो भी आप इस सदन में कहते हैं, बहुत सोच समझ कर भारत सरकार तथा आर्मी के सोर्स को कन्फर्म कर तब आपको कहना चाहिए। … (व्यवधान)
(1815/GG/UB)
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): क्या चाइना पर चर्चा करना गलत होगा? सर, मैं यह कह रहा हूँ कि डोकलाम में हमारी फौज आपके नेतृत्व में डर से रुकी थी। लेकिन बात यह है कि डोकलाम से हमने सीखा नहीं। डोकलाम की घटना को नज़रअंदाज़ करते हैं। हम आत्मतुष्टि की भावना में डूबे हुए थे। आपने शायद सोचा होगा कि शी जिंगपिंग के साथ हमारी और कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि दोस्ती बढ़ती जा रही है। चीनी सरकार की यह जो इविल इंटेशन थी, शायद आपको पता नहीं होगी। अगर हम इसको पॉइंट आउट करते हैं तो इसमें गलती क्या है? चीन हमें घेरने की कोशिश तो कर रहा है। हमको इंटरनली स्टैब्लाइज़ होना चाहिए। आप देखिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रांग इकोनॉमी चाहिए, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी चाहिए, सोशल स्टेब्लिटी चाहिए। मैं प्रधान मंत्री जी को यह जरूर कहना चाहता हूँ कि आपने बांग्लादेश में जाने के बाद तैयार किया था, लेकिन बांग्लादेश की आम जनता ने आपके खिलाफ प्रदर्शन तो वहां की सरकार ने न कर दिया। यह हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है।

आप मालदीव में जाइए, चाइनीज़ इंस्टिगेशन की बदौलत वहां इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। चाइना वहां उकसाता है और इंडिया आउट कैंपेन चलता है। इसका मतलब हमारे पीछे चीन और पाकिस्तान सब मिले हुए हैं और हमको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर के हालात आप ठीक कर लीजिए। मैं इसलिए यह कह रहा हूँ क्योंकि हरिद्वार की जो घटना घटी थी, वहां जो हिंदू सम्मेलन हुआ था, उसके बाद प्रधान मंत्री जी को और महामहिम राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिखी गई। यह चिट्ठी मैंने नहीं लिखी। Some of the signed dignitaries include four former Chiefs of Naval Staff – Admiral (Retd.) Laxminarayan Ramdas, Admiral (Retd.) Vishnu Bhagwat, Admiral (Retd.) Arun Prakash, Admiral (Retd.) R K Dhowan, and Vice Admiral (Retd.) Raman Prem Suthan. उसमें क्या लिखा था? उसमें यह लिखा था कि "We cannot allow such incitement to violence together with public expressions of hate, which not only constitute serious breaches of internal security, but which could also tear apart the social fabric of our nation. One member made a call to the army and police to pick up weapons and participate in the cleanliness drive, that means '*safai abhiyan*'. This amounts to asking the army to participate in genocide of our own citizens, and is condemnable and unacceptable. We are seriously perturbed by the content of speeches made during a three to four days religious conclave called a *Dharam Sansad*, of Hindu Sadhus and other leaders, held at Haridwar between 17th -19th December 2021. There were repeated calls for establishing a *Hindu Rashtra* and, if required, picking up weapons and killing of India's Muslims in the name of protecting Hinduism." सर, मैं इसको प्रधान मंत्री जी की निगाहों में लाना चाहता हूँ। शायद सब उनको सच्चा नहीं भी कह सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज मौका मिलते ही ये सारी बातें बताऊं।

सर, मैं अभी इस बात पर आता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के नौजवान बेरोज़गार हैं। 53 मिलियन नौजवान बेरोज़गार पड़े हुए हैं, यह सीएमआई की रिपोर्ट कहती है। चुनाव के पहले मोदी जी कहते थे कि सालाना दो करोड़ नौकरियां मिलेंगी और अभी कह रहे हैं कि 60 लाख मिलेंगी। कम कर दिया, ठीक है, अच्छा किया। लेकिन जो बेरोज़गार पड़े हुए हैं, वह क्या करेंगे? क्या आप जानते हैं कि वे अभी क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मोदी जी आपके अच्छे दिन के सपने हमने देख लिए हैं, हम और अच्छे दिनों का सपना नहीं देखना चाहते हैं। वे अब कहते हैं कि मोदी जी आप हमारे बुरे दिन लाइए। मोदी जी लौटा दीजिए हमारे बीते हुए दिन।

(1820/RV/KMR)

हम कहते हैं - बेकार, नौजवान। बेरोजगार नौजवान कहता है – 'मोदी जी, मुझे लौटा दे, बीते बुरे दिन।' आप किधर जाएंगे? आप महंगाई को देखिए। प्रधान मंत्री जी, आप चौंक जाएंगे। यह क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वर्ष 2014 में एक लीटर पेट्रोल का दाम 68 रुपये प्रति लीटर था, आज वह 110 रुपये प्रति लीटर है। इसमें कितनी फीसदी बढ़ोतरी हुई है? इसमें 62 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।। डीजल 57 रुपये प्रति लीटर था। आज वह बढ़ कर 95 रुपये प्रति लीटर पर चला गया। इसमें 67 प्रतिशत का इजाफा है। एल.पी.जी. सिलिण्डर पहले 414 रुपये प्रति सिलिण्डर था। अभी वह 900 रुपये है। इसमें 117 प्रतिशत इजाफा है। वर्ष 2014 में टोमैटो 18 रुपये प्रति किलो था, अभी 35 रुपये प्रति किलो है। इसमें 84 फीसदी इजाफा हुआ। कैप्सिकम 33 रुपये प्रति किलो था, अभी वह 72 रुपये प्रति किलो है। इसमें 118 फीसदी इजाफा हुआ। हम लोग कहां जाएंगे? यहां की आम जनता कहां जाएगी? मस्टर्ड ऑयल से लेकर कोकोनट ऑयल, ग्राउण्डनट ऑयल, वनस्पति घी, तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, ग्राम दाल, हर जगह जिस तरह से दाम में इजाफा हुआ है तो आम लोग भी अब कहने लगे हैं – 'मोदी जी, लौटा दे मेरे, बीते बुरे दिन।' लोग कहते हैं कि हम गरीब होते जा रहे हैं। हमारे ऊपर बोझ क्यों डालते हैं? मोदी जी, हिन्दुस्तान दो हिस्से में बँटा है। हमारे नेता राहुल गाँधी जी ने इसलिए कहा था कि अमीर और गरीब में फर्क बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप एक कार खरीदते हैं, जिसका दाम होता है – 15 करोड़ रुपये। आप एक प्लेन खरीदते हैं, जिसका दाम होता है साढ़े चार हजार करोड़ रुपये, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बेकार नौजवान रास्ते में भटकते हुए आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे भटकते नौजवान दिन-रात रास्ते में भटकते हुए माँ-बाप की गाली खाते हैं। आपको यह पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं मोदी जी को याद दिलाता हूं कि मोदी जी, आप सत्ता में हैं और सत्ता में आने के बाद आप एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस को तोड़ रहे हैं, यह सही नहीं होगा। आप पेगासस डाल रहे हैं। हमारे खिलाफ पेगासस को एक औजार की हैसियत से इस्तेमाल कर रहे हैं। पेगासस का इस्तेमाल करते समय क्या आपको यह नहीं लगता है कि हम किसके खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल करते हैं? हमारे हिन्दुस्तान की आम जनता से टैक्स वसूला जाता है और उसी टैक्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे खिलाफ इस खुफिया तंत्र का आप इस्तेमाल करते हैं। यह क्यों होता है? हमारे खिलाफ यह अन्याय क्यों होता है? यह हम जानकारी लेना चाहते हैं।

एक के बाद एक, जैसे आपके आने के बाद लोकपाल बिल खत्म हो गया, व्हिसलब्लोअर्स बिल खत्म हो गया, राइट-टू इंफॉर्मेशन एक्ट खत्म हो गया, ज्युडिशियरी पर ज्यादा हस्तक्षेप होने लगा। एक के बाद आप देखते जाइए। आप खुद पता कर लीजिए कि मैं जो कहता हूं, वह सही है या नहीं। हमारी इस तरह से छवि धूमिल होती जा रही है। आप सिटीजेन्स अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, लेकिन इस सिटीजेन्स अमेंडमेंट एक्ट के चलते हमारी जो सारी नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां की आम जनता आपके खिलाफ आवाज़ बुलन्द करती है। यह हमारे देश के लिए हानि है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल कन्जम्पशन के लिए आप हमारे देश की सुरक्षा को खतरे में मत डाला कीजिए, यह हमारी आपसे मांग है।

सर, मैं एक बयान पेश करता हूं कि यहां बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं कि हिन्दुस्तान की तरक्की हो रही है। India recorded a daily average of 77 rapes a day in 2020, a negligible decline from 88 rapes per day in 2019. Ninety per cent of crimes were registered under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) in 2020. There was 9.4 per cent increase in crimes against members of Scheduled Castes and 9.3 per cent increase in crimes against the members of Scheduled Tribes. The highest number of cases of atrocities were recorded in BJP-led States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar. India's status in the Freedom in the World 2021 Report was downgraded from 'Free' to 'Partly Free'. Hate crimes against religious minorities have spiked by 300 per cent since the BJP assumed power in 2014. Incidents of cow vigilantism and related violence have increased sharply in PM Modi ji's successive governments. Despite the COVID-19 lockdown in 2020, 16 such incidents were recorded which resulted in 94 deaths.

मोदी जी, कोविड के चलते जो एक्स-ग्रेशिया मिलना चाहिए था, एस.डी.आर.एफ. में आप पैसा मुहैया कराकर सारे एक्स-ग्रेशिया पाने वाले को जल्द से जल्द ये पैसा मुहैया कराएं, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

कम्युनल एण्ड रिलीजियस रायट्स में कितना इजाफा हुआ है – 95.6 प्रतिशत। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स कितने बढ़े हैं? यह 49.6 प्रतिशत बढ़ा है।

(1825/MY/RCP)

मोदी जी, आप देखिए कि अभी क्या हो रहा है। Under the Modi *ji*'s Government, India slipped 10 places in the World Justice Project's (WJP) Rule of Law Index 2021 to 79th place out of 139 countries. It is now rated third in South Asia after Nepal and Sri Lanka. On the Order and Security factor, India slipped to 121st rank from 114 in 2020. In terms of Civil Justice, India ranked 114 compared to 78 in 2020. इसलिए, हम चाहते हैं कि मोदी जी, आप इस पर ध्यान दीजिए। हम सब यह मानकर चलते हैं कि यह देश हम सबका है। सुख हो या दुख हो, हर हालत में देश हमारे दिल का सहारा है। भारत प्यारा, देश हमारा, यह सारे देश से प्यारा है। इस देश को हमें बचाना है। इस देश की हमें रक्षा करनी है। नमस्कार

(इति)

1826 बजे

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने की अनुमति दी।

अध्यक्ष जी, मैं यहाँ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। आज हम आजादी का 'अमृत महोत्सव' मना रहे हैं। हम आजादी के अमृत-काल से गुजर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान, इस देश को हमें किस गति से आगे ले जाना है, इस देश को हमें किस दिशा में ले जाना है, इसके लिए संकल्प किया है। उनकी सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, बहुत सारे फैसले जो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा लिए गए हैं, वे इस देश को विकास की ओर ले जाने के लिए, इस देश को सशक्त करने के लिए, इस देश को और मजबूती प्रदान करने के लिए हैं। देश के लिए जो फैसले लिए गए हैं, पिछले आठ सालों में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के द्वारा लिए गए हैं।

आजादी के 'अमृत महोत्सव' में नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं, उसमें ऐसी उनकी मंशा है, क्योंकि आज हम आजादी के 75वें वर्ष में खड़े हैं। आजादी के आने वाले 25 सालों में हम कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, हम कैसे भारत को बनाना चाहते हैं, उसके लिए यह काल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, मैं नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार का धन्यवाद इसके लिए भी करता हूँ कि उन्होंने इस देश की बुनियाद को बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, वह बहुत ही सशक्त कार्य है। हमारे विपक्ष के लोग अभी बोल रहे थे, ये लोग कई बार उनकी आलोचना करना चाहते हैं। मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप कम्पेयर कर लीजिए कि आपके 70 साल के काल में जो कार्य हुए और पिछले आठ साल में जो कार्य हुए, वे कई गुना अधिक कार्य हुए हैं। देश के गरीबों के लिए कार्य हुआ है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, उनके लिए मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ:

उन्हें गुमान है कि हमारी उड़ान कुछ कम है,
मुझे यकीन है कि आसमां हमारे लिए कुछ कम है।

महोदय, यहाँ पर मैं कोरोना महामारी की बात करूँगा। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं भली-भाँति जानता हूँ कि यह जो महामारी आई, इतनी अप्रत्याशित और असमान्य महामारी पहले हमने कभी नहीं देखी। मेरी मेडिकल कार्य अवधि करीब पचास साल की रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो कोरोना महामारी आई, जो बड़े से बड़े देश हैं, जिनका मेडिकल ढाँचा बहुत ही मजबूत था, वे भी बिखर गए। इसमें अमेरिका है, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, जापान है। ऐसे सभी देश बिखर गए थे, बौखला

गए थे। भारत में हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज़ थे, तब नरेन्द्र भाई मोदी जी ने हमें जिस प्रकार का नेतृत्व दिया, उनकी सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए, उन निर्णयों के लिए पूरा देश नरेन्द्र भाई मोदी जी और इस सरकार का आभारी रहेगा।

(1830/CP/RK)

जब दूसरे देश लड़खड़ा गए थे, तब नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के साथ जो लड़ाई लड़ी गई, जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, वह बेमिसाल लड़ाई थी। इस महामारी में जिनके द्वारा हमें लड़ाई लड़नी थी, वे कोरोना वॉरियर्स हों या डॉक्टर्स हों या नर्सेज़ हों या स्वास्थ्यकर्मी हों, या पैरा मेडिकल स्टॉफ हो या सफाईकर्मी हों या हमारे सिक्योरिटी के लोग हों या हमारे वैज्ञानिक हों, उनको नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा इनकरेजमेंट मिला। उससे उन्होंने यह कार्य करके दिखाया है।

हमारे विपक्ष के लोग उस वक्त ताली बाजाना हो, दिया जलाना हो, थाली बजाना हो, उस पर वे लोग कटाक्ष करते थे।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन): प्राइवेट मेंबर्स बिल का जो डिस्कशन है, उसमें अभी इंट्रोडक्शन लिया जाए और इंट्रोडक्शन के बाद फिर यह चर्चा जारी रखें।

माननीय अध्यक्ष : आज केवल गैर-सरकारी विधेयकों के पुर:स्थापन को लिया जाए। तत्श्चात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखी जाए। आज की कार्य सूची में चर्चा के लिए सम्मिलित गैर-सरकारी विधेयक 17 मार्च, 2022 को कार्य सूची में सम्मिलित किए जाएंगे।

माननीय किरीट सोलंकी जी आप अपना भाषण बाद में चालू रखेंगे। प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद आप अपनी बात कंटीन्यू रखेंगे। जो माननीय सदस्य राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में बाकी रह गए हैं, वे जितनी देर तक बैठे रहेंगे, उनको मौका दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : अब सदन गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेगी।

श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगरे - अनुपस्थित

श्री रवनीत सिंह - अनुपस्थित

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी जी।

INDIAN EASEMENTS (AMENDMENT) BILL
(Amendment of section 7, etc.)

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Easements Act, 1882.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय *सुखाचार* अधिनियम, 1882 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्दीन ओवैसी जी - अनुपस्थित

श्री रमेश चन्द्र कौशिक - अनुपस्थित

श्री भर्तृहरि महताब।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I have three Bills to introduce. I may be allowed to introduce them one after another.

HON. SPEAKER: Okay.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Substitution of new article and sub-heading thereto for article 29)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I introduce the Bill.

PREVENTION OF ACID ATTACKS AND REHABILITATION OF ACID ATTACK VICTIMS BILL

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for prevention of acid attacks and rehabilitation of women victims of acid attacks and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> “कि अम्ल हमलों के निवारण और अम्ल हमले की महिला पीड़ितों के पुनर्वास तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 84 and 173)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> “कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I introduce the Bill.

(1835/PS/NK)

HON. SPEAKER: Shri Asaduddin Owaisi Ji – Not present.

Shri Ashok Mahadeorao Nete – Not present.

Shrimati Riti Pathak – Not present.

Shri Sudheer Gupta – Not present.

Shri Rakesh Singh – Not present.

Shri Ravi Kishan – Not present.

Shri Manish Tewari – Not present.

Shri Feroze Varun Gandhi – Not present.

Now, Item No. 41, Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

GUTKA AND PAN MASALA (PROHIBITION) BILL

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit the production, promotion and sale of gutka and pan masala.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, संप्रवर्तन और विक्रय का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I introduce the Bill.

HON. SPEAKER: Now, Shri Feroze Varun Gandhi.

1836 hours (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

PREVENTION OF BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS AND OFFICIALS OF PUBLIC INTERNATIONAL ORGANISATIONS BILL

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent corruption relating to bribery of foreign public officials and officials of public international organisations and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prevent corruption relating to bribery of foreign public officials and officials of public international organisations and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Sir, I introduce the Bill.

ONLINE PLATFORM DELIVERY PERSONNEL (PROTECTION) BILL

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide rights, welfare and social security to online platform delivery personnel and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide rights, welfare and social security to online platform delivery personnel and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Shri Rajendra Agrawal – Not present.

Now, Item No. 44, Shrimati Supriya Sadanand Sule

JUDICIOUS USE OF TAX REVENUE (FOR GOVERNMENT ADVERTISEMENTS) BILL

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to strictly prohibit the use of tax revenue for any form of promotion of the Central Government, State Governments, elected and nominated representatives, politicians and political parties, symbols and colours and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to strictly prohibit the use of tax revenue for any form of promotion of the Central Government, State Governments, elected and nominated representatives, politicians and political parties, symbols and colours and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Shri P. P. Chaudhary – Not present.

Shri Shrirang Appa Barne – Not present.

Now, Shrimati Rama Devi

महिला (विकास और कल्याण) प्राधिकरण विधेयक

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि योजनाओं के निरूपण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए उपाय़ों के बारे में समुचित सरकार से सिफारिश करने के संबंध में महिला विकास और कल्याण प्राधिकरण के गठन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब): प्रश्न यह है:

"कि योजनाओं के निरूपण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए उपाय़ों के बारे में समुचित सरकार से सिफारिश करने के संबंध में महिला विकास और कल्याण प्राधिकरण के गठन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

महिला (कार्यस्थल में आरक्षण) विधेयक

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि स्थापनाओं में महिलाओं हेतु पदों के आरक्षण और तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for reservation of posts for women in establishments and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण (संशोधन) विधेयक
(धारा 5 और 9 का संशोधन)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005."

The motion was adopted.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

(1840/SMN/SK)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB):

Shri Jasbir Singh Gill – not present.

Dr. Shrikant Eknath Shinde – not present.

Shri Ravi Kishan – not present.

Shri Jagdambika Pal – not present.

Prof. Ram Shankar Katheria – not present.

Dr. Sukanta Majumdar – not present.

Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu – not present.

Shri Sunil Kumar Singh – not present.

Shri Benny Behanan.

DESTITUTE AND NEGLECTED WOMEN (WELFARE) BILL

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the maintenance and welfare measures to be undertaken by the State for the destitute, neglected, old, infirm or physically challenged widow, divorcee or unmarried women through establishment of an Authority and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leaved be granted to introduce a Bill to provide for the maintenance and welfare measures to be undertaken by the State for the destitute, neglected, old, infirm or physically challenged widow, divorcee or unmarried women through establishment of an Authority and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I introduce the Bill.

*****

PERSONS LIVING IN COASTAL ZONE
(REHABILITATION AND WELFARE) BILL

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for setting up of an Authority for rehabilitation and welfare of persons living in coastal zone and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for setting up of an Authority for rehabilitation and welfare of persons living in coastal zone and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I introduce the Bill.

*****

HON. CHAIRPERSON: Shri Vincent H. Pala – not present.

Shri Manoj Kotak.

ESTABLISHMENT OF SPECIAL SCHOOLS FOR
MENTALLY RETARDED CHILDREN BILL

SHRI MANOJ KOTAK (MUMBAI NORTH-EAST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of special schools including residential and school for mentally retarded children by the Union and the State Governments and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of special schools including residential and school for mentally retarded children by the Union and the State Governments and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI MANOJ KOTAK (MUMBAI NORTH-EAST): Sir, I introduce the Bill.

INFORMATION TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL
(Insertion of new section 66CA)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000."

The motion was adopted.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I introduce the Bill.

*****

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2020
(Amendment of article 16)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I introduce the Bill.

*****

INFORMATION TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL
(Amendment of section 7).

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000."

The motion was adopted.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I introduce the Bill.

*****

राष्ट्रीय लघु राज्य निर्माण बोर्ड विधेयक

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि लघु राज्यों के निर्माण के लिए संभावनाएं तलाशने और रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय बोर्ड गठित करने; इसके संबंध में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करने और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to constitute the National Board to explore possibilities and prepare blueprints for creation of small States; make recommendations thereto to the Central Government and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*****

HON. CHAIRPERSON: Shri Vinod Kumar Sonkar – not present.

Shri Hemant Patil – not present.

Shri Su. Thirunavukkarasar – not present.

Prof. Rita Bahuguna Joshi – not present.

Dr. Manoj Rajoria – not present.

Shrimati Locket Chatterjee – not present.

(1845/SNB/SK)

WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955."

The motion was adopted.

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item no. 83, Shri P. V. Midhun Reddy -- Not present; Item No. 84, 85 and 86. Shrimati Ranjeeta Koli -- Not present; Item No. 87, Shrimati Poonam Mahajan – Not present; Item No. 88, Adv. Adoor Prakash -- Not present; Item No. 89, Shri Asaduddin Owaisi -- Not present; Item No. 90, Shri Tirath Singh Rawat -- Not present; Item No. 91and 92, Shri Santokh Singh Chaudhary – Not present; Item No. 93, Shri Sudheer Gupta -- Not present; Item No. 94, Shri Ashok Kumar Rawat -- Not present;

Item No. 95 Shri Ramdas Tadas

विदर्भ राज्य निर्माण आयोग विधेयक

श्री रामदास तडस (वर्धा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन कर पृथक विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए एक आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Commission for the formation of a separate State of Vidarbha by re-organization of the existing State of Maharashtra and for matters connected therewith."

श्री रामदास तडस (वर्धा): महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक

(<u>धारा 2 का संशोधन, आदि</u>)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016."

The motion was adopted.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

जनसंख्या नियंत्रण विधेयक

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for measures to control the population in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

एकल उपयोग प्लास्टिक (विनियमन) विधेयक

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश को वर्ष 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक का उन्मूलन करने का लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाने की रूपरेखा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for measures to control the population in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

COMPULSORY YOGA AND SPORTS EDUCATION IN SCHOOLS BILL

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory yoga and sports education from primary to senior secondary level in all the schools throughout the country and making it obligatory for the Central and State Governments to provide requisite infrastructure in order to prepare talent of sports from school level thereby ensuring good health of students and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory yoga and sports education from primary to senior secondary level in all the schools throughout the country and making it obligatory for the Central and State Governments to provide requisite infrastructure in order to prepare talent of sports from school level thereby ensuring good health of students and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I introduce the Bill.

COMPULSORY DONATION OF SURPLUS FOOD BILL

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory donation of surplus food packets by super-markets, promotion for reduction of food wastage and creation of an institutional mechanism for monitoring and implementing the process and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory donation of surplus food packets by super-markets, promotion for reduction of food wastage and creation of an institutional mechanism for monitoring and implementing the process and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Sir, I introduce the Bill.

(1850/RU/MK)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Item No. 101, Shri Abu Hasem Khan Choudhury – not present. Item No. 102, Shri Kumbakudi Sudhakaran – not present.

Shri Nihal Chand Chouhan.

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक
(नई धारा 6क का अंत:स्थापन)

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009."

The motion was adopted.

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Item No. 104, Shri Kumbakudi Sudhakaran – not present. Item No. 105, Dr. Sukanta Majumdar – not present.

Shri Manoj Kotak.

WELFARE OF FAMILIES OF DEFENCE PERSONNEL BILL

SHRI MANOJ KOTAK (MUMBAI NORTH-EAST): Sir, I request you to club item No. 106 and item No. 115.

Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for constitution of a fund for the welfare of families of defence personnel who are killed in action or seriously injured during such action and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of a fund for the welfare of families of defence personnel who are killed in action or seriously injured during such action and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI MANOJ KOTAK (MUMBAI NORTH-EAST): Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 107, Shri Rahul Kaswan – not present.
Item No. 108, Shri Rahul Kaswan – not present.

SECULARISM AND COMMUNAL HARMONY (PRESERVATION) BILL

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to ensure preservation of secularism and communal harmony in the country for a peaceful life to all communities irrespective of caste, religion or region.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to ensure preservation of secularism and communal harmony in the country for a peaceful life to all communities irrespective of caste, religion or region."

The motion was adopted.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 110, Shri Sushil Kumar Singh – not present. Item No. 111, Shri Tirath Singh Rawat – not present. Item No. 112, Shri Tirath Singh Rawat – not present. Item No. 113, Shri Jasbir Singh Gill – not present.

Dr. Shashi Tharoor.

ASYLUM BILL

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an effective system to protect refugees and asylum-seekers by means of an appropriate legal framework to determine claims for asylum and to provide for the rights and obligations flowing from such status and matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an effective system to protect refugees and asylum-seekers by means of an appropriate legal framework to determine claims for asylum and to provide for the rights and obligations flowing from such status and matters connected therewith."

The motion was adopted.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I introduce the Bill.

PRE-SCHOOL REGULATORY AUTHORITY BILL

SHRI MANOJ KOTAK (MUMBAI NORTH-EAST): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for constitution of a Pre-School Regulatory Authority to regulate the functioning of pre-schools in the country and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of a Pre-School Regulatory Authority to regulate the functioning of pre-schools in the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI MANOJ KOTAK (MUMBAI NORTH-EAST): Sir, I introduce the Bill.

SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO THE KORAPUT, BALANGIR AND KALAHANDI REGION OF THE STATE OF ODISHA BILL

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the Koraput, Balangir and Kalahandi (KBK) Region of the State of Odisha for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people, assistance for relief and restoration of damaged infrastructure in the State of Odisha due to recurrent natural calamities and for the development, exploitation and proper utilization of its resources.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the Koraput, Balangir and Kalahandi (KBK) Region of the State of Odisha for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people, assistance for relief and restoration of damaged infrastructure in the State of Odisha due to recurrent natural calamities and for the development, exploitation and proper utilization of its resources."

The motion was adopted.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 117, Shri P.P. Chaudhary – not present. Item No. 118, Shri P.P. Chaudhary – not present.

Shri Nihal Chand Chouhan.

राष्ट्रीय फसल बीमा आयोग विधेयक

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि फसलों के बीमा के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा आयोग के गठन और उससे संबन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of National Crop Insurance Commission for insurance of crops and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Item No. 120, Shri Malook Nagar – not present.

Item No. 121, Shri Malook Nagar – not present. Item No. 122, Shri C.P. Joshi – not present. Item No. 123, Dr. Thol Thirumaavalavan – not present. Item No. 124, Dr. Thol Thirumaavalavan – not present. Item No. 125, Dr. Thol Thirumaavalavan – not present. Item No. 126, Shri Kodikunnil Suresh – not present.

(1855/SM/SJN)

Dr. Sanjay Jaiswal – Not present

Shri Rajmohan Unnithan – Not present

Shri Malook Nagar – Not present

Shri Syed Imtiaz Jaleel.

REDUCTION OF FOOOD WASTAGE AND REDISTRIBUTION OF EXCESS FOOD BILL

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a legal framework for reduction of food wastage and redistribution of excess food and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for a legal framework for reduction of food wastage and redistribution of excess food and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Sir, I introduce the Bill.

अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (जनगणना एवं अन्य कल्याणकारी उपबंध) विधेयक

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की पृथक गणना और उनके कल्याण तथा समग्र विकास हेतु पृथक बजटीय आबंटन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for separate enumeration of persons belonging to the Other Backward Classes and the Economically Weaker Sections and provision of separate budgetary allocation for their welfare and overall development."

The motion was adopted.

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर मानदंड को हटाया जाना) विधेयक

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार और उसके स्थापनों के अंतर्गत सेवाओं और पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करते समय क्रीमी लेयर मानदंड हटाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for removal of creamy layer criteria while providing reservation in favour of Other Backward Class of citizens in services and posts under the Central Government and its establishments."

The motion was adopted.

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Schedule I.)

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005."

The motion was adopted.

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर) : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

BEGGARS (EMPLOYMENT SKILL DEVELOPMENT AND REHABILITATION) BILL

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to empower beggars to lead a with dignity life through skill development by imparting them compulsory vocational training and programmes for their rehabilitation and to enable them towards self-sustainable livelihood and the prevention of begging and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to empower beggars to lead a with dignity life through skill development by imparting them compulsory vocational training and programmes for their rehabilitation and to enable them towards self-sustainable livelihood and the prevention of begging and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I introduce the Bill.

RIGHT TO WORK BILL

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the right to work to every eligible citizen and for payment of allowance till such time as appropriate work is provided to every such citizen, constitution of Right to Work Fund, framing of Right to Work Insurance Policy and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the right to work to every eligible citizen and for payment of allowance till such time as appropriate work is provided to every such citizen, constitution of Right to Work Fund, framing of Right to Work Insurance Policy and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Amendment of the Preamble, etc.)

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI-NORTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI-NORTH): Sir, I introduce the Bill.

BUREAU OF ACCOUNTABILITY BILL

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI-NORTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of a Bureau of Accountability to suggest measures for rooting out corruption; making the administration efficient and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of a Bureau of Accountability to suggest measures for rooting out corruption; making the administration efficient and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI-NORTH): Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi Thangapandian – Not present

Shri Sunil Dattatray Tatkare – Not present

Shri Subrata Pathak – Not present

Shri Sudhakar Tukaram Shrangare – Not present

Dr. Mohammad Jawed.

(1900/KSP/YSH)

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

(*Omission of Section 124A*)

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Shri Rahul Kaswan – Not present

Shri Rajendra Agrawal	-	Not present
Shri Jugal Kishore Sharma	-	Not present
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	-	Not present
Shri Gajanan Kirtikar	-	Not present

शैक्षणिक संस्थाओं में भारत के ज्ञान, परंपराओं और प्रथाओं का अनिवार्य शिक्षण विधेयक

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत में विद्यालयी शिक्षा में कक्षा सात से दस तक सह-पाठ्यक्रम विषय के रूप में भारत के ज्ञान, परंपराओं और प्रथाओं के अनिवार्य शिक्षण का उपबंध करने, ताकि छात्रों को भारत की गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं को जानने और समझने तथा भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता की क्षमता को पोषित करने, सुदृढ़ करने और बनाए रखा जा सके, और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to provide for compulsory teaching of Knowledge Traditions and Practices of India as a co-curricular subject for classes seventh to tenth standard in school education in India in order to enable students to know and understand India's glorious culture and traditions and foster, strengthen and maintain Indian culture and its civilization strength and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

संसद सदस्य (खिलाड़ियों का अंगीकरण) विधेयक

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने और पदक प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य से दो खिलाड़ियों का अंगीकरण करने तथा ऐसे खिलाड़ियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और खेल उपकरण तथा अन्य खेल संबंधी सुविधाओं का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to provide for adoption of two sportspersons by every Member of Parliament from his constituency or State and provide such sportspersons with necessary training and sports equipment and other sports related facilities in order to enable them to participate and win medals in international sports events."

The motion was adopted.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

COMPULSORY TEACHING OF FINANCIAL EDUCATION BILL

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for imparting compulsory financial education to all citizens of the country in order to achieve higher financial literacy and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to provide for imparting compulsory financial education to all citizens of the country in order to achieve higher financial literacy and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): Sir, I introduce the Bill.

DIRECT CASH TRANSFER (FINANCIAL ASSISTANCE TO POOR HOUSEHOLDS) BILL

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of minimum rupees seventy-two thousand per annum as financial assistance by means of direct cash transfer to poor households for enhancement of livelihood and social security and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of minimum rupees seventy-two thousand per annum as financial assistance by means of direct cash transfer to poor households for enhancement of livelihood and social security and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Shri Hasmukhbhai Somabhai Patel - Not present; Dr. G. Ranjith Reddy.

ANDHRA PRADESH REORGANISATION (AMENDMENT) BILL
(*Amendment of Thirteenth Schedule*)

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014."

The motion was adopted.

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Dr. D. Ravikumar – Not present

Shri Vijaykumar (*alias*) Vijay Vasanth - Not present

Shri Rajendra Agrawal - Not present

Dr. Heena Vijaykumar Gavit

SCHEDULED TRIBES (RESERVATION IN POSTS AND SERVICES AND FILLING UP OF VACANCIES IN A TIME BOUND MANNER) BILL

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for reservation in posts and services under the Central Government and private sector for persons belonging to the Scheduled Tribes and timely filling up of vacancies meant for Scheduled Tribes to ensure their equal representation and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for reservation in posts and services under the Central Government and private sector for persons belonging to the Scheduled Tribes and timely filling up of vacancies meant for Scheduled Tribes to ensure their equal representation and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I introduce the Bill.

(1905/KKD/RPS)

PROVISIONS OF THE MUNICIPALITIES (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) BILL

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the extension of the provisions of Part IXA of the Constitution relating to the Municipalities to the Scheduled Areas.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the extension of the provisions of Part IXA of the Constitution relating to the Municipalities to the Scheduled Areas."

The motion was adopted.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I introduce the Bill.

CODE ON SOCIAL SECURITY (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 2, etc.)

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Code on Social Security, 2020.

HON. CHAIRPERSON: The Question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the Code on Social Security, 2020."

The motion was adopted.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of article 243c).

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Sir, I introduce the Bill.

NATIONAL URBAN EMPLOYMENT GUARANTEE BILL

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, I beg move for leave to introduce a Bill to provide for the enhancement of livelihood security of the poor households in Municipal areas of the country by providing at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every poor household whose adult members volunteer to do unskilled manual work and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the enhancement of livelihood security of the poor households in Municipal areas of the country by providing at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every poor household whose adult members volunteer to do unskilled manual work and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, I introduce the Bill.

वक्फ (संशोधन) विधेयक
(नई धारा 43क का अन्त:स्थापन)

श्री संजय भाटिया (करनाल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वक्फ अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Waqf Act, 1995.

The motion was adopted

श्री संजय भाटिया (करनाल): महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

PERSONS LIVING ON RIVERINE ISLANDS IN THE STATE OF ASSAM (WELFARE AND CENSUS) BILL

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA):Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for welfare and census of persons living on char or riverine islands in the State of Assam and issue of migration certificate to persons displaced from their place of residence in riverine island due to erosion caused by rivers flowing across the State of Assam and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for welfare nd census of persons living on char or riverine islands in the State of Assam and issue of migration certificate to persons displaced from their place of residence in riverine island due to erosion caused by rivers flowing across the State of Assam and for matters connected therewith. "

The motion was adopted.

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Sir, I introduce the Bill.

SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE FOR ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS IN THE STATE OF TAMIL NADU BILL

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Tamil Nadu to meet the costs of repairs, renovations and preservation of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains including excavation of new archaeological sites and remains situated in the State of Tamil Nadu.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Tamil Nadu to meet the costs of repairs, renovations and preservation of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains including excavation of new archaeological sites and remains situated in the State of Tamil Nadu."

The motion was adopted.

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I introduce the Bill.

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा 11 और 20 का संशोधन)

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960. "

The motion was adopted.

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(1910/RP/SPS)

INFANTS, CHILDREN AND YOUNG ADULTS (COMPREHENSIVE CARE AND PROTECTION) BILL

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide care and protection all infants, children and young adults and strengthen the existing social and legal provisions to improve the overall status and strengthen the multi-sectoral response to childhood abuse and gender-based violence and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB) The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide care and protection all infants, children and young adults and strengthen the existing social and legal provisions to improve the overall status and strengthen the multi-sectoral response to childhood abuse and gender-based violence and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item no. 173, Shri Srinivas Kesineni – not present.
Item No. 174 – Shri Dileshwar Kamait.

शहीद (पर्याप्त प्रतिकर की संदायगी) विधेयक

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय सशस्त्र बल, अर्द्धसैनिक बल, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य सशस्त्र पुलिस बल में अपने कर्तव्य क्रम में जीवन का बलिदान करने वाले दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त प्रतिकर की संदायगी का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for payment of adequate compensation by the Central Government to the dependents of deceased personnel of the Indian Armed Forces, Paramilitary Forces, Central Armed Police Forces and the State Armed Police Forces, who sacrifice their lives in the line of duty."

The motion was adopted.

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL,

(Insertion of new article 21B)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL,
(Insertion of new article 16A)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I introduce the Bill.

HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL
(Insertion of new section 7A)

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Hindu Marriage Act, 1955.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Sir, I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 181, Shri Bidyut Baran Mahato – not present.
Item No. 182 - Shri Arvind Sawant.

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL
(Amendment of section 166)

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860."

The motion was adopted.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I introduce the Bill.

NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES (AMENDMENT) BILL
(Amendment of section 2, etc.)

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985."

The motion was adopted.

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(Substitution of new article for article 85, etc.)

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, I introduce the Bill.

धरोहर शहर और स्थल (संरक्षण और विकास) विधेयक

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि धरोहर शहरों और स्थलों की ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखकर और अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू पर्यटन का संवर्धन करके तथा उनके ऐतिहासिक महत्व का पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं और ऐसी अन्य सामग्री के माध्यम से प्रकाशन करके तथा समग्र विकास के लिए धरोहर शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में घोषित करके उनका संरक्षण और विकास करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the conservation and development of heritage cities and sites by way of retaining their historical identification and promoting international and domestic tourism and publishing their historical importance through booklets, pamphlets and such other material and for declaring heritage cities as smart cities for overall development and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर) : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

(1915/RAJ/NKL)

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य, पेयजल और चारा की पूर्ति का अनुरक्षण विधेयक

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कि केंद्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय उपभोग के लिए खाद्य और पेयजल की तथा कृषकों के पशुधन के लिये चारा की अनिवार्य पूर्ति बनाये रखने और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the compulsory maintenance of food and potable water supplies for human consumption and fodder for the livestock of the farmers in drought affected areas by the Union Government in consultation with the Government of the State concerned and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

व्यथित विधवाएं और एकल महिलाएं (संरक्षण, पुनर्वासन और कल्याण) विधेयक

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि व्यथित, अशक्त, उपेक्षित और अन-अंगीकृत विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए कल्याण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता, पेंशन, चिकित्सा देखरेख, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करके ऐसी विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यकता आधारित पुनर्वासन और कल्याण सहित संरक्षणकारी उपायों तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the protective measures with need based rehabilitation and welfare to be undertaken by the Government for the distressed infirm, neglected, and disowned widows and single women by providing financial assistance, pension, medical care, housing and other facilities through a Welfare Board to such widows and single women and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक
(धारा 2 का संशोधन आदि)

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.”

The motion was adopted.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

समान सिविल संहिता विधेयक

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for uniform civil code for all citizens of the country and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS – Contd.

1919 बजे

HON. CHAIRPERSON: Now, we come back to the deliberation.

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki, you may continue.

1919 बजे

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, मैं कोरोना महामारी के बारे में बात कर रहा था। हमारी सरकार और यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने उससे देश को किस प्रकार से बचाया है। नरेन्द्र भाई मोदी जी की अगुवाई में कोरोना महामारी के प्रति जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें चाहे डॉक्टर्स हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज हों या वैज्ञानिक हों, उन सभी को प्रोत्साहन दिया गया। उस वक्त नरेन्द्र मोदी जी ने दीया जलाने, ताली मारने और लोगों को आह्वान किया था। मुझे याद है कि सभी बड़े-बड़े नेता और सभी सामान्य जन आह्वान पर आगे आए थे और उन्होंने यह कार्य किया था।

(1920/VB/MMN)

मुझे बहुत खेद है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि विपक्ष के लोगों ने उसका मजाक उड़ाने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि यह प्रक्रिया करने से कोरोना कैसे भाग जाएगा। मगर नरेन्द्रभाई की सोच से वे कई योजन दूर थे। श्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच थी कि अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती है, उसमें जनभागीदारी को जोड़ने के लिए लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए उन्होंने यह कार्य किया था और इसकी वजह से कोरोना की लड़ाई में जनभागीदारी सम्मिलित हुई और इसका जो परिणाम आया, चाहे वे कोरोना वॉरियर्स हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे हमारे देश के नागरिक हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि नरेन्द्रभाई मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर 'सेवा ही संगठन' के माध्यम से हमारे लोग पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना के मरीजों को और जो लोग भूखे थे, उनको भोजन कराने के लिए आगे आए थे और इस संयुक्त प्रयास से हमने कोरोना की लड़ाई को बहुत ही सफलतापूर्वक लड़ा है।

हमारे देश में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज थीं, वे लिमिटेड थीं। मगर विदेश के जो बड़े-बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप के देश हों, उनके यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही अच्छा था। मगर ऐसे देश भी लड़खड़ा गए थे। उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, उनके नेतृत्व में जो काम किया गया, उसकी वजह से पूरे देश में एक उत्साह आया और हमने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी। श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने लॉकडाउन जैसे निर्णय लिए। 135 करोड़ की जनता वाले बड़े देश में और विविधाओं वाले देश में लॉकडाउन लगाने का जो कार्य किया गया, उसे लोगों ने स्वीकार किया। एक राजनेता की, देश के एक नेता की लोगों में कितनी प्रतिष्ठा है, इससे हमें इस बात का पता चलता है।

लोगों ने लॉकडाउन को स्वीकार किया। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाना आदि के लिए भी जनभागीदारी से जोड़ा गया, इससे हमें बहुत सफलता मिली है। कोरोना की लड़ाई में श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, वह वैक्सिनेशन की उपलब्धि है। माननीय सभापति जी, मैं स्वयं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मुझे पता है कि ऐसी महामारी, ऐसी असामान्य महामारी, ऐसी अनप्रिसिडेंटेड महामारी को हमने अपने कार्यकाल में नहीं देखा था। मुझे पता है कि पहले जब कोई महामारी आती थी, स्मॉल पॉक्स आई थी, ऐसी ही अनेक महामारियाँ आई थीं, उस समय जो वैक्सीन आया था, वह निश्चित रूप से विदेश में बना था। उसे हमारे देश में आते-आते लगभग 40-50 साल लग गए थे। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का गौरव है कि नरेन्द्रभाई मोदी जी की अगुवाई में देश के वैज्ञानिकों ने अपने ही देश में दो टीके बनाए। इन टीकों की वजह से, जिन गिने-चुने देशों ने टीके बनाए थे, उनमें से भारत भी एक देश था। मुझे इस बात का गर्व है कि पहले हमारे यहाँ कोई टीका नहीं बनता था। आज भारत ने टीका बनाकर पूरे विश्व को बता दिया है कि नया भारत क्या है। हमारे लोग कभी क्रिटिसिज्म करते हैं कि नया भारत क्या है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भारत में ही बने हुए टीके से देश के 150 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाता है, जो विभिन्न स्थानों पर की जाती है, दुर्गम स्थानों पर की जाती है। जंगलों में, पर्वतों पर, पहाड़ियों पर लोग रहते हैं, सुदूर स्थानों और मरुभूमि में लोग रहते हैं, ऐसी सभी जगहों पर जाकर देश के स्वास्थ्यकर्मियों ने लोगों का टीकाकरण किया। यह विश्व की सबसे बड़ी टीकाकरण की योजना थी। इसके लिए नरेन्द्रभाई मोदी जी की सरकार और नरेन्द्रभाई मोदी जी अभिनन्दन के पात्र हैं।

बच्चों के टीकाकरण के लिए भी हमारे यहाँ के टीके को मान्यता मिली है। मैं मानता हूँ कि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कई सिलेक्टेड लोग हैं, चाहे वे कोरोना वॉरियर्स हों, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हों, जिनको डायबिटीज या अन्य बीमारियाँ हों, ऐसे लोगों को तीसरा टीका देने का काम मोदी सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि हमें एक अप्रत्याशित सफलता मिली है।

(1925/PC/VR)

हमारे यहां पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, जिसमें सब लोग बहुत हैल्पलेस महसूस करते थे। तब मोदी सरकार ने हॉस्पिट्ल्स में ऑक्सीजन पहुंचाई, वेंटिलेटर्स पहुंचाए, लोगों को रेमडिसीवर और ऐसे कई अन्य इन्जैक्शन्स पहुंचाए। इन सब कार्यों को करने के लिए देश मोदी सरकार का ऋणी रहेगा। जिस प्रकार तीसरी लहर, ओमीक्रॉन की लहर आई, ओमीक्रॉन की इस लहर में भी पॉज़िटिव केसेज़ की संख्या भारी मात्रा में है, जैसे दूसरी लहर में थी। लेकिन उसकी जो सीवियेरिटी है, जो इंटेंसिटी है, वह बहुत ही कम मात्रा में है। कोरोना का मरीज चार से पांच दिनों में सिम्पटम्स-फ्री हो जाता है। न मरीजों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और न ही उनको हॉस्पिटलाइज़ेशन की जरूरत पड़ती है। बहुत कम लोगों को आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ती है। इस स्थिति के लिए अगर किसी को हम श्रेय दे सकते हैं, तो हमारे टीकाकरण अभियान को दे सकते हैं।

हमारे देश में इतने सारे लोगों को टीका लगाया गया, जिसके कारण आज ओमीक्रॉन की तीसरी लहर आने के बावजूद बहुत ही कम मात्रा में मोर्टेलिटी हुई है, फ्रेलिटी हुई है और कम मात्रा में लोगों को ऑक्सीजन और वेंटीलेटर्स की जरूरत पड़ी है, इसके लिए अगर किसी को इसका श्रेय जाता है, तो हमारे टीकाकरण अभियान को जाता है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हमारे देश के सभी लोगों को देश में बना हुआ टीका लगा। सही मायने में अगर आत्मनिर्भर भारत की अगर कोई पहचान है, तो हमारे देश में बने हुए दोनों टीके आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन गए हैं।

पूरे विश्व में इसकी सराहना हो रही है। कोविड का अलग-अलग वेरिएंट आता है। मुझे पूरा यकीन है कि इन वेरिएंट्स के आने के बाद भी हमारे यहां जो रोबस्ट टीकाकरण हुआ है, वह दूसरे देशों की तुलना में कई गुना बेहतर है। अमेरिका जैसे देश में भी संख्या की दृष्टि से इतने टीके नहीं लगे हैं, जितने टीके हमारे यहां लगे हैं। परसेंटेज के हिसाब से भी हमारे यहां बहुत ज्यादा लोगों को टीका लगा है और यह टीकाकरण हमारे लिए बहुत ही सफल रहा है। देश बच गया है, यह नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण है, उनके मार्गदर्शन के कारण है और उन्होंने हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को जिस तरह इनकरेज किया, उसके कारण हुआ है।

अभी भी कोरोना की महामारी चल रही है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन' लॉन्च किया है। आने वाले समय में, जिस प्रकार यह महामारी हमारे सामने आई है, इसी प्रकार की कोई अलग महामारी या वायरस आ सकता है। प्रधान मंत्री जी ने जब 'प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन' उद्घाटन किया था, जब इसका लोकार्पण किया था, तब उन्होंने स्वस्थ और समृद्ध देश का नारा दिया था। इस नारे को चरितार्थ करने के लिए पूरे भारत में पैन-इंडिया हैल्थ अम्ब्रेला सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या डिजिटल स्वस्थ्य सेवाएं हों, इनके लिए प्रधान मंत्री जी ने 64,180 करोड़ का बहुत बड़ा आवंटन किया है। इसकी वजह से देश का हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होगा। प्रधान मंत्री जी का यह फैसला सबसे बड़ा है।

देश में आयुष्मान भारत की 1,50,000 लेबरॉट्रीज़ स्थापित की गई हैं। आयुष्मान भारत के जो वेलनेस सेंटर्स, लेबरॉट्रीज़ और क्लीनिक्स स्थापित किए गए हैं, इनमें से 79,000 आज की डेट में ऑलरेडी फंक्शनिंग हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेजेज़ बनाने का सरकार ने, प्रधान मंत्री जी ने जो निर्णय लिया, इसकी वजह से अब तक 157 मेडिकल कॉलेजेज़ सैंक्शन होने का कार्य हो चुका है। ट्रेन्ड वर्कफोर्स फॉर पब्लिक हैल्थ इमरजेंसी के लिए भी प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। देश में 22 एम्स का निर्माण करने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है, जिसमें से 7 एम्स आज कार्यरत हैं। शॉर्ट समय में सारे 22 एम्स चालू हो जाएंगे, जिससे पूरे देश में हमें रोबस्ट हैल्थकेयर सिस्टम हमें मिलेगा।

(1930/CS/SAN)

देश में लैबोरेटरीज की श्रृंखला खड़ी की है। उनमें ब्लॉक लेवल पर 134 प्रकार के डिफरेंट टेस्ट नि:शुल्क किए जाएंगे तथा देश की हेल्थ सुविधा के लिए 602 जिलों में क्रिटिकल केयर सेंटर खोले जाएंगे। आने वाले समय में कोई और महामारी आए तो उसके लिए भी देश में स्वास्थ्य सुविधा को सुनिश्चित करने का काम माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। अगर मैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करूँ तो इसके तहत पूरे देश का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा और देश के सभी अस्पताल डिजिटली कनेक्ट होंगे। एक व्यक्ति, चाहे वह तमिलनाडु का हो, अगर वह उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में आता है तो उसके डिजिटल आईडी की वजह से उसका रिकॉर्ड देश के किसी भी कोने में देखा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन मेडिकल के क्षेत्र में हुई है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे हेल्थ मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी ने जो इंक्लूसिव हेल्थ मॉडल सुनिश्चित किया है, इससे भी देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारा कार्य किया है, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह सफाई अभियान हो, चाहे वह शौचालय हो, ऐसी अन्य योजनाएं है, लेकिन मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में जन-धन खातों की शुरूआत करवाई थी। हमारे विपक्ष के कई लोग इस बात की हँसी उड़ाते थे। उनको पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी ने इसको किस मंशा के साथ चालू किया था। आज करीबन 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के नि:शुल्क जन-धन खाते खुलवाए गए हैं। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। उन खातों में डीबीटी के ट्रांसफर से करीबन 200 से ज्यादा अलग-अलग तरह की सहायताएं, चाहे वह छात्रवृत्ति हो, चाहे फर्टिलाइजर का पैसा हो, चाहे कोई सब्सिडी देनी हो, मनरेगा का वेतन देना हो, उसे उन खातों में ट्रांसफर करते हैं। एक प्रधानमंत्री जी ने सदन में पहले ऐसा बोला था कि जब मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ तो उसमें से करीबन 85 पैसे बीच में घिसा जाता है और लाभार्थी के हाथ में मात्र 15 पैसा जाता है। आज डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने बिचौलियों का सफाया किया है। प्रधानमंत्री जी अब एक रुपया भेजते हैं तो लाभार्थी के खाते में 100 पैसे जमा होते हैं। उसका शत-प्रतिशत लाभ लाभार्थी को होता है। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

हमारे एक कांगेस के मित्र दो दिन पहले, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने दो बातें कीं, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि यहाँ दो इंडिया हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि भारत को तोड़ने की बात न करो, भारत को जोड़ने की बात करो। हजारों साल से भारत 'एक भारत' है और उसको तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने दूसरी बात किंग और राजशाही की बात कही थी। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पहले जब राजशाही थी तब राजा रानी की कोख से पैदा होता था, उसकी कोख से पैदा होता था।

बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को एक रोबस्ट संविधान दिया है और उस संविधान के तहत देश में लोकतंत्र बढ़ रहा है, पल-पोस रहा है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या कोई भी चुने हुए प्रतिनिधि हों, वे बैलेट के जरिए चुनकर आते हैं, वे कभी कोई रानी की कोख से पैदा नहीं होते हैं। नरेन्द्र भाई मोदी जी ने अपने नेतृत्व के सहारे वर्ष 2014 हो या वर्ष 2019 हो, बहुत बड़ी, भारी जीत हासिल की थी। जब वे लोकतंत्र के मंदिर में आए थे तो उन्होंने यहाँ माथा टेका था। मैं विपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार की बेहूदा बातें न की जाएं। मैं एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

"कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले,
मेहनत तय करेगी कि यह आसमान किसका है।"

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब): श्री हनुमान बेनिवाल।

आपके शुरू करने से पहले मैं हाउस को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हरेक राजनीतिक दल का जो समय निर्धारित हुआ था, वह खत्म हो चुका है। बाकी जो इनडिपेन्डेंट हैं, उनके लिए पाँच-पाँच मिनट का समय दिया जाता है। फिर भी कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने सबको पाँच-पाँच मिनट में अपना वक्तव्य रखने के लिए कहा है। इस हिसाब से आज यह चर्चा हम समाप्त करेंगे। इसके लिए सबके सहयोग की कामना है।

(1935/KN/SNT)

1935 बजे

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): महोदय, मुझे समय थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। मैं रात को लास्ट तक बैठता हूं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब): आपको पाँच मिनट प्लस वन छ: मिनट का समय दिया जाता है। आपको एक मिनट और ज्यादा मिलेगा। आप शुरू कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

महोदय, अभिभाषण किसी भी सरकार के विजन का आईना होता है और सरकार की रीति, नीति तथा कार्यों को लेकर अभिभाषण में जो बातें कही जाती हैं, उससे हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के विजन को समझने में तथा सरकार के कार्यों को मानने में आसानी होती है। मगर इस अभिभाषण के अंदर राष्ट्रपति महोदय ने 82 बिंदुओं के माध्यम से जो बातें कही हैं, उनमें ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हुआ। क्योंकि जो विषय सरकार की कमी, खामी या नाकामी का हिस्सा थे, उनका कोई जिक्र इसके अंदर नहीं किया गया।

महोदय, वर्ष 2047 के शताब्दी वर्ष की बात इस अभिभाषण के अंदर सरकार ने कही है लेकिन देश का पिछड़ा वर्ग गरीब, दलित, अल्पसंख्यक तो आज भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की स्थिति क्या है, यह आपको भी पता है और देश के लोगों को भी सच्चाई मालूम है। यहां तक देश का गरीब, वंचित, पिछड़ा वर्ग कैसे आगे पहुंचेगा, क्या इसका विजन आपके पास है? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप जिस आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, वह आजादी देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पा रही है? आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है? जिस उत्तर प्रदेश का आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, वहां चुनाव है। आप वहां जाकर देखिए कि क्या स्थिति है? आज भी वहां के गरीबों के वोट, उनके अधिकार कुछ खास लोगों के द्वारा ही तय किए जाते हैं कि किसको मतदान करेंगे? आज भी उन लोगों को आजादी का मतलब तक नहीं पता है।

महोदय, कोरोना के संकट काल में देश को बचाने के लिए कोरोना योद्धाओ ने काम किया है। तीसरी लहर भी चली गई है और हिन्दुस्तान के अंदर ईश्वर की कृपा रही है कि बड़ा बलिदान देने के बाद भी हम अभी सेफ साइड के अंदर हैं। मैं उन कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देता हूं और साथ ही इस जंग में जो दिवंगत हो चुके हैं, उन नागरिकों को, भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

महोदय, अभिभाषण में कोरोना की स्थिति और देश की स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र हुआ है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए इंतजाम नाकाफी थे। पूरे अस्पताल के तीन से पाँच प्रतिशत बेड इमरजेंसी विभाग में हैं और कोरोना संक्रमण के दौर में आई इस रिपोर्ट का खास महत्व है।

क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर अस्पताल डाक्टरों, विशेषज्ञों और नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। साथ ही अन्य संसाधनों का अभाव है और इसका असर मरीजों और खासतौर से आपात सेवाओं पर भी पड़ रहा है। महोदय, मेरी मांग रहेगी कि अस्पतालों में अविलंब मानव संसाधनों की कमी को पूरा करने की जो जरूरत देश में थी, उसको वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल में प्रमुखता दे और खाली पदों को भरे। अस्पतालों के अंदर जो भी आधुनिक संसाधन हैं, उनको लेकर और आम जन को बचाने के हिसाब से सारा काम सरकार करे। जब कोरोना की सैकेंड लहर आई थी, तब ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर और आईसीयू वार्ड के अभाव में भी हजारों जानें इस देश के अंदर गई थीं।

महोदय, संविधान, आरक्षण और दलित अत्याचार के संबंध में बिंदु संख्या 14 में राष्ट्रपति जी ने संविधान के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके आदर्शों का ज़िक्र तो किया, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों को खत्म करना क्या आरक्षण को खत्म करना नहीं है? चूंकि आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में है, इसलिए सरकारी नौकरियों में कटौती का मतलब आरक्षण का कमजोर होना भी है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार वंचित वर्गों के साथ अन्याय कर रही है। अगर हम नौकरियों की घटती संख्या, सरकारी क्षेत्र के निजीकरण और नौकरशाही में हो रही लैट्रल एंट्री में आरक्षण की अनदेखी को मिलाकर देखें तो यह कहा जा सकता है कि वास्तव में आरक्षण ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है, जहां इसके होने या नहीं होने में खास अंतर नहीं रह जाएगा।

महोदय, अभिभाषण में स्वाधीनता, समानता तथा भाई-चारे का जिक्र किया गया है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि देश में उत्तर प्रदेश, बिहार और मेरे राजस्थान राज्य में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, वे चिंताजनक हैं। ऐसे में सरकारों को आजादी के दशकों बाद भी दलित उत्पीड़न के मामलों पर लगाम लगाने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकताएं थी। मगर ये आवश्यकताएं पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं आ पा रही हैं।

महोदय, देश में किसानों का जो हाल है, वह आपसे छिपा नहीं है। बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर हुआ और 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। बाद में सरकार ने तीनों कृषि बिल भी वापस लिए। मैं यह नहीं समझता कि जिन किसानों ने, जिन जवानों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधान मंत्री के पद पर बैठाया, भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट्स देकर अकेले बहुमत दिया, उसके बावजूद भी किसानों को भूल कैसे रहे हैं, जवानों को भूल कैसे रहे हैं? मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि बिंदु संख्या 22 से 29 तक कृषि से जुड़े मामलों का बखान किया गया। पिछले साल हमने देखा कि सरकार ने यह स्वीकार किया कि हमारी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई। तपस्या तो सरकार कर रही थी और इस तपस्या में वह स्वाह: किसानों को कर रही थी। 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत को बिना स्वीकारे सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। मगर किसान आंदोलन के दौरान सरकार की जो हठधर्मिता सामने आई, उसे पूरा देश जानता है।

(1940/GG/SRG)

सभापित महोदय, प्रधान मंत्री जी ने का कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे और किसान इन पर भरोसा कर के दो बार इनको सत्ता के अंदर ले कर आए। मैं सदन को यह याद दिलाना चाहूंगा कि इसी सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का टारगेट निर्धारित किया था। लेकिन इनके वादे और जमीनी हकीकत की खाई ने भारत के किसानों के संकट को ही दुगुना कर दिया। एनएसएसओ की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में किसान परिवारों की वार्षिक कृषि आय में वर्ष 2002-03 के बीच औसत वृद्धि लगभ 20 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2012-13 से 2018-19 के बीच लगभ 12 प्रतिशत तक गिर गई। यह भी तब जब कृषि की अनुमानित विकास दर 4.5 प्रतिशत है।

सभापति महोदय, किसान आत्महत्या कर रहा है। वर्ष 2021 में आए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में किसान आत्महत्याओं में वृद्धि दर्ज की गयी है। यहां पर पीएम किसान योजना का उल्लेख कई बार किया गया है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि देश में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों की आत्महत्याओं में भी 18 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गयी, जिन्हें पीएम किसान जैसी योजनाओं के लाभ से बाहर रखा गया है। किसान आत्महत्या के आंकड़े इन बहुतप्रचारित योजनाओं के लिए आइना हैं और सच्चाई को उजागर करते हैं कि छोटे और सीमांत किसान अपनी गिरती आय और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण खुद को मार रहे हैं। जब परसों राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने बहुत कुछ कहा। लेकिन मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि देश की संसद में सरकार द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मेरे राजस्थान के किसानों पर 1 लाख 20 हजार 979 करोड़ रुपये का कृषि कर्ज बकाया है। राजस्थान में राहुल गांधी जी जब वर्ष 2018 के राजस्थान के चुनावों में गए तो कहा कि दस दिन में संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस की सरकार भी बन गई और 10 दिनों में कर्ज माफी की बात तो छोड़ो अभी पिछले दिनों किसानों की जमीनें कुर्क करने के लिए वहां इनकी टीमें पहुंच गई थीं और आनन-फानन में इनको अपने आदेश वापस लेने पड़े और वे दस दिन आज तक पूरे नहीं हुए।

सभापति महोदय, वर्ष 2021 में डीएपी की कीमतों में 58 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई। ट्रैक्टरों पर जीएसटी 12 प्रतिशत है, प्लास्टिक पाइपों पर जीएसटी 18 प्रतिशत है। कृषि उपकरणों पर जीएसटी अभी 12 से 18 प्रतिशत है। इतना टैक्स कृषि आय को दिन प्रति दिन कम करता जा रहा है।

गिरती आय और बढ़ती लागत के इस दौर में गांव देहात का एक गरीब किसान अपना जीवन-यापन कैसे करेगा यह सोचने विषय है।

सभापित महोदय, अभी जब किसान आंदोलन समाप्त हुए, तब एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून की बात भी किसान संगठनों ने सरकार से की थी। किसानों के भारी आंदोलन के बाद कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया और प्रधान मंत्री जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मुद्दों की जांच के लिए एक समिति के गठन का वादा किया था। उचित एमएसपी तय करने से किसानों की आय में सुधार होगा। लेकिन अभी भी इस समिति का गठन होना बाकी है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब): बेनिवाल जी, छह मिनट हो गए हैं।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): गन्ना ही नहीं, गेहूं और धान की एमएसपी खरीद के आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में साल 2021-22 में करीब 34 लाख कम किसानों से खरीद की है यानी लाभार्थी किसानों की संख्या घट गई है, जिसकी वजह से करीब 78 लाख मीट्रिक टन अनाज की कम खरीद हुई और सरकार को करीब 11 हजार करोड़ रुपये कम खर्च करने पड़े। इसलिए किसान को सशक्त बनाने के लिए एमएसपी पर काननू बनाने तथा एमएसपी पर किसान की पूरी उपज खरीदने की नीति बनाने की आवश्यकता है। अभी 25 क्विंटल खरीद का राइडर लगा हुआ है। साथ ही मेरे प्रदेश राजस्थान में सिंचित क्षेत्र को विकसित करने की जरूरत है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत है।

सभापित महोदय, मैं युवाओं पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। हाल ही में रेलवे भर्ती मे शामिल युवाओं ने उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया, जिन पर पुलिस ने खूब लाठियां भांजी और कई युवा घायल हुए। कुछ ऐसी स्थिति बिहार में रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षा व परिणाम में हुई तथा कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बनी।

वर्ष 2019 में 35 हजार नौकरियों के लिए सवा करोड़ युवाओं ने अप्लाई किया। तीन साल के बाद भी इन युवाओं को नौकरी कहीं दूर-दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। ऊपर से अपना हक मांग रहे गरीब परिवारों से आ रहे युवाओं को ही बेरहमी से पीटा गया।

सभापति महोदय, देश में रोज़गार की हालत यह है कि केवल केंद्र में 8.72 लाख पद खाली पड़े हैं, वहीं केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली भर्तियों जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईएम, आईआईटी, पीएसयू बैंकों में पौने चार लाख भर्तियां खाली हैं। यह हमारे देश के मध्यम वर्ग से आने वाले युवाओं से सबसे बड़ा विश्वासघात है कि उन्हें नौकरी लेने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा है, नौकरी तो बहुत दूर की बात है।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि देश में राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं में बेरोज़गारी के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे अत्यंत भयावह हैं। मेरे राजस्थान की अगर बात करूं तो एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार हर दूसरा ग्रेजुएट युवक राजस्थान के अंदर बेरोजगार है। 20 लाख से अधिक युवा राजस्थान में तो बिहार, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हर तीसरा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। देश की हर पांचवी शहरी महिला बेरोजगार है। ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार देने के ठोस उपाय का कोई विजन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नजर नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति: ठीक है, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): सर, मैं एक-डेढ़ मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं राजस्थान के प्रमुख मामले के बारे में कहना चाहता हूँ। राजस्थान का युवा आंदोलित है।

(1945/RV/AK)

महोदय, राजस्थान प्रांत के अन्दर भर्तियों में बड़ी धांधली हो रही है। हर पेपर आउट हो रहा है। कल भी यह मामला यहां उठा था। लगातार आउट हो रहे पेपर से बेरोजगारों में व्याप्त आक्रोश व बेरोजगारों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान की रीट, 2021 की भर्ती हुई और एक संगठित गिरोह ने राजस्थान की सरकार के जिम्मेदारों के संरक्षण में पेपर आउट किया। दुर्भाग्य इस बात का है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के जिन जिम्मेदारों की भूमिका परीक्षा को करवाने की थी, उन्हीं जिम्मेदारों ने पेपर आउट करवाया।

सभापति महोदय, राजस्थान रीट के मामले में पेपर आउट होने के बाद बोली लगी। पाँच करोड़ रुपये तक पेपर बिका और जिसने जितनी ज्यादा रकम लगाई, उसको पेपर पहुंचा। आर.बी.एस.ई. द्वारा शिक्षा संकुल में गैर सरकारी व्यक्तियों को पेपर की निगरानी के लिए नियुक्त कर देना और राजस्थान की जांच एजेंसी एस.ओ.जी. द्वारा यह स्वीकार करना कि शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ है, जो यह इंगित करता है कि राजस्थान सरकार में बैठे मंत्रियों, अधिकारियों एवं सी.एम.ओ. की शह के बिना यह असंभव था, संभव नहीं था। इस पूरे मामले में एक बात यह भी सामने आई कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जिन्हें राजस्थान में रीट परीक्षा में अहम जिम्मेदारी मिली थी, वे कांग्रेस की राजीव गांधी स्टडी सर्कल संस्था में सदस्य और पदाधिकारी हैं, जिसके संरक्षक राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत और नेशनल को-ऑर्डिनेटर मंत्री सुभाष गर्ग हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष डी. पी. जारोली सदस्य और रीट, जयपुर को-ऑर्डिनेटर पराशर संस्था के जयपुर रिजन को-ऑर्डिनेटर हैं।

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब): आपकी सारी बात आ गई है। बस आप लास्ट लाइन बोल दीजिए।

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): महोदय, एस.ओ.जी., राजस्थान सरकार की एजेंसी है, इसलिए पर्दे के पीछे जो असली मगरमच्छ हैं, उन्हें वह नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि पेपर जब आउट हुआ, तब राजस्थान सरकार के जिम्मेदार यह दावा कर रहे थे कि पेपर आउट हुआ ही नहीं, इसलिए इस मामले की सी.बी.आई. जांच जरूरी है। चूंकि पेपर को एक संगठित गिरोह ने बड़ी रकम लेकर कई लोगों को बेचा, इससे साफ जाहिर है कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि दिल्ली की सरकार इसके अन्दर इंटरफेयर करे। इस 'रीट' को रद्द करे। इसकी सीबीआई जांच करे और जारोली को केवल बर्खास्त करने से नहीं होगा, उसे गिरफ्तार करे।

सभापति महोदय, मुझे मेरी बात समाप्त करने दें। दस साल पहले 'आर. टेट' के पेपर जिस फर्म से छपवाए गए थे, उसी फर्म से इस बार भी छपवाए गए। गड़बड़ी उस समय भी हुई। उसके बावजूद भी एजेंसी को फिर से प्रिंट का जिम्मा दे दिया गया। फिर राजस्थान के किस अधिकारी ने उसी फर्म को यह काम दिलवाया, यह जांच का विषय है क्योंकि इस पूरे मामले में वित्तीय घोटाला भी हुआ है क्योंकि इस फर्म को 130 करोड़ रुपये के आस-पास की राशि का भुगतान किया गया।

माननीय सभापति : हनुमान जी, आपको बोलते हुए 11-12 मिनट हो गए हैं। आपकी सारी चीजें आ गई हैं।

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): महोदय, मैं बस अंतिम में बोल देता हूं।

महोदय, इसी प्रकार वर्तमान राजस्थान सरकार के कार्यकाल में पाँच बड़ी भर्ती परिक्षाएं हुईं। पाँचों परीक्षाओं के पेपर आउट हुए। तमाम कोशिशों के बावजूद नकल गिरोह पर शिकंजा नहीं कसा जा सका, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है।

HON. CHAIRPERSON: Now, I am calling the next speaker.

… (*Interruptions*)

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): महोदय, मुझे एक मिनट का समय दें। मुझे पूरी बात कहने दें।

माननीय सभापति : आपकी पूरी बात आ गई है।

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): महोदय, मुझे बस आधा मिनट का समय दें। मैं अपनी बात बस आधे मिनट में बोल दूंगा।

माननीय सभापति : ठीक है, आधा मिनट मतलब आधा मिनट।

कल एक मिनट में क्या हुआ, आपको उसकी जानकारी है और आप आधा मिनट मांग रहे हैं। आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए हैं।

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): सर, मैं वह नहीं हूं। मैं तो आपकी बात मानकर बैठ जाऊंगा। आप बैठे हैं तो हमें आधे मिनट का समय और मिल जाएगा। मैं बस लास्ट वर्ड कहकर समाप्त कर रहा हूं।

राजस्थान एस.आई. भर्ती परीक्षा, नीट-2021, जे.ई.एन. भर्ती परीक्षा – 2021, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड-3 परीक्षा के बाद अब सबसे बड़ी परीक्षा रीट का पेपर आउट हो जाना इस बात का संकेत है कि सरकारी संरक्षण में बड़ा खेल राजस्थान में खेला जा रहा है। राजस्थान सरकार, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से लेकर परिणाम तक भ्रष्टाचार से अछूते नहीं रहे और आर.पी.एस.सी. के एक अध्यक्ष जेल तक जा चुके हैं और न केवल वर्तमान राजस्थान के शासन काल में, बल्कि इससे पूर्व की सरकार के समय भी भर्तियों में जमकर धाँधली हुई, मगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मैं चाहता हूं कि ठोस कानून इन नकल गिरोहों के खिलाफ बने और ऐसे मामले में भर्तियां रद्द हों और सीबीआई जांच हो।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इसकी जांच सीबीबाई को दे। मगर वह नहीं देगी क्योंकि उनका पूरा ग्रुप, मंत्री, आई.ए.एस., सी.एम.ओ. सारे इसमें इंवॉल्व्ड हैं। हम चाहते हैं कि आप दिल्ली से टीम भेजकर गवर्नर से रिपोर्ट मंगाएं। संसदीय समिति वहां जाए और सारी भर्तियां, जिनके-जिनके पेपर आउट हुए हैं, उन्हें रद्द करवाकर नौजवानों को नए सिरे से रोजगार दें, यह मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब): एक व्यतिक्रम है। मैं हाउस का सेंस लेना चाहता हूं।

हमारे एक ऑनरेबल मेम्बर was not present when Private Member's Bills were being introduced. If the House allows, I will call him and subsequently we will go into the debate on the President's Address.

Shri P. P. Chaudhary -- Item No. 45.

Constitution (Amendment) Bill

(Amendment of article 51A)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I introduce the Bill.

Constitution (Amendment) Bill

(Amendment of article 124)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I introduce the Bill.

(1950/SPR/MY)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of article 124)

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I introduce the Bill.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS – Contd.

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Navaskani in Tamil,
please see the Supplement. (PP 374A to 374C)}

1959 बजे

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): चेयरमैन सर, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। There is not a single sector which is not under stress because of the policies of the Government and the Presidential Address of this year was the advertisement of high-level … *(Not recorded)* where the Government has tried to paint a rosy picture of the economy and the condition of the country. The Address has missed out several important issues which are plaguing the country today.

1959 बजे (श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

There is no mention about the job losses, adverse impact of coronavirus, migrant labour crisis, falling GDP, escalation on the border by China which is resulting in deaths of our soldiers, protests, deaths of our farmers and increasing inequality.

(2000/NK/KMR)

The Prime Minister during his 2014 election campaign had said: बहुत हुआ जनता पर पेट्रोल का वार, अबकी बार मोदी सरकार, India's wholesale inflation has risen at the fastest pace in three decades on input costs fuelled by high commodity prices and supply constraints. Wholesale prices rose 14.2% in November from a year earlier as per data released by the Commerce Ministry, which is at the highest level since December 1991 when it was 14.3 per cent.

In a reply given in the Lok Sabha, the Government has stated that revenue generated by taxation is used for the development schemes of the Government and also to provide relief to the poor during the pandemic period by schemes like Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) under which free ration was provided to 80 crore beneficiaries. What is the price of groundnut oil? It was Rs.150.5 per litre a year ago and now it has gone up to Rs.177.91 per litre. The Price of mustard oil rose from Rs.126.17 to Rs.172.55. Prices of palm oil, vanaspati, and every household item have increased.

One of the Ministers in the Government said that they imposed taxes to provide free vaccines to the people. I would ask the Government why they are advertising free vaccines and free food for the poor when in reality they are charging high taxes on petrol and diesel which are being paid by the poor sections of the society. आप भी महिला हैं, हम भी महिला हैं। आज आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम भी हैं, लेकिन जब भी हम रसोई में जाते हैं, प्याज काटने से आंसू निकलता है, उसी तरह अगर बाजार में जब पॉकेट से पैसा निकाल कर देते हैं कि बाजार करके सामान लाओ तो भी आंसू निकलते हैं, क्योंकि हर दिन जैसे हर दिन आगे बढ़ रहा है, हर कमोडिटी का दाम बढ़ते जा रहा है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। यह गरीब की

जेब को काटते जा रहा है। यह चिंतन का विषय है और आप भी इस चीज को अच्छे से महसूस कर रहे हैं। डिमोनिटाइजेशन अचानक नवम्बर, 2016 में भारत के प्रधानमंत्री ने लागू किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इससे आतंकवाद और ब्लैक मनी खत्म होगी, जो ब्लैक मनी आ रही है, वह भी बंद होगी। लेकिन आज तक यह प्रॉबल्म सॉल्व नहीं हुई, क्या हुआ? Unemployment rate has increased from six to seven per cent during COVID pandemic period. Given the economic uncertainty due to prevailing COVID situation, we have not been able to see the promised *acche din*. अच्छे दिन हम लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं। जिसके पास नौकरी थी, उसने भी नौकरी खोयी है।

The Economic Survey reveals that even in the financial year 2021--22 the economy will be of the same size as in 2019-20 fiscal. The Government should be *… (Not recorded)* of the economic ruin caused by its misplaced priorities.

The two lost years have pushed 4.6 crore people into poverty and 84 per cent of families have seen wage reduction. The total debt of the Government of India, which was Rs.53 lakh crore in March 2014, would blow up to Rs.136 lakh crore by March 2022.

Our Chief Minister Mamata Banerjee has been leading the fight and protesting against the Government on the issue of price rise. The Centre has raised Rs.4 lakh crore in the recent times from increased fuel prices, and our Chief Minister Mamata Banerjee has demanded that the money should be equally distributed among the States.

(2005/SK/RCP)

Even during this time of crisis also, she has given Rs. 500 or Rs.1000 to every woman under the Lokkhi Bhandar scheme. I oppose the Motion of Thanks on the President's address because it does not take into consideration the importance of Andaman and Nicobar Islands and conveniently ignores their aspirations. It also paints a rosy picture of the economy whereas the reality is that we are moving towards recession due to the failed economic policies like demonetization and GST which have an adverse effect on the farmers, MSMEs and labourers and which have led to unemployment.

मैं एक लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं। इस सरकार की यह दशा है -

लश्कर तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है।
तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है।
इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं,
कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है।

(इति)

2006 बजे

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): माननीय सभापति जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश में कोरोना जैसी महामारी के दौरान पहली बार 8.5 फीसदी देश की जीडीपी होती जा रही है। मैं समझता हूं कि यह 2,94,000 करोड़ डॉलर है। हम इस तरह से कोरोना महामारी में आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी भी हो, जब खेत और खलिहान ठीक होगा, किसान के खेत में जब अच्छी फसल होगी, मैं उसे ही जीडीपी मानता हूं। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भारत की समृद्धि का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। मैं समझता हूं कि देश के गांवों को मजबूत करने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। पिछले सात सालों में देश किस तरह से विकास के पथ पर पहुंचा है, यह कहने में मुझे कोई शंका नहीं है।

हम आज एक विकासशील श्रेणी में जाकर खड़े हुए हैं। आज हम लोग विकास के देशों में खड़े हुए हैं। जब देश में कोरोना महामारी आई थी तब से लेकर अब तक देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंतन किया। देश में करीब 168 करोड़ डोज़ज़ लगी हैं। 91 करोड़ लोगों को पहली डोज़ लग चुकी है और करीब 72 करोड़ लोगों को दूसरी डोज़ लग गई है। मैं समझता हूं कि इस महामारी से देश को निकालना बहुत बड़ी बात थी। चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, भारत के अंतिम छोर पर गांव में बैठे व्यापारियों और मजदूरों का अगर किसी ने रखा है तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने रखा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में दो जिले हैं, दोनों जिलों में केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिए हैं। मैं माननीय मंत्री जी और केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज की बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं। मैं समझता हूं कि पहली बार केंद्र सरकार ने इस देश के गांवों में बसे गरीबों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना की शुरूआत की है। आज देश का गरीब आदमी, जिसके सिर पर छत नहीं थी, अगर उसके सिर पर छत देने का काम किसी ने किया है तो देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने फरवरी, 2015 में मेरी कांस्टीटुएंसी श्रीगंगानगर में सॉयल हैल्थ कार्ड की शुरूआत की थी।

(2010/MK/RK)

तब से लेकर अब तक किसानों की जमीन किस तरीके से अच्छी रहे, उनकी जमीन किस तरह से खुशहाल रहे, धरती माँ की तबीयत खराब न हो, इसके लिए अगर किसी ने बीड़ा उठाया है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। किसानों की एक छोटी-सी बात को भी लेकर देश के प्रधानमंत्री जी बीड़ा उठाते हैं। मेरी कांस्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा कीनू होता है। अभी कीनू के लिए एक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया है। यह काम देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार केन्द्र सरकार ने की है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। कीनू के लिए एक ट्रेन को बांग्लादेश भेजने का काम पहली बार हुआ है। हमारा भारत एक श्रेष्ठ भारत हो, हमारा भारत एक विश्व गुरू बने,

इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रण लिया है। मैं समझता हूँ कि विकास के पथ पर पहुँचाने का काम और विश्व गुरू बनाने का काम, देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है।

महोदया, एक जमाना ऐसा था, जब पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था, लेकिन आज पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु मानने के लिए तैयार है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मुझे एक बार अमेरिका जाने का सौभाग्य मिला था। वर्ष 1996 में, जब मैं अमेरिका गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर सेल्फ सर्विस है। ग्राहक आता है, माल देखता है, बाद में माल लेकर चला जाता है और पैसा वहीं पर छोड़ जाता है। जब मैं वापस हिन्दुस्तान में आया तो एयरपोर्ट पर लिखा हुआ था कि सवारी अपने सामान के लिए खुद जिम्मेवार है। जब मैं बस में बैठा तो यह लिखा हुआ था कि जेब कतरों से सावधान। अगर यह हालत इस देश की किसी ने की है तो इन लोगों ने की है। अभी इनके कोई भी सदस्य सदन में सम्मिलित नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसको उठाने और देश को विकास की पथ पर ले जाने का काम केन्द्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने किया है।

महोदया, मेरी कांस्टिट्यूएंसी बॉर्डर से लगी हुई है। वह सीमावर्ती क्षेत्र है। वहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर की सड़क निकल रही है। यह 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से बन रही है। यह भटिण्डा से लेकर पूरे राजस्थान होते हुए, भावनगर तक जाएगी। मेरी कांस्टिट्यूएंसी में एक बहुत बड़ी सड़क निकल रही है। इसके लिए मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे इतनी बड़ी सड़क मेरी कांस्टिट्यूएंसी से निकाल रहे हैं।

मैं एक और बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं समझ रहा हूं कि मेरा टाइम नहीं था, फिर भी आपने मुझे बोलने का टाइम दिया है।

अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में रीट के पेपर हुए थे। रीट के एग्जाम में जिस तरह से धांधली हुई थी, अभी रीट की एजेंसी वही है। कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार ने 8 साल पहले इसी एजेंसी को रीट का एग्जाम कराने के लिए कहा था और आज भी उसी को बोला है। उस एजेंसी ने रीट के पेपर को बेच दिया था। उसकी जांच एसओजी ने की है। इसके लिए उसने सरकार और विभाग के अधिकारियों को दोषी माना है।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। जो परीक्षा हुई है, उसको रद्द किया जाए, ताकि राजस्थान के नौजवानों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। वे एक बार फिर से अच्छे एग्जाम की तैयारी कर सकें।

महोदया, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी कांस्टिट्यूएंसी राजस्थान प्रदेश का एक सीमावर्ती क्षेत्र है। पूरा राजस्थान प्रदेश रेतीला है। कहीं पर सिंचाई हेतु पानी है तो कहीं पर नहीं है। कहीं पर पीने हेतु पानी है तो कहीं पर नहीं है। लेकिन, जो 'जल जीवन मिशन' स्कीम है, उसने हर घर तक जल पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जो को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने और उसे विकास के पथ ले जाने का काम किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

(इति)

2014 बजे

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): सभापति महोदया, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा एवं भविष्य की योजना और उसके स्वरूप का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है। उन्होंने यह साफ किया है कि भारत सरकार देश के विकास और आम जनमानस के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

महोदया, सरकार द्वारा संचालित गरीब कल्याण योजनाएं काफी सफल एवं सराहनीय रही हैं। विशेषकर, वैश्विक महामारी के समय जब पूरा विश्व इस प्रकोप से जूझ रहा था, तो लोगों की नौकरियां जा रही थीं और मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार ने उनकी चिंता की। इस देश की 80 करोड़ गरीब जनता को अनाज देने की चिंता करने का काम भी मोदी जी की केंद्र सरकार ने किया है।

(2015/SJN/PS)

सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार के द्वारा लाई गई 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' की चर्चा की है। देश में पहली बार किसानों को 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' के माध्यम से सम्मानित करने का कार्य भारत सरकार कर रही है। इससे देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। अभी तक किसानों को लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना 'आयुष्मान भारत योजना' है, जिसके माध्यम से करीब 50 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि बचे हुए सभी बीपीएल परिवारों को 'आयुष्मान भारत योजना' से यथाशीघ्र जोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि अभी तक जो भी गरीब परिवार शेष रह गए हैं, उनको इस योजना का लाभ मिल सके।

सभापति महोदया, सरकार द्वारा लाई गई 'प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना' का जो प्रारूप सामने आया है, मैं उसके तहत आपके माध्यम से सरकार से बिहार प्रांत और अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया के लिए कुछ मांग करना चाहता हूं। विदुपुर एनएच, दलसिंह सराय, सिमरी-बख्तियारपुर, उदाकिशुनगंज, पूर्णिया और कटिहार एनएच - 131ए जो कि 'भारतमाला परियोजना' के तहत ग्रीन फील्ड में चयनित है, उसका सर्वे कराया जाए। उस योजना में इसको शामिल किया जाए, इसकी निविदा हो और 'भारतमाला परियोजना' के तहत इस सड़क का निर्माण कराया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं। इसके साथ ही खगड़िया से पूर्णिया तक के लिए जो नेशनल हाइवे है, उसके फोर लेन के निर्माण के लिए उसका डीपीआर तैयार हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष में उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाए, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। इसके साथ ही कुरसेला से सिमरी-बख्तियारपुर के लिए जो स्टेट हाइवे है, उसको फोर लेन और नेशनल हाइवे में परिवर्तित किया जाए। उसे 'प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना' में शामिल किया जाए और इस सड़क को फोर लेन में परिवर्तित किया जाए।

सभापति महोदया, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 'उड़ान योजना' में पूर्णिया जिले को भी सम्मिलित किया गया है। पूर्णिया से हवाई सेवा प्रारंभ करने की मांग बहुत पुरानी है। मैं इस मांग को पिछले लोक सभा कार्यकाल से सदन में उठाता आया हूं, किन्तु उसके लिए भूमि अधिग्रहण में कुछ देरी हो रही है। अतः मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि पूर्णिया में स्थित रक्षा मंत्रालय के सैन्य हवाई अड्डे में अस्थायी तौर पर एक टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाए और वहां से वायु सेवा बहाल की जाए। जो पिछड़ा हुआ इलाका है, एस्पिरेशनल इलाका है, अगर वहां से वायु सेवा बहाल होगी, तो पूर्णिया कमिश्नरी, कोसी कमिश्नरी, बंगाल और नेपाल के लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा।

सभापति महोदया, पूर्णिया जिला मेरा संसदीय क्षेत्र है, वह देश का सबसे पुराना जिला है। सन् 1770 में पूर्णिया जिला बना था। पूर्णिया आधारभूत संरचना में पिछड़ा हुआ है, जिसकी वजह से नीति आयोग ने उसको आकांक्षी जनपद में शामिल किया है। पूर्णिया से देश की राजधानी और बिहार की राजधानी पटना के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है। वह सबसे पुराना जिला है, लेकिन वहां से ट्रेन की कोई सीधी व्यवस्था नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पूर्णिया कोर्ट में एक वाशिंग पिट बने और देश की राजधानी दिल्ली एवं बिहार की राजधानी पटना के लिए 'तेजस' और 'वंदे भारत' जैसी ट्रेनों की सुविधा बहाल की जाए।

सभापति महोदया, मैं जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूं, वह सीमांचल और कोसी का इलाका है, वहां मक्के की भी पर्याप्त खेती होती है, लेकिन किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। उसका समर्थन मूल्य तय है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह आपस में समन्वय स्थापित करे और किसानों से उचित समर्थन मूल्य पर मक्के की फसल की खरीदारी की जाए। अतः इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही साथ हमारी दो रेल परियोजनाएं काफी दिनों से लंबित हैं। जो कुरसेला से बिहारीगंज रेलखंड है, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, तब उन्होंने उसका सर्वे कराया था और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उसका शिलान्यास किया था। मैं सात वर्षों से इस परियोजना के लिए इस सदन में चर्चा करता आया हूं। इस वित्तीय वर्ष में उसके लिए मात्र एक हजार रुपये की राशि आवंटित की गई है, ताकि वह योजना जिंदा रह सके। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस योजना को भी पूर्ण कराया जाए।

अंत में, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ जो बिहार की मांग है, चूंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, उसे विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष सहायता मिले, ताकि बिहार भी अग्रणी राज्यों के साथ आगे बढ़ सके। जब बिहार आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

(इति)

(2020/YSH/SMN)

2020 बजे

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। साथ ही हमारी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और विश्वास जताया कि मैं गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज को इस सदन में रख सकूँ।

महोदया, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों व समाज के अंतिम वंचित तबके के लिए विकास कार्यों का विवरण और उन कार्यों के लिए मद की व्यवस्था के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आया हूं, जिसके अंतर्गत दो जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर आते हैं।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आज निहाल जी का जन्म दिवस है इसलिए मैं उनको यहां से बहुत-बहुत बधाई दे रही हूँ। बहुत-बहुत आशीर्वाद।

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): वे हर मायने में बहुत ही पिछड़े हैं और उत्तर में प्रदेश के कुल 8 अति पिछड़े जिलों में से आते हैं। अभी भी यहां के लोग ज्यादातर झोपड़ पट्टी में रहते हैं। यहां के लोगों को जीवन जीने के लिए मूलभूत बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पीने योग्य पानी, बिजली, सड़क, उच्च और गुणवत्तायुक्त शिक्षा और स्वास्थ सुविधाओं की भारी कमी है ।

सभापति महोदया, हमारा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती जिला जो अत्यंत ही पिछड़ा जिला है, आजादी के 75 साल बाद आज भी रेलवे लाइन से नहीं जुड़ पाया है। बहराइच, खलीलाबाद, भिन्गा, श्रावस्ती, बलरामपुर, उतरौला, डुमरियागंज, मेहदावल और बासी रेल लाइन परियोजना को शीघ्र शुरू करने के बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। यही पर विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध स्थल है, जहां देश-दुनिया से लाखों अनुयायी और पर्यटक प्रतिवर्ष घूमने आते हैं। यहाँ पर एक एयरपोर्ट बना है, लेकिन अभी तक चालू करने के बारे कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

महोदया, यहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जिस कारण लाखों लोगों की जान और माल की क्षति होती है। इन पिछड़े जिलों का सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र तक नहीं हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कोरोना और पूर्ण बंदी के दौरान करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। उनका रोजगार छिन गया और कइयों की तो तनख्वाह आधी हो गई। साथ ही छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की दुकानें व व्यावसाय बंद हो गया, जिस कारण उनकी आमदनी पर असर पड़ा है। उनके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की है कि वर्तमान सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष 2022 तक रखा था, लेकिन यह कही नहीं बताया गया है कि किसानों की इनकम कब और

कैसे दोगुनी होगी। आज स्थिति यह है कि किसानों की आय दोगुनी तो दूर किसानी की लागत में दोगुनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सिंचाई उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी से किसानों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बजाय किसानों को ही समाप्त करने पर तुली हुई है। न रहेंगे किसान और न आय की बात होगी।

महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश के अन्नदाता किसान जो आंदोलन में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का न ही आर्थिक सहयोग या किसी अन्य प्रकार का सहयोग देने की बात कही है। मेरी व हमारी बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों को सरकार द्वारा उनके परिवार को कम से कम 20 लाख रुपये प्रति किसान और साथ ही उनके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए, जिसका राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम सभी सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिए पाँच करोड़ रुपये मिलते हैं।

(2025/RPS/SNB)

इसी पांच करोड़ रुपये में 18 प्रतिशत जीएसटी भी कट जाता है और 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से देने का कोई जिक्र नहीं है। क्षेत्रीय विकास निधि में सरकार द्वारा फण्ड बढ़ाने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सीमित संसदीय क्षेत्र विकास निधि के द्वारा क्षेत्र में विकास के कार्य कैसे करेंगे, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

महोदया, एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि एक किसान ने अपनी तीन एकड़ जमीन में खेती करने का काम किया। उस खेत में बोने के लिए उस किसान ने जब मार्केट से गेहूं और उर्वरक खरीदकर, सिंचाई के लिए पानी, मंड़ाई आदि सब खर्चों को जोड़कर अनुमान लगाया तो खेती करने के बाद उसका प्रॉफिट मात्र एक क्विंटल गेहूं और उसका भूसा निकलता है। यही उस किसान का प्रॉफिट है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसान के हित को देखते हुए, किसान की जो रीढ़ टूट रही है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

2026 hours

SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM): Hon. Chairperson, at the very outset, on behalf of the Sikkimese people I would like to thank and congratulate hon. Prime Minister and the Government for their extensive vaccination drive. The State of Sikkim has been a forerunner in vaccination and most of the adult population in Sikkim has been vaccinated. I would also like to extend my gratitude to the healthcare workers who have worked incredibly at the time of pandemic and all the other frontline COVID warriors.

Hon. Chairperson, in the last few years, the State of Sikkim has seen quite a bit of development in infrastructure sector like extension of highways, widening of highways, and construction of bridges along the Indo-China border in North and East Sikkim. For this, I would like to thank the hon. Defence Minister. I would like to bring to the kind notice of the Government and the hon. Minister that Sikkim is a small State but we are surrounded by three international borders. One of the most sensitive borders is the Indo-China border. However, our State also has a long border in the Western part of the State which is the Indo-Nepal border. This border is still isolated, there is no road connectivity and there is no reliable mobile network. There are 14 BOPs and most of them are above 12,000 feet altitude. Therefore, I would like to request the Government to take this issue very seriously and help the State Government of Sikkim to be able to give connection to the Indo-Nepal border as well.

The deplorable condition of NH-10 is known to the Government. I would again reiterate to the Government of India and the Minister of Surface Transport that this is the only highway that connects Sikkim with rest of India. This is very important and I request in this august House that this NH-10 highway may kindly be considered for improving the condition of the highway which is very deplorable at this point in time.

Sikkim is known for a number of sports persons and athletes and some of our brothers in Sikkim have represented India in Olympics as well. I would like to extend my gratitude to the Government for providing us with a `*Khelo* India Centre of Excellence' at Gangtok. We look forward to have more such centres so that athletes from a small State like Sikkim and other North-Eastern States get an opportunity to participate more and grow the sports culture in our State. The Sikkim Government has announced to provide playgrounds to each and

every school including primary schools in the remote areas so that we can have more sports persons and athletes.

Hon. Chairperson, one big announcement by the Government is chemical-free farming which will change the entire nature of agriculture and also its economy in the country. However, I would like to point out one very basic issue in this regard. The State of Sikkim is already an organic State and we have been through this problem and so before implementing chemical-free farming in the rest of the country, I would like to request the Government to allocate more funds for production of organic manure, fertilizers, and bio-fertilizers so that productivity does not decrease in those areas where chemical-free farming is proposed by the Government.

(2030/RU/SPS)

Lastly, I would like to thank hon. Prime Minister for all the help given to the State of Sikkim during the time of pandemic. Due to his help and generosity and because of his compassionate leadership, a small State like Sikkim was able to fight COVID-19 pandemic.

With these words, I support the Motion of Thanks on the President’s Address.

(ends)

2031 बजे

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): सभापति महोदया, धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अवसर प्रदान किया। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और लोकतांत्रिक गणराज्य में आम जनता के हितों की रक्षा करना सरकार का एक परम दायित्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महामहिम के अभिभाषण में दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना-19 में विषम परिस्थितियों में भी कार्य करने वाले स्थानीय प्रशासन, चिकित्सक, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, वैज्ञानिकों एवं उसमें सहयोग करने वाले सभी उद्यमियों के प्रति महामहिम द्वारा अभिनंदन किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से अभिभाषण पर उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस बात पर भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि भारत में कोरोना-19 में डेढ़ सौ करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज़ लगाकर एक रिकॉर्ड कायम करते हुए दुनिया में सशक्त स्वास्थय सेवा के रूप में भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत के नागरिकों में सरकार के प्रति सुरक्षा की भावना बढ़ी है और उनका मनोबल भी बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। मैं इस बात पर भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि किसी देश में तमाम सारी महामारियां, जिन्हें हमने इतिहास में पढ़ा है, देखा है और हमने सुना है, उनमें से ऐसी भी महामारी आई कि लोगों को दाने-दाने के लिए मोहताज होना पड़ा है। लेकिन दुनिया की वैश्विक महामारी के दौर में भी, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि महामहिम के अभिभाषण पर अपनी सरकार के मुखिया के प्रति कि उन्होंने पूरी दुनिया में कोरोना से हिल जाने के बावजूद भी, लॉकडाउन होने के उपरांत भारत के नागरिकों को उनके घरों तक सुलभ और नि:शुल्क राशन पहुंचाकर उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया और पूरे देश में कहीं भी कोई इस कोरोना महामारी में भूखा नहीं सोया। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और दुनिया में लोग भारत की एक नज़ीर देने को मजबूर हो चुके हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से महामहिम के अभिभाषण पर इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि देश में 80 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1 लाख 80 हजार करोड रुपए इस कोरोना काल में दिए गए। वहीं श्रमिकों के रूप में पंजीकृत श्रमिकों को भी सीधे उनके खाते में इस संकट के दौर में रुपया भेजने का काम बिना किसी बिचौलिए के सरकार द्वारा किया गया। दूसरी ओर माताओं और बहनों के जन-धन खातों में सीधे भारत सरकार से रुपया भेजकर, उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया गया। इसलिए मैं आप के माध्यम से महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदया, मैं इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि दुनिया में आज तक महामारी के दौर के बाद भी भारत सरकार की नीतियों, रीतियों और कार्यक्रमों के चलते हमारी अर्थव्यवस्था कहीं कमजोर नहीं दिखी और हम पूरी तरह से एक मजबूत लोकतंत्र को लेकर दुनिया के सामने भारत को खड़ा करने में कामयाब हो सके। साथ ही इस दौर में टोक्यो ओलंपिक में

भारत ने अपनी युवा शक्ति की क्षमताओं को देखा और इस प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक रूप से भारत ने मेडल जीता और दुनिया में पैरा ओलंपिक में भी 19 पदक जीतकर अपना एक रिकॉर्ड कायम किया। इसके लिए भारत सरकार की 'खेलो इंडिया नीति' और युवाओं के प्रति देश की सरकार का समर्पण निश्चित रूप से सराहनीय रहा। स्टार्ट-अप इंडिया, संचार साधनों, एमएसएमई व अनेक क्षेत्रों के साथ-साथ जंगे-आजादी की लड़ाई में बापू के नेतृत्व में देश की चेतना का प्रतीक रही खादी एक बार फिर छोटे उद्यमियों का संबल बन रही है और सरकार के प्रयासों से वर्ष 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री 3 गुना बढ़ी है, जो भारत के स्वावलंबन का एक प्रतीक है। मैं आपके माध्यम से इसलिए भी माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेजी से उभरते वैश्विक परिवेश में भारत ने अपने राजनयिक संबंधों को बेहतर कर दुनिया में एक सशक्त भारत के रूप में अपना स्थान बनाया है।

(2035/RAJ/SM)

उसी का यह परिणाम रहा है कि अगस्त, 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की और इस दौरान कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए।

मान्यवर, मेरी सरकार नागरिकों की जरूरतों के प्रति सरकारी विभागों को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने के लिए जो कृत संकल्प है। बकाया मामलों के निपटारे हेतु स्वच्छता के लिए भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में जो विशेष अभियान चलाया गया उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदया, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट हुआ कि मेरी सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है और उसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में विशेषकर रक्षा उत्पादन में देश आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आज मेक इन इंडिया का परिणाम है कि वर्ष 2020-21 में 90 प्रतिशत उपकरणों से जुड़े अनुबंधों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई है और हमारी सेनाओं ने 209 ऐसे साजो-सामान की सूची भी जारी की है।...(व्यवधान) जिन्हें विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। रक्षा उपक्रमों द्वारा 2800 से ज्यादा उपकरणों की सूची जारी की जा चुकी है जिनका निर्माण किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप को तेजी से बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की प्रतिबद्धता के लिए भी मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मान्यवर, जहां एक ओर कृषि के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और वित्तीय संसाधनों के क्षेत्र में सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारत की अमूल्य धरोहरों को भी देश में वापस लाए जाने का अभिनव प्रयोग सरकार द्वारा करते हुए, भारत से शताब्दी पूर्व चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को भी वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाना, दुनिया में एक अनूठा उदाहरण है।...(व्यवधान) मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
...(व्यवधान)

(इति)

2037 hours

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Thank you, Madam, for giving this opportunity. At first, I would say that hon. President's Address became a political speech. It is quite unfortunate. It has not touched the heart of the people. It has not addressed the emotions, sentiments, concerns of the common people.

Madam, what is the fuel price now-a-days? It costs one hundred rupees. Our hon. Leader mentioned about it. Is it because of the international market price? No. It is because of tax exploitation. What is the excise duty that the Government is imposing now? It is Rs.27.9 for petrol and Rs.21.8 for diesel.

During the period of UPA, it was Rs.9.47 for petrol and Rs.3.5 for diesel. At that time, you had protested. Now, the country is asking why the tax rates are not being reduced. It is a question being asked from every part of this country. Government should give answer on this.

Unscientific implementation of GST, demonetisation, COVID-19 pandemic severely affected and destroyed the livelihood of the common people. It has affected small-scale merchants, small-scale traders, farmers and everybody is suffering. So many people have committed suicide. Government should give answer on this specifically.

What about our MGNREGA? This Government is considering the MGNREGA programme as a secondary one. It was the prestigious programme introduced by UPA Government 16 years back. This Government is planning the mercy killing of MGNREGA programme. What is the budget allocation? Only Rs.73,000 crore was allocated now. Earlier, it was Rs.98,000 crore. Before that, it was Rs.1,11,169 crore. This kind of decreasing rate is showing that this Government is not at all considering the MGNREGA programme.

In the last six months, in my State Kerala, MGNREGA workers are wating for their wages. It is not being disbursed. It should be disbursed immediately. It is very shameful for the Central Government. The Government should attend to that case specifically.

Then, what about our agriculture sector? As per the Economic Survey report, 3.9 per cent is the growth rate. There is a slight difference from last year. It was 6.8 per cent in 2016. What is the reason? It is because of the wrong policies adopted by this Government. Three wrong farmers' laws had been tried

to be introduced. It had been withdrawn due to the farmers' protest. Now, this Government is trying to reintroduce it. But it may not be possible.

What is the subsidy policy of this Government about fertilizers? An amount of Rs.99,500 crore had been allocated by your Government last time. Now, it is reduced to Rs.49,000 crore for urea. For P&K fertilizer, it was Rs.39,000 crore last year. Now, it is only Rs.35,500 crore.

(2040/KSP/VB)

It will affect the production rate. Then, what about the price of commercial crops? We are facing a very critical situation in our State. I am coming from an area which has the maximum cultivation of cardamom, pepper and rubber. We want MSP for these commodities. Due to the low price of cardamom, the farmers require Rs. 2,000 as MSP; we need Rs. 700 as MSP for pepper; and for rubber, we need, at least, Rs. 250 as MSP. But the Government is not willing to pay MSP for these farmers. I demand that these commodities be included in the list of Commission for Agricultural Costs and Prices. Jute, tobacco and cotton have already been included in this list. We are not opposing that. But we demand that cardamom, pepper and rubber also should be included in this list. Madam, two days ago, our hon. leader mentioned about the discrimination shown by this Government towards the States ruled by the Opposition parties. This is the main problem which we are facing in Kerala. The Government should address this issue. Then, what about the position of labourers. I am representing a constituency which has the maximum number of plantation labourers. We expected a package for tea estate workers. During the Budget of 2021, the hon. Finance Minister announced a package for the tea workers of Assam and Bengal. At that time, in this august House, the hon. Finance Minister stated that she will consider the case of Kerala next time. In Peerumedu area of my constituency, more than 17 tea estates are not operating because managements of these estates are not in a position to run these estates. So, our tea estate workers are suffering very much. There is no housing, drinking water, and there are no basic infrastructure facilities there. This issue should be addressed immediately. Therefore, we want a special package for the tea estate workers of Kerala. These kinds of mistakes are being repeated by this Government. That is why, I oppose the Motion of Thanks on the President's Address.

(ends)

2042 बजे

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): माननीय सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के चौथे बिन्दु में पढ़ा है- "मेरी सरकार मानती है कि अतीत को याद रखना तथा उससे सीख लेना, देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है।"

यह बहुत ही जरूरी है। बहुत ही सही और बेहतरीन तरीके से उन्होंने अभिभाषण को देश के सामने रखा है। मैं एक नया सांसद हूँ, इसलिए हमको भी सीखने का मौका मिला। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का भी अभिनन्दन करना चाहूंगा। बहुत वर्षों के बाद 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय हुआ। बिरसा मुण्डा का फ्रीडम मूवमेंट में जो योगदान रहा, उसका रिकोग्निशन नहीं था। हम देखते हैं, देश बदल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने देश को बनाने के लिए काम किया, उनका कोई रिकोग्निशन पहले था ही नहीं। अभी जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया है, यह सभी के लिए एक संतुष्टि का विषय है। आप असम में देखेंगे, तो झारखण्ड से लोग असम में जाकर बिरसा मुण्डा दिवस मनाते हैं, लेकिन इसका कोई रिकोग्निशन नहीं था। पहली बार ऐसा रिकोग्निशन मिला है। इसलिए हम उनका बहुत ही आदरपूर्वक धन्यवाद करते हैं।

महोदया, हमारा संकल्प क्या है? "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" हमारा संकल्प है। पहली बार हमने ऐसा संटेंस और ऐसा मोटो सुना है। सबके साथ सबका विकास होगा, सबका विश्वास होगा और सबका प्रयास होगा। सबको लेकर देश बनाने का एक संकल्प हमने लिया है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम यह सुनते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है। प्रधानमंत्री इतने सुंदर तरीके से सबको लेकर काम करने के लिए बोलते हैं, फिर भी लोग इसको विश्वास में नहीं लेते हैं।

(2045/PC/KKD)

हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल बिंदु अंत्योदय का है। अंत्योदय के ऊपर पूरे देश में हम विचार रख रहे हैं। मैं दूसरे किसी विषय के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। जब पद्म अवॉर्ड दिए गए, तो उनमें हमने पहली बार देखा कि कई लोग, जो बिना चप्पल के थे, वे पद्मा अवॉर्ड लेने आए थे। … (व्यवधान) हम लोगों ने पहली बार टीवी पर ऐसा नज़ारा देखा था। ऐसा पहले कभी नहीं था।

मैं नॉर्थ-ईस्ट के बारे में बोलता हूं। नॉर्थ-ईस्ट को तो कभी रिकॉग्निशन मिला ही नहीं। यहां बोला गया कि इंडिया क्या है, भारत क्या है, स्टेट्स और बाकी सब यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बोला गया। लेकिन नॉर्थ-ईस्ट पहले कहां था? नॉर्थ-ईस्ट के लोगों का क्या रिकॉग्निशन था?

इस बार हम आजादी के 70 ईयर्स पूरे होने पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वर्ष 1979 से असम एजिटेशन हुआ, उस टाइम से हमने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। जब 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन हो रहा था, उस टाइम असम में क्या माहौल था, हम क्या मानते थे? हम लोगों को

लगता था कि 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे लिए बंद है। वहां असम बंद होता था। हम लोगों को पहली बार 15 अगस्त, 2021 को ऐसा मौका मिला, जब किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन या मिलिटेंट ग्रुप ने बंद डिक्लेयर नहीं किया। इस बार हम लोगों ने पहली बार 26 जनवरी पर सेलिब्रेशन किया। किसी ने इसको भी बंद डिक्लेयर नहीं किया। हमने पहली बार ऐसा अनुभव किया, हमने कभी इससे पहले ऐसा फील ही नहीं किया।

हम इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन असम और नॉर्थ-ईस्ट के लोगों से पूछिए कि 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के समय हमारे यहां क्या माहौल था, हम वहां कैसे रहते थे? यहां लोग बोलते हैं कि सेंटिमेंट्स को रिलेट करना है, लेकिन कैसे सेंटिमेंट? सेंटिमेंट को कैसे फील किया जाता है? वहां लोग मर जाते हैं, उसका कोई सेंटिमेंट यहां नहीं होता है। देश किस तरह से चल रहा है। नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के साथ जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, उससे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्या लगता था? उनको लगता था कि दिल्ली हमको देखती नहीं है। मैडम, तब किसकी सरकार थी? दिल्ली में किसकी सरकार थी और वहां, असम, नॉर्थ ईस्ट में किसकी सरकार थी? हम लोगों ने वहां ऐसा कुछ नहीं देखा था। … (व्यवधान) मैडम, मुझे नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा तो बोलने दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर) : मैडम, एक मिनट में कैसे बोलूं? … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपको पांच मिनट का टाइम दे दिया गया है।

… (व्यवधान)

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर) : मैडम, थोड़ा सा टाइम और दीजिए। पहली बार हमने देखा, श्री नरेन्द्र मोदी जी पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट 60 टाइम्स विज़िट किया है। … (व्यवधान) पहले कोई प्रधान मंत्री ऐसा था, जो 60 टाइम्स विज़िट करे? हमने ऐसा कोई प्रधान मंत्री नहीं देखा है। हमें पहली बार यह देखने का मौका मिला कि यूनियन मिनिस्टर्स को नॉर्थ ईस्ट में भेजा गया। पहली बार हमें यूनियन मिनिस्टर्स वहां दिखे। यहां लोग एक यूनियन मिनिस्टर से मिलने के लिए एक महीने तक बैठे रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट में 15 दिनों में यूनियन मिनिस्टर्स जाते हैं। ऐसा पहली बार हमने देखा, जब नरेन्द्र मोदी जी ने असम के 'गामूसा' को पहनकर वैक्सीन लगवाई। हमें कितना गर्व महसूस होता है, हमारे क्या सेंटिमेंट्स, क्या फीलिंग होती है।

जब पद्म अवॉर्ड दिए जाते हैं, तो मणिपुर को चार पद्म अवॉर्ड मिलते हैं। जब एक गरीब चाय वाले, मजदूर के बेटे को पद्म अवॉर्ड दिया जाता है, उस सेंटीमेंट को कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। उस इमोशन को हमने रिप्रेज़ेंट किया। आप देखिए बीटीआर, नॉर्थ ईस्ट के उस एरिया में कितने मिलिटेंसी ग्रुप्स थे। लोग डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते? बिना शांति के क्या डेवलपमेंट होगा, क्या रास्ता निकलेगा, कैसे बड़े-बड़े डेवलपमेंट्स होंगे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वर्ष 2012 और 2014 में यहां लोग बोलते थे कि माइनॉरिटी के ऊपर बहुत दंगे हो रहे हैं। लेकिन असम और नॉर्थ ईस्ट में कैसे दंगे हो रहे थे? वर्ष 2012 में चार लाख लोग रिलीफ कैम्प्स में रहे। वहां 273 रिलीफ कैम्प्स बने।

वहां इस तरह का परिवेश था। इसके बाद नरेन्द्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई और वर्ष 2014 में ऑपरेशन ऑलआउट डिक्लेयर हुआ।

(2050/CS/RP)

उसके बाद इन्सर्जेंसी के ऊपर बीटीआर रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद अभी असम में शांति है, अभी डेवलपमेंट है, अभी प्रोस्पर है। अभी नॉर्थ-ईस्ट में हम सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। नॉर्थ-ईस्ट में पहले नेफा था। उस टाइम जब पूरे हमारे नॉर्थ-ईस्ट को अलग-अलग स्टेट बनाया गया, स्टेट की बाउन्ड्री को वहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया। इससे नॉर्थ-ईस्ट के बीच में, स्टेट्स के बीच में वहाँ रिलेशन खराब हुए, लेकिन पहली बार इस बार नॉर्थ-ईस्ट के बीच में सबके साथ हम बॉर्डर के ऊपर बात कर रहे हैं कि नॉर्थ-ईस्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पहली बार हम लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री मिला, जिन्होंने हमारे इमोशन को समझा, हमारी प्रॉब्लम्स को समझा और हमें कैसे डेवलपमेंट में आगे लेकर जाना है। पहली बार नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को लग रहा है कि हम लोग देश के मेन एरिया में आ रहे हैं। पहली बार दिल्ली जाकर नॉर्थ-ईस्ट में अराइव किया है। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से जो वक्तव्य दिया है, जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, उस काम को हम सभी लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ-ईस्ट प्रोस्पर करेगा, नॉर्थ-ईस्ट आगे बढ़ेगा और एक बेहतर नॉर्थ-ईस्ट और असम बनेगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं।

महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

2052 hours

KUMARI AGATHA K. SANGMA (TURA): Thank you, Madam, Chairperson for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks on the Presidential Address.

Madam, I would like to rise in order to support the Motion of Thanks on behalf of my political party, the National People's Party and I would like to extend my congratulations and gratitude on behalf of my State to the Government of India under the able leadership of hon. Prime Minister Mr. Narendra Modi for continually supporting and assisting my State of Meghalaya. In the Presidential Address, the President has mentioned about 50 years of statehood celebration that Meghalaya witnessed this year. I would like to, once again, thank the Government for helping the State of Meghalaya to build our infrastructure and the various developmental programmes that the Government has been assisting us with.

Madam, just to give you a few statistics, the Government of Meghalaya has built 1200 kilometres of roads under the PMGSY in three years. We also have to achieve the target under the Jal Jeevan Mission by this year in December 2022 as against the national target of December, 2024. I would request the Government to continue giving us the support that it has been giving us. Due to paucity of time, I may not be able to go into the details of the developmental works of my State but I would like to state that since this is the 50^{th} year of our statehood, it would be a very, very historic and a very symbolic gesture on behalf of the Government of India if it accepted the long-standing demand of the people of Meghalaya regrading inclusion of the Garo and Khasi languages in the Eighth Schedule to the Constitution.

Madam, this year a Padma Shri Award was given to Professor Badaplin War who is a professor in Khasi, the Department of Khasi in NEHU Campus in Shillong. Madam, Padma Shri being awarded to a professor like that, who is an expert in Khasi, symbolises or acknowledges the importance of Khasi language in our country. If the Garo and Khasi languages are being included within this year, it would be extremely symbolic for our State.

Madam, the President in his Address talked about air connectivity in North-East. In this regard, I would like to inform you that there is an airport in my constituency, the Baljek Airport, which needs to be started immediately.

(2055/NKL/KN)

I would request the Government to look into this demand. As far as our State is concerned, the land acquisition and other formalities have already been done from the State Government's side. So, we require the support from the Central Government, and I would really appreciate if you could look into that.

Since I also represent North Eastern States in general, I would also like to say a few things about the North East. The hon. President spoke about the settlement which was reached between the Central Government and the Government of Assam to end the long dispute that is going on in Karbi Anglong, and a peace settlement is being negotiated. In the same manner, I would request that the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) also be repealed, especially in connection with the North-Eastern States. We witnessed a very unfortunate incident which happened in Nagaland last year in December, which should not have happened. Many innocent lives were lost in this incident. The incident like this should not repeat itself. Therefore, I would request that the AFSPA be repealed.

Madam, there was a mention regarding the National Mission on Edible Oil-Palm Oil and an outlay of Rs. 11,000 crore has been given for this particular mission. After that, the speech says:

> "The Government is also making special efforts like organic farming, natural farming and crop diversification."

Madam, I somehow feel that there is a little bit of a conflict here. Just to let you know, the forest cover in the North-East Region is about 23 per cent of the country's forest cover. I think, it is very important. We regard the North-East as a potential carbon sink avenue for India. There is a huge market for carbon sinks and for the eco-system services that the forests provide. So, instead of focussing on palm oil, etc. if we could focus on the forests of North-East, protect them, and instead use them for the ecosystem services, I think, that would do a larger benefit, not only to the region but to the country in general.

Madam, there was a mention regarding the Khelo India centres. Again, the North-East has a huge potential when it comes to our youth, who are extremely talented in sports. So, I would request that when you are saying that you are setting up hundreds of Khelo India centres – some are already being set up in the North-East – a lot more focus be given to the North-Eastern States.

Madam, I have one more very small point. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana has been a lifesaving scheme. I would like to congratulate the Government for initiating this wonderful scheme during the pandemic. It has really helped the rural population. I urge upon the Government to continue this scheme even beyond March 2022. If the allocation to MGNREGA is being reduced, I feel that there is a need to continue this scheme in order to ensure that the basic safety net is provided to the rural population.

I conclude by extending my support to the Motion of Thanks on the President's Address on behalf of my Party, the National People's Party. With these few words, I thank you for giving me the opportunity to speak.

(ends)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : श्री मलूक नागर जी, आप अपने प्राइवेट मेम्बर्स बिल्स को प्रस्तुत करें।

PROTECTION OF FARMERS FAMILIES BILL

SHRI MALOOK NAGAR (BIJNOR): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the protection of the families of farmers by the State who have lost their lives in accident of any nature, due to disease, natural death or by committing suicide by extending welfare measures and financial assistance, so as to enable the bereaved families to bear the loss of their bread winners and live a respectable life and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि किसी प्रकार की दुर्घटना, रोग, प्राकृतिक मृत्यु अथवा आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवाने वाले कृषकों के परिवारों को राज्य द्वारा कल्याणकारी उपायों और वित्तीय सहायता आदि के द्वारा संरक्षण प्रदान करने, जिससे शोकसंतप्त परिवार अपने आजीविका कमाने वाले की मृत्यु से हुई क्षति को सहन कर सकें और एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें, तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MALOOK NAGAR (BIJNOR): Madam, I introduce the Bill.

(2100/MMN/GG)

FARMERS (GUARANTEED INCOME AND WELFARE) BILL

SHRI MALOOK NAGAR (BIJNOR): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide to the constitution of Farmers Welfare Fund to ensure guaranteed income to farmers irrespective of natural calamity or price fall and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): प्रश्न यह है :

> " कि प्राकृतिक आपदा या मूल्यों में कमी का विचार किए बिना कृषकों के लिए गारंटीकृत आय सुनिश्चित करने हेतु कृषक कल्याण निधि के गठन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MALOOK NAGAR (BIJNOR): Madam, I introduce the Bill.

NATIONAL COMMISSION FOR CREATION OF SMALL STATES BILL

SHRI MALOOK NAGAR (BIJNOR): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute the National Commission to explore possibilities and prepare blueprints for creation of small States; make recommendations thereto to the Central Government and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि लघु राज्यों के निर्माण के लिए संभावनाएं तलाशने और रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने, इसके संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिश करने और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI MALOOK NAGAR (BIJNOR): Madam, I introduce the Bill.

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण्, मेरे पास अभी पांच सदस्यों की सूची है। यदि सदन की सहमति हो तो आधे घंटे के लिए समय बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

माननीय सभापति : श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, बोलेंगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव - जारी

2103 बजे

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ, मैंने कई बार उसको यूट्यूब पर देखा है। देखने के बाद मैंने कई बार महसूस किया कि महामहिम ने अपना जो अभिभाषण शुरू किया, उसमें सबसे पहले, जो हम 75वां अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबको उन्होंने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी, उन सबको नमन किया। इसके बाद 75 साल तक हम जिस तरह से यहां पर पहुंचे हैं, उसमें जिन भी नेताओं का योगदान था, उनकी भी उन्होंने सराहना की है। इसके बाद जो बहुत ही अच्छी बात हमें लगी कि उन्होंने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको याद किया। इसके साथ-साथ गुरूतेग बहादुर जी, जिनको हम हिंद की चादर भी कहते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि हम उनका प्रकाश उत्सव बड़ी धूम धाम से मनाएंगे। हम पिल्लई जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। अरविंदो जी के जन्म दिवस को मनाएंगे। नेताजी की 125वीं जयंती है, उसको भी हम मनाएंगे। इस तरह से हमारा गणतंत्र दिवस 23 जनवरी से शुरू हो कर बीटिंग रिट्रीट तक चलेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बीटिंग रिट्रीट पर अबकी बार वह धुन बजाई गई, जिस पर सबकी आंखें नम हो जाती हैं, ए मेरे वतन के लोगों की धुन को बजाया गया। जिस तरह से एक हजार ड्रोन पूरे आकाश में हमारे देश के अमृत महोत्सव के बारे में बखान कर रहे थे तो हम सभी देशवासियों का मन गदगद हो गया। उसके लिए हम आदरणीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।

(2105/RV/VR)

महोदया, इसी के साथ-साथ मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूं कि हमारे जो साहिबजादे, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, जो गुरु गोविन्द सिंह जी के दोनों साहिबजादे हैं, उन्हें याद करते हुए जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि 26 दिसम्बर को 'वीर बाल दिवस' मनाया जाएगा। मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र सिरसा है और वहां पर हमारे सिख बन्धु बहुत रहते हैं। मेरी खुद की भी बहुत आस्था गुरू ग्रंथ साहिब में है।

महोदया, जब मैंने खुद उस स्टोरी को पढ़ा तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से मुगलों के साथ हमारे गुरु गोविन्द सिंह जी लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय औरंगजेब ने एक खत लिख कर उनको बरगलाने की कोशिश की, उनको बहकाने की कोशिश की कि अगर आप आनन्दपुर साहिब के किले से बाहर निकल जाएंगे तो आपके साथ हमारा युद्ध बंद हो जाएगा। गुरु गोविन्द सिंह जी जानते थे कि मुगलों का पिछला इतिहास कैसा रहा है और जैसे ही वे वहां से निकले, उनके ऊपर औरंगजेब ने जबरदस्त तरीके से चढ़ाई कर दी और उनका पूरा परिवार छिन्न-भिन्न हो गया। परिवार के सदस्य कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए। उसी में माता गुजरी, उनकी दादी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को लेकर जंगल के अन्दर चली गईं और वहां पर गुफा में रहीं। आप देखिए कि वहां किसी ऐसे देशद्रोही ने खबर कर दी और उसके बाद उनको यह कहा गया कि तुम्हें दीवारों में चुनवाया जाएगा। उन दो मासूम बच्चों को जिस तरह से एक-एक करके दीवारों में चुनवाया गया, उसे हम लोग जिन्दगी भर नहीं भूल सकते। इसलिए उन बच्चों की याद में हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी

जी ने कहा है कि 26 दिसम्बर को इन बच्चों के लिए जो 'वीर बाल दिवस' मनाया जाएगा तो मैं इस बात का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। महामहिम जी ने भी इस बात का जिक्र अपने अभिभाषण में किया है।

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि हम एक ऐसी महामारी से गुजर रहे हैं, जो 100 वर्षों में पहले कभी नहीं आई। ऐसी महामारी में, जबकि हमें लग रहा था कि इस विभीषिका से हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे और हमें यह लग रहा था कि देश किस तरह की परिस्थितियों में चला जाएगा तो हमारे जो आदरणीय प्रधान मंत्री जी हैं, उनके मन की जो संवेदनाएं हैं और इसके साथ-साथ जो उनकी दूरदर्शिता है, उससे न केवल हम इस महामारी से पार पाए हैं, बल्कि हमने 80 करोड़ आम जनों को किस तरह से भोजन पहुंचाने का काम किया है, राशन पहुंचाने का काम किया, इस बात का जिक्र भी इस अभिभाषण में किया गया है। मैं तहे दिल से इस बात के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं।

महोदया, मैं कहना चाह रही थी कि उन्होंने 'हर घर जल' की बात कही। हमारी जो महिलाएं हैं, उनके परिवार में उन्हें कह दिया जाता है कि खाना बना दीजिए। अब उसके बाद वह खाना बनाने के लिए पानी कहां से आ रहा है, इसके लिए परिवार के लोग ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। 'हर घर जल' के तहत छ: करोड़ घरों को पेयजल का कनेक्शन दिया है, उसका जिक्र महामहिम जी ने अपने अभिभाषण में किया है, इसके लिए मैं महामहिम जी को और अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

सभापति महोदया आप यह देखिए कि जिस तरह से हमारी सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैनिक स्कूलों के अन्दर हमारी बेटियां भाग ले रही हैं। जून, 2022 से एन.डी.ए. का पहला बैच शुरू होने वाला है। मैं खुद एक स्पोर्ट्सपर्सन भी रही हूं। मैं आपको अपनी खुशी बयां नहीं कर सकती हूं कि हमारी बेटियां आर्मी के अन्दर, नेवी के अन्दर पार्टीसिपेट करेंगी और उन्हें परमानेंट कमीशन भी हमारी सरकार ने दिलवाने का काम किया। मैं तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि कल काँग्रेस के एक वरिष्ठ नेता महामहिम के अभिभाषण का जिक्र कर रहे थे और वे जो चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वे अपने देश की इमेज को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी मैं बहुत सख्त शब्दों में निन्दा करती हूं क्योंकि हमारा जो देश है, यह गुरु तेग बहादुर जी का देश है, गुरु गोविन्द सिंह जी का देश है। गुरु गोविन्द सिंह जी कहते थे कि 'सवा लाख से एक लड़ाऊं, ता गुरु गोविन्द सिंह नाम कहाऊं' ऐसी बात उन्होंने कही थी और आप देखिए कि हमारे मुट्ठी भर सिख सैनिकों ने लाखों-लाख मुगलों के साथ लोहा लिया। ऐसे देश के ऊपर वे इस तरह का सन्देह कर रहे हैं। हम यह कहते हैं कि जब से माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश का नेतृत्व संभाला है, तब से हमारी सेना के अन्दर एक अलग ही तरह का बल आ गया है। हम अभिनन्दन को कैसे भूल सकते हैं? इस तरह की बातें करके नेता, प्रतिपक्ष हमारी सेना को या हमारे मनोबल को कमजोर करने की कोशिश न करें।

(2110/MY/SAN)

आप यह देखिए कि अभी ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ पेपर में एक समाचार आया, ये लोग बाहर के न्यूज़ पेपर्स पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गलवान में भारत के बजाय चीन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर इनको बाहर के न्यूज़ पेपर पर ज्यादा विश्वास है तो वे उस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं।

महोदय, वह कह रहे थे कि मैं सीखता हूँ। हम सभी को सीखना चाहिए। जैसा कि हम सभी कहते हैं कि

करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
रसरी आवत-जात ते, सिल पर पड़त निशान।।

आप सीख रहे हैं, लेकिन क्या सीख रहे हैं? यह बहुत अच्छा है कि आप बहुत अच्छी बातें सीख रहे हैं। अभी आपने सिर्फ इतना ही सीखा है कि भाषण के दौरान आपकी जो भाव-भंगिमाएं हैं, कम से कम उनसे आप परहेज कीजिए, क्योंकि आप देश के बारे में बात कर रहे हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आपने अभिनंदन का नाम लिया है, इसलिए आप अभिनंदन कर लीजिए।

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): जी, अभिनंदन को अभिनंदन है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री जी के घर के बारे में जिक्र किया कि उनके घर पर मणिपुर के कुछ सदस्य गए थे।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी दो-तीन दिन पहले की बात है। हमारी बहुत ही प्यारी सांसद है, जो तमिलनाडु से आती है। वह मेरे घर पर अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने के लिए आई थी। जब मैं उनके पास पहुँची तो उन्हें देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वह बेयर फूटेड थी।… (व्यवधान)

महोदय, मैं अपनी बात तुरंत समाप्त कर रही हूँ। मुझे सिर्फ आधे मिनट का समय दे दीजिए। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यह परंपरा है। मुझे लगता है कि वे लोग विदेशों में ज्यादा भ्रमण करते हैं। हमारे तमिलनाडु, गुजरात तथा पूरे देश की क्या परंपरा है, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है।… (व्यवधान)

महोदय, मैं बस यह कहना चाह रही हूँ कि नेता के मन में जो बात होती है, वही बात हमेशा आती है। जैसा हम कहते हैं कि

कबीरी देखी परखी ले, परखी मुखों बुलाए
जैसी अंतर होएगी, मुख निकसेगी आय।

इसी तरीके से मैं जो आखिरी बात कहना चाहती हूँ, हमारे एक सांसद ने कल जिस तरह का बिहेवियर किया।

सभापति महोदय, आप भी यहाँ पर बैठी थी। आप तीन-चार बार की सांसद ही नहीं, बल्कि हमारी माँ समान भी है। उन्होंने इस तरह की जो बात कही, उससे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

2112 बजे

श्री एस. वेंकटेशन (मदुरै):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri **श्री एस. वेंकटेशन** in तमिल ,
please see the Supplement. (PP 400 A to 400 B)}

(2115/SNT/CP)

2115 hours

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, I rise to speak on the Motion of Thanks on the President's Address.

Painting a rosy picture of the dismal situation of the nation has been the trait of the present Government since it came to power in 2014. Similar was the scenario on 31st January, 2022 when the hon. President of India addressed the Parliament. Every sphere of failure has been covered with false promises and self-boasting of these promises being fulfilled.

The claims of the Government are absolutely different from real ground reality. In the current scenario, India has been performing poorly across all sectors be it education or healthcare or even for that matter as basic and crucial as the agriculture sector. The hon. President mentioned in his speech that the Government ensured food security for every citizen of India but India is experiencing a serious level of hunger. Over 35 lakh children in the country are severely malnourished and more than 10 lakh are actually malnourished. Imagine the level when the entire population is taken into account. So, the claim that every Indian manages three meals a day is absolutely false.

The hon. President mentioned that tele-law has benefitted 13 lakh people across the country by enabling legal advice but this is nowhere close to what is the actual need of the hour. More than 500 posts of judges are lying vacant across all 25 High Courts. Seventy-three thousand cases are pending in the Supreme Court alone, and taking all cases into account, a massive 44 million pending mark has been breached. Due to the unjust policies of your Government, 75 per cent inmates are under trial. Among them numerous might be innocent. Their lives are being destroyed. It is safe to assume that a large percentage of those dying in prison are not convicted of any offence. Despite the promises of article 21 that no person shall be deprived of his life or liberty except according to procedure established by law, the NCRB data reveals that the number of those dying in prison as they await their trials is only going up. Does an act like tele-law would be of no help? Instead of advertising, the Government should do what is actually required to be done.

The North-Eastern States found a place in the President's sugar-coated speech but the reality is very different from what he spoke. The unthoughtful

bogus laws of the Government have pushed numerous people into a state of mental torture. In a recent case, Manik Das, a resident of Borkhal village of Assam committed suicide because of the Government. The man was fighting a case in the Foreigners Tribunal in order to prove his nationality as an Indian despite the fact that his name was listed in NRC. He was still tagged as Bangladeshi while the rest of his family members were identified as Indians. This is just one case that I have highlighted. There are thousands of such cases and no one except the Government is to be blamed. The Government is tainted by the blood of farmers, citizens tagged as foreigners, migrant labourers, children, and the list is endless. The most distress fact among the current situation is that the Ruling Party has turned the temple of democracy into a mere ground of debating club where the Opposition puts forth their suggestions that go in vain. But it is now a known fact that the will of the Government will prevail in every domain without giving a heed to the minority. But then you must at least ensure that your will is rightful and reasonable.

The policies of the Government are so inefficient that MGNREGA workers are still waiting for almost Rs. 3,360 crore in pending wages payments with the largest pending payments in West Bengal. Due to inadequate allocation, West Bengal is suffering a deficit of Rs. 752 crore to be exact, which is the highest among all States.

(2120/NK/SRG)

I would take this opportunity to seriously demand the government to disburse the pending wages immediately. … (*Interruptions*). Madam, give me one minute. I am concluding.

Coming to the education sector, again the situation of India is worrisome. The education policy does not make English a compulsory medium of education, but is adamant to test their knowledge in government exams. Policies like these keep the urban-rural divide alive and make it a vote- seeking propaganda.

I would like to conclude by saying that in a situation where the country is suffering and people are looking up towards the Government with hope in their eyes, you are constructing a new Parliament building with the aim of providing "adhik suvidha" to the lawmakers that we do not want.

(ends)

SHRI V. MURALEEDHARAN: Madam, I want to refer to a speech which was made in this House some time ago today evening by the hon. Leader of the Congress Party. While he spoke, he referred to a letter supposed to be written by four former Service Chiefs including Laxminarayan Ramdas, Vishnu Bhagat etc. which is an unverified document. The Leader of the Congress Party is not the addressee in that letter. So, such a letter, which is an unverified document, should not have been referred here, should not have been brought up here. So, I suggest that such a reference should not be part of the proceedings.

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): अध्यक्ष जी, इसे देख लेंगे, ठीक है।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): माननीय सांसद, श्री तापिर गाव जी।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैडम, जबर्दस्ती मत कीजिए, वह जो कहेंगे वही रूल नहीं है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): इस चीज को अध्यक्ष जी देख लेंगे, आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

2124 बजे

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): माननीय सभापति महोदया, मैं यहां राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हम लोग ऐसी महामारी से गुजर रहे हैं, मोदी जी न होते तो हिन्दुस्तान कोविड में कैसे बच सकता। … (व्यवधान) अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने यह कहा है… (व्यवधान)।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैडम, यह सही नहीं होगा। … (व्यवधान)।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): इसे अध्यक्ष जी देखेंगे, प्लीज इनको बोलने दीजिए, यह गलत है, आप अध्यक्ष जी से बात कीजिएगा।

… (व्यवधान)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): माननीय सभापति महोदया, अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि अगर इंडिया की कोविड वैक्सीन न होती तो हिन्दुस्तान और दुनिया में और ज्यादा महामारी होती। … (व्यवधान) मैं मोदी जी, इंडियन साइंटिस्ट, हैल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत तारीफ करता हूं, प्रेसिडेन्शियल स्पीच में भी यही कहा। हैल्थ मिनिस्टर ने हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट बैठा दिया, आज हिन्दुस्तान सिक्योर है इसलिए मैं प्रेसिडेन्शियल एड्रेस का समर्थन करना चाहता हूं।

यहां कांग्रेस के नेता बैठे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को एक चीज बताना चाहता हूं कि इनके नेता ने कहा कि हिन्दुस्तान में दो भारत है, मेरी नजर में दो भारत नहीं है बल्कि तीन भारत है। एक भारत आक्साई चीन, जिसे नेहरू जी ने चीन को देकर रखा है, एक भारत पीओके, जिसको नेहरू जी ने पाकिस्तान को देकर रखा है और तीसरा भारत यह है, जहां हम खड़े हैं, यह तीसरा भारत है। हिन्दुस्तान के टुकड़े करने के लिए, हिन्दुस्तान को डिस्टबर्ड करने के लिए, गौरव गोगोई के प्रदेश में उल्फा का क्रिएशन किसकी सरकार के समय में हुआ।

(2125/SK/AK)

नागा में अंडरग्राउंड कैसे हुआ? मणिपुर में अंडरग्राउंड कैसे हुआ? त्रिपुरा में त्रिपुरा टाइगर कैसे हुआ? मिजोरम में कैसे हुआ? यह सब कांग्रेस की देन है। … (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से इस सदन को और देशवासियों को बताना चाहता हूं, जम्मू-कश्मीर हो … (व्यवधान) या पंजाब हो, उग्रवादियों को पैदा करना कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आज सुरक्षित है, जिसे प्रेजीडेंट ऑफ इंडिया ने रिप्ले किया। … (व्यवधान) उसके बाद कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश को कमजोर कर रहे हैं। मैं बताना चाहता कि किसके समय में देश कमजोर हुआ। मैं कांग्रेस नेताओं को बताना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू जी ने मणिपुर की कवाई वैली को मणिपुर के राजा और पब्लिक से सलाह-मश्वरा किए बगैर बर्मा के राजा को हैंडओवर किया। यह है देश को कमजोर करने वाले। … (व्यवधान) न बीजेपी, न आरएसएस, देश को कमजोर नहीं कर सकते हैं। मैं यह देश को बताना चाहता हूं। … (व्यवधान)

महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सारे प्रदेश गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान से जुड़े हैं। मोदी जी के आने के बाद अरुणाचल रेलवे से

कनैक्ट हुआ। कालपिचु मणिपुर में रेलवे से कनैक्ट हुआ। प्रेजीडेंट के भाषण में यह उल्लेख हुआ कि अरुणाचल प्रदेश ईटा नगर में होलोंगी एयरपोर्ट 15 अगस्त 2022 में इनऑगरेट किया जाएगा। त्रिपुरा में टॉप क्लास एयरपोर्ट बना रहे हैं। आज हम रेलवे से जुड़े हुए हैं। पहले अरुणाचल कहां था, मणिपुर कहां था, मेघालय कहां था, देश के लोग नहीं जानते थे। आज चेहरे से भी पहचानते हैं कि तापिर गाव अरुणाचल से है। गौरव गोगोई के चेहरे से लोग पहचानते हैं कि असम से हैं। यह मोदी जी के दिन हैं, मोदी है तो मुमकिन है। … (व्यवधान)

मैं अधीर रंजन साहब को एक चीज बताना चाहता हूं, चाइना हैज़ क्लियर विज़न एंड प्लान्स - यह कांग्रेस नेता ने कहा। इसका विज़न कांग्रेस नेता को ही मालूम है, जिन्होंने बीजिंग में जाकर जिनपिंग के साथ एग्रीमेंट किया। अधीर रंजन साहब, उस एग्रीमेंट में क्या प्वाइंट था, यह देशवासी जानना चाहते हैं। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):, सरकार आपकी है, तफ्तीश कीजिए।… (व्यवधान)

श्री तापिर गाव (अरूणाचल पूर्व): मैं कनकलूड करता हूं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री तापिर गाव (अरूणाचल पूर्व): मैं एक चीज बताना चाहता हूं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपने बहुत बता दिया है। इन्हें बोलने दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री तापिर गाव (अरूणाचल पूर्व): दोलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट को कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर ने रिवाइज़ किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सप्लेनेशन कॉल किया। क्यों? लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी को रिवाइव किया। … (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति: श्री मलूक नागर जी।

2126 बजे

श्री मलूक नागर (बिजनौर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। … (व्यवधान)

जहां बिधूड़ी साहब आ जाते हैं वहां लफड़ा ज्यादा पड़ जाता है। वह तभी थमेगा जब मैं बोल पाऊंगा। … (व्यवधान)

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत सारी चीजें हो सकती थीं। दलितों, गरीबों, मजलूमों और पिछड़ों के लिए, अगर नहीं हैं तो मैं मानता हूं कि इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष के लोगों से बढ़िया तरीके से भूमिका अदा नहीं की जा सकती है, जिसकी वजह से ये लोग इतने हावी हो गए हैं और ये जो चाहते हैं, कर पाते हैं।

(2130/MK/SPR)

अभी किसानों के बारे में पिछले 70 सालों से दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ और अक्लियत के लोगों के साथ अन्याय होता रहा है। अब जाकर माहौल बना है। अब लगता है कि पिछड़ों और दलितों को न्याय मिलने वाला है। इसी सदन में जब माननीय प्रधान मंत्री जी आकर बोलते हैं कि पिछड़ों में इतने मिनिस्टर बनाए गए और दलितों में से इतने मिनिस्टर बनाए तो लगता है कि न्याय मिलेगा। पता नहीं हमारे पड़ोसी क्यों कूदते हैं? अबकी बार ऐसा लगा है। परसों जब राहुल जी अभिभाषण पर बोलने के लिए आए तो कई बार मजाक और व्यंग्यात्मक बातें हुईं और कई बातें उन्होंने अच्छी और गंभीर भी कहीं। लेकिन, आज यह नोट करने वाली बात है। मैं कांग्रेसी साथियों से कह रहा हूं कि ये इतना माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं, जिनको हमें झेलना है। उनकी कोई काट नहीं है। आज जब अधीर रंजन जी बोल रहे थे तो माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी आकर बैठ गए और उनकी पूरी बातों को सुना। इनका जो मन आया, वह बोला। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री जी पूरी तैयारी में हैं। जब वे सोमवार को बोलेंगे तो राहुल गांधी जी ने जो एक साल की तैयारी की है, वह सब साफ हो जाएगी। आप रोज ऐसी ही तैयारी कीजिए, जिससे बिधूड़ी साहब की पार्टी इतनी हावी न हो पाए। गरीबों, मजलूमों और कमजोरों के लिए बढ़िया तरीके से अब उम्मीद जगी है। माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच देखकर लगता है कि अब उन्हें न्याय मिल सकेगा। … (व्यवधान)

महोदया, मैं जम्मू-कश्मीर से संबंधित कुछ बातें कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): मलूक जी के बाद सत्यवती जी बोलेंगी। उसके बाद जीरो ऑवर तक समय बढ़ाया जाता है, यदि सभा सहमत हो?

अनेक माननीय सदस्य: मैडम, हम सहमत हैं।

माननीय सभापति: आप सभी सहमत हैं, तो ठीक है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: इनको बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री मलूक नागर (बिजनौर): मैडम, मुझे जम्मू-कश्मीर के बारे में कुछ कहना है, जहां आजादी के बाद से ही गरीबों, दलितों और खासकर के गुज्जर बकरवाल के साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण होता रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: पीछे आपके मेम्बर बोल रहे हैं। आप नियम तोड़ रहे हैं।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): मैडम, यह मानसिकता पिछले 70 सालों से अधिकारियों की रही है। जब यहां पर गृह मंत्री जी जम्मू-कश्मीर के गुज्जरों के बारे में खड़े होकर अपने मुंह से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार की सोच अच्छी है। वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उनकी सोच भी अच्छी है। लेकिन, पिछले 70 सालों से जो अधिकारी हैं, उनकी मानसिकता ही ऐसी हो गई है। पिछले दिनों उन्होंने एक मुहिम चलाई है, जो गुज्जर बकरवाल और वन गुज्जर हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। जबकि, अधिनियम, 2006, सेक्शन-4(5) के नियम और कानूनी प्रावधानों के अनुसार पुरानी आबादी स्वत: राजस्व गांव डिक्लेयर हो जाता है। मैं आपके द्वारा मांग करता हूं कि उनको अधिनियम, 2006, सेक्शन-4(5) के अनुसार राजस्व गांव डिक्लेयर किया जाए। उन्हें नहीं उजाड़ा जाए। अगर, जमीन की जरूरत हो, तो वर्ष 2014 का जो भूमि अधिग्रहण अमेंडमेंट बिल है, उसके अनुसार उनको सर्कल रेट का चार गुना मुआवजा देकर जमीन ली जाए, ताकि उनका घर बना रहे, उनके बच्चों की रोजी-रोटी चलती रहे, वे जानवर पालते रहें और उन्हें न्याय मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

2134 hours

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Madam, the hon. President of India in his Address has shared with the people of India the Government's vision of a prosperos India. The Address was full of aspirations and quite clearly highlighted the Government's policy priorities and plans for the upcoming year.

First of all, I congratulate the Union Government for effectively controlling COVID and vaccinating crores of people of India in a very fast manner. Being a medical professional, I am very thankful to this Government.

(2135/UB/SJN)

In this context, I want to congratulate the Union Government on sanctioning 13 new medical colleges with the Central funds. Our hon. Chief Minister, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy Garu, is concentrating on health and education as his two eyes under Nadu-Nedu Programme.

2135 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

Hon. Speaker Sir, through you, I want to request the Central Government, since ours is a divided State, that we need a lot of support from the Central Government, and a special status for my State was also promised in this august House.

Our hon. Chief Minister Garu has sanctioned 16 new medical colleges. Three medical colleges are already sanctioned and funds have been granted by the Central Government. Rest of the thirteen colleges in my constituency are also there. Mine is a newly formed constituency, Anakapalle, and each parliamentary constituency gets a medical college is the target of the Central Government. I welcome and thank the hon. Union Minister for this.

I want to quote a poem which was also quoted by the hon. Prime Minister in his 'Mann ki Baat'. It is a poem written by a great writer and great social reformer who was born in a small village of my parliamentary constituency, Shri Gurajada Apparao Garu:-

“దేశమును ప్రేమించుమన్నా
మంచి అన్నది పెంచుమన్నా
వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయ్
గట్టి మేల్ తలపెట్టవోయ్

పాడిపంటలుపొంగి పొర్లే
దారిలో నువు పాటు పడవోయ్
తిండి కలిగితె కండ కలదోయ్
కండ కలవాడేను మనిషోయ్ "

It means that you love your country and you love your people also. So, you should be for the welfare of the people of this country. In this context, "పాడిపంటలు పొంగి పొర్లే దారిలో నువు పాటు పడవోయ్" means we should uplift the farmers of this country.

I want to mention a few points regarding the farmers because the hon. President mentioned in para 14 that the Government's top priority is being given to the villages and the poor, but the Government in the present budget, sorry to say this, has reduced the fund for MGNREGA. So, through you, Speaker Sir, I want to request the Government to provide employment and corresponding material wages to the workers putting up a stellar show in implementing the MGNREGA Scheme.

I hail from Visakhapatnam district. Anakapalle is a new district and a new constituency. Visakhapatnam Steel Plant, which is our steel plant, is running in profits and when it was established, almost 23 people sacrificed their lives. "Visakha Ukku, Andhrula Hakku Ninadam Tho" -- people of the Andhra Pradesh. Like Farmers Bill, please take back the disinvestment policy. It is a request from our hon. Chief Minister Garu and all the parliamentarians from my State.

I have one more request regarding GST. There is GST on farm equipment and e-learning gadgets. There is a strong need to rationalise GST in agriculture sector to boost farm mechanisation as mentioned in the Address. The record-breaking collection of Rs. 1,40,986 crore is the highest since the inception of GST. With such a high collection, the Government must look forward to reducing the GST on farm machinery from 12 per cent to 5 per cent to support the farmers of the nation.

Since the hon. Prime Minister has said it in so many meetings about the connectivity to Varanasi, we have a long pending demand of a regular train from Rajahmundry to Varanasi via Vishakhapatnam because from River Godavari to River Ganga, people make holy dips. They perform prayers for the demised

people. So, this is my request through you, Speaker Sir, to the Union Government.

Since the hon. Health Minister is also here, I want to request him to open two trauma care centres in Anakapalle district hospital and in one area hospital at Anakapalle because they are nearby the national highway and so many accidents occur there. Please sanction two trauma care centres from the Central Government for my parliamentary constituency. Thank you very much for giving me the opportunity. Please help the State of Andhra Pradesh because it is a divided State.

(2140/KMR/YSH)

Sir, many promises were made by the Union Government in this august House to our newly divided State of Andhra Pradesh. Our hon. Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy *garu* is trying to develop our State in a very positive manner. Our State is in the third position in the country in the development rankings. If you can give the financial support to our State as promised, we can flourish and become the model State in the country. Thank you very much, Sir. Jai Hind!

(ends)

*SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The people of this country expected a lot from the address by our Hon'ble President this year too, but were greatly disappointed as the address lacks direction and the way the government intends to move in the year ahead. Therefore, I strongly oppose the address. However, I would like to highlight here some of the issues that were found no place in the entire address such as:

The word Amrit Mahotsav found at many places in the entire address of the Hon'ble President, but no mention has been made about the supreme sacrifices of our 20 jawans who have been killed in Galwan Valley at the hands of our enemy, China and China is posing very serious threat to our nation's security than ever.

The country has lost its first Chief of Defence Staff and 13 other defence personnel in a helicopter crash very recently, again no mention about this tragic loss in the address.

14 innocent people were killed by the army wrongfully in Nagaland very recently, and again no mention about this brutal killing and how it has happened.

Bhagwaan Birsa Munda was a great freedom fighter and he was a Gaurav for the entire nation. Therefore, celebrating his birth anniversary as Jan Jatiya Gaurav Diwas, as mentioned in the address, is really disrespecting him instead of honouring him and his contribution, as no celebration can be attached with the name of caste or religion he or she belongs to.

It is now more than two years that we are experiencing Covid-19 pandemic, no mention been made in the address as to how the government has failed to vaccinate the entire population of the country. Several crores of people are yet to get even the first dose.

The address has failed to acknowledge the benefit of the Green Revolution brought out by our then Prime Minister, late Smt. Indira Gandhi, when the government takes the credit of providing food during Covid-19 pandemic.

There has been no mention in the address that when will the government be able to make rules against the Citizens Amendment Act, 2019. The bill was passed by both the Houses of Parliament in the year 2019 and 83 people have lost their lives while protesting against it. Very sorry to state that even a starred

---

* Laid on the Table

question of mine laid for answer on 8.2.2022 in this regard has been simply taken off to unanswer it.

It is really surprising that no mention has been made in the address about more than 700 farmers who have lost their lives while protesting against the three farm bills brought out by the government and later on withdrawn them.

Our annadatas have been demanding for a new Minimum Support Price guarantee law for all agricultural produce, but no mention has been made in the address in this regard.

The global demand for Indian ayurved products is increasing day by day, but the government is yet to take steps to boost this sector, and moreover, no mention has also been made in the address in this regard.

In the address it has been stated that 1 crore 17 lakh houses have been approved at a cost of Rupees one and a half lakh crore in the last three years under Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin, but no mention has been mentioned that how many have been constructed and handed over to the beneficiaries during the said period as there have been reports that the scheme is moving at snail's speed.

As per the address 2 crore 25 lakh youth across the country have been skilled through various forums, but the fact is that these trained skilled youths have no employment for most of them. Therefore, this address lacks the number of youths skilled who have got employment because of the skill development they got.

High cost for all input materials and non-availability of some of the important input materials are the burning issues the MSMEs are facing now. This address has no word on how to help these MSMEs which are the main sources of employment in the country.

Covid-19 pandemic added further loss of employment in the country and the people are facing difficulties to meet their day to day needs. The high cost of petrol and diesel pushed the prices of all essential commodities at an all-time high. However, no mention has been made in the address how to provide relief to the people.

Now I come to some of the issues that are concerning the State of Kerala, the State which I belong to. It has been a demand of the people of Kerala to set up an AIIMS in the State as this State does not appear in the list of 22 AIIMS the

government has initiated. Therefore, I urge that an AIIMS be sanctioned for the State of Kerala and Palakkad is the most ideal place for the same to be set up there, as it is centrally located in the State. Land has been acquired which is lying unused and is in the custody of the Central government. Apart from that, an institution is also willing to offer its giant campus of more than 500 acres with requisite infrastructure for the proposed AIIMS. The proposed AIIMS at Palakkad, can also put an end to the continued infant child mortality in Attappadi which is a tribal area due to lack of medical care there. This will also benefit people of various districts in the neighbouring State of Tamil Nadu too. Therefore, setting up an AIIMS at Palakkad will benefit people of two States. Therefore, it is requested that AIIMS be set up at Palakkad at the earliest.

Palakkad, which is my parliamentary constituency, is a centrally placed district in the State of Kerala and adjoining to the State of Tamil Nadu. Airports for the people of Palakkad are at Nedumbassery, Karipur and Coimbatore having a road distance of 113 kms., 101 km. and 69 kms respectively. Palakkad is the second largest industrial district in Kerala, having all types of industries, including both central and State governments public sector undertakings. The only IIT in the State of Kerala is at Palakkad. Palakkad is also the divisional headquarter of Southern Railway. The work on the Industrial Corridor between Coimbatore and Kochi via Palakkad is in progress. Palakkad is the gateway for reaching all materials to the State of Kerala from many parts of the country. More-over, many thousands of people from this district and its neighbouring district are settled in many parts of the globe, earning precious foreign exchange for the country. The proposed Coimbatore-Kochi Industrial Corridor is expecting huge foreign Investment. Hence, it is necessary and essential to have an airport at Palakkad to make travel to/from Palakkad easier. Therefore, I urge that Palakkad may also be included in the airport expansion plan of the government.

There has been a long pending demand to take steps to get UNESCO heritage site status for Edakkal Caves in Kerala, but this address has no mention of this. Getting UNESCO heritage site status for these caves at Edakkal shall pave the way for attracting more tourists to this place and thereby economic development of the area in which these caves are located. With this I conclude and I oppose the address.

Thank you.

(end)

*SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): The President's Address is a big disappointment and reflects the Government's failure.

According to Oxfam Report, the corporates and rich get richer and the poor get poorer.

The Government has approved women to join the National Defence Academy but it is submitted to the Court that women cannot be given commander post equivalent to that of men.

Cochlear implant surgery which finds a mention in the President's Address was first implemented free of cost by our leader Dr. Kalaignar in Tamil Nadu in 2010.

The President had quoted a couplet from Thirukural, but the Government is not following the ideals of the Constitution.

Thank you very much.

(ends)

* Laid on the Table

*SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Respected Speaker sir,

1. I am very thankful for the opportunity given to me.
2. We are very thankful to the Honourable President, for reminding us about the words of the Chief Architect of our constitution Dr.Baba Saheb Ambedkar that the society should be based on liberty, equality and fraternity..... and Democracy and not merely a form of Government. And assuring the country that the present Government in social justice, equality, respect and equal opportunities as the mantra of Antyodaya.
3. We are very happy to note that the present Government has decided to celebrate the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda on 15th November as a 'Jan-Jatiya Gaurav Diwas' and from this year onwards to celebrate to start the Republic Day celebrations from January 23rd which is a birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose.
4. The measures taken by the Government to vaccinate 90% of the adults out of which both the doses given to 70% of the adult citizens is remarkable and appreciable.
5. The health infrastructure mission with an allocation of Rs. 64000/- crores hopefully will meet the demands in the coming years.
6. Providing free ration to 80 crore beneficiaries in the last 19 months and extending the same up to March 2022 is a big relief to the poor.
7. It is appreciable that the Government has approved 117 lakhs houses in the last three years. However, it is estimated that there is a requirement of 25 million houses by 2030, under 'housing for all', in the backdrop of fast urbanization.
8. Jaljeevan Miss really eated greater relief to the women of six crore households by accessing tap water connection. But nearly 15 crore households are without piped water in rural areas are inviting. This number may be higher than this. It is also a fact to note that seven states in the country water table depleting rapidly. But it is a long way to go.
9. In the agricultural sector 80% of farmers belong to small and marginal category with less than 2 acres of land. The PM SAMMAN Nidhi amount

---

* Laid on the Table

need to be enhanced from Rs. 6,000/- to Rs. 10,000/- as requested by the Chief Minister of Andhra Pradesh Sri. YS. Jangan Mohan Reddy.

10. I am thankful to the Prime Minister for sanctioning the Kisan Rail which is a first in south India and second in the country which was started in Anantapur of Andhra Pradesh which is also my Parliament Constituency. So far 122 trips of trains from AP to Delhi and other places were run by the Department to meet the demand of Horticulture production.
11. The issues related to Minimum Support Price (MSP) purchase and procurement of the produce of the farmers need to be taken into consideration.
12. Creating a provision for Gender Inclusion fund in the national education policy and admitting women cadets in the National Defence Academy is paving ways for equal opportunities for women. However, there is a decrease in the budget allocations from 3.8 % of the spending in 2015-16 to 2.7% allocation in 2021-22 There is a need to relook into the spendings.
13. The opening of Ekalavya Model Residential Schools is a welcome step to provide quality education. But budgetary allocations to provide infrastructure, teaching staff and other support staff need to be taken care of. Sufficient budget allocation is the need of the programme to achieve its success.
14. Divyang facilities should be taken on a priority basis. The Data suggests that there are seven crore population in the country who are Divyang. Establishing National Institute of Mineral Health Rehabilitation and developing a 10,000-word Indian Sign Language Dictionary is appreciable.
15. Reference to the development and security of Scheduled Castes is totally missing in the speech.
16. As part of Atmanirbhar Bharath, increasing the support to MSME through guaranteed collateral free loans from rupees 3 lakh crore to Rupees 4.5 lakh crore is a welcome step. However, the employment loss during the COVID- 19 pandemic is huge. It is estimated that 35% of MSMEs either closed or de functional as a result of the pandemic. The Government needs to create some more supports to the MSME sector.

17. It is also estimated that India's unemployment rate has reached to nearly 8%. Announcing an urban employment guarantee programme might have given hope to millions of urban labour in the country.
18. Developing infrastructure facilities like roads, railways, airports, higher Education institutions in north east and Jammu, Kashmir and Ladakh is very much needed and the steps taken by the Government is very much appreciable.
19. As a Member of Parliament coming from the state of Andhra Pradesh which is affected by the bifurcation in 2014, we are consistently urging the government to provide Special Category Status (SCS) for the state to overcome the problems inherited. However, in the Hon'ble president speech the sanction of the special category status is missing.
20. Similarly, the supports promised in the AP Bifurcation Act 2014 are also not proclaimed in the speech of the Hon'ble president.

We whole heartedly thank the President for the commitments towards health, creation of water resources, employment and farmers' welfare.

Thank you Speaker Sir,

(ends)

*SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Hon'ble Speaker Sir, thank you for permitting me to speak on Motion of Thanks to the Hon'ble President for his address to the joint session of the Parliament.

This is the Amrit Mahotsav year of India as the country is celebrating the 75th year of independence. The Hon'ble President Address of this very important year, is full of confidence and having many significant things in terms of how to develop country with a view to pay respect to the great heroes of the country.

With regard to Housing for All by 2022, I would like to say that it is a very good initiative by the Union government, But the scheme is not properly implemented and real beneficiaries are not getting the benefits of the Housing scheme.

However, there is a need for review of the implementation of the scheme. Out of the total 4.3 crore persons earmarked for the scheme, only 2.32 crore have become eligible after verification by Gram Sabhas, The possibility of a politically motivated approach in identification of beneficiaries. To ensure proper identification of beneficiaries, So, there is a need for downsizing the role of Gram Sabhas and Panchayats in identification of beneficiaries and roping in private/ non-governmental bodies for verification and authentication.

I would like to suggest that the government should take necessary steps to streamline the identification of beneficiaries for incorporation of a block development officer for oversight and also to take steps to transferring ownership of the housing unit to the designated nominee after the death of a beneficiary. So that real beneficiaries would get the benefits of the scheme.

The overall economic, employment situation in the country has been a matter of grave concern for all of us due to Covid-19 led crisis. The widespread havoc that it inflicted on the economy.

MSP:

While MSP is announced for 23 crops every year, public procurement is limited to a few crops such as paddy, wheat, and, to a limited extent, pulses. I am of the opinion that the government should take necessary steps to procure more crops to help the farmers. The BJP on the demand of minimum support price plus 50%, gave a version that satisfied no one.

There are reports on shortcoming in the implementation of MSP. Mainly, procurement is largely from a few states. And lack of awareness among farmers

* Laid on the Table

before the sowing season. Increasing cost of transportation for farmers, and also there is an inadequate storage capacity.

Therefore, I would like to suggest that the government should address these issues to ensure benefits for the farmers.

| would like to suggest that the agricultural pricing policy needs to be reviewed to ensure that farmers are receiving remunerative prices for their produce. Farmers are often forced to engage in distress sales, i.e., selling below MSPs.

Ethanol blending programme:

India has a real opportunity to become a global leader if it chooses to focus strongly on ethanol made from a by-product of the sugar industry, namely molasses and farm wastes. This would help our farming community and also bring a strong climate and air quality benefits, since these wastes are currently often burned, contributing to smog. Therefore, I would like to suggest that the government should take firm steps in this regard to provide benefits to the farming community particularly for sugarcane growers.

Inadequate Kannada as a classical language:

India is one of unique countries in the world that has the legacy of diversity of languages. Among these three languages, Sanskrit, Tamil and Kannada have been recognized as classical language with special status and recognition by Government of India.

The government is not funding adequately for the promotion of Kannada as a classical language.

Classical language Kannada Rs.1 crore in 2017-18, Rs. 0.99 crore (Ninety-Nine lakhs) in 2018-19 and Rs. 1.07 crore in 2019-20.

Rs 643.84 crore on the promotion of Sanskrit in the last three years, which is 22 times the total amount of Rs 29 crore spent on the other five classical Indian languages - Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Odia.

During the same period the funds given to Tamil was Rs. 10.59, Rs. 4.65 and Rs. 9.80. Rs. 11.73 crores allocated during 2020-21. Till date Tamil language received nearly Rs. 50 crores. However, it is only Rs. 8 crores to Kannada language.

Hence I urge the union government to do justice to Kannada language and people of Karnataka by releasing adequate funds.

Environmental impact assessment should be made scientifically:

As far the **environmental impact assessment** to give approval for industrial, real estate and mining schemes is concerned it is not being done scientifically to assess the impact of industrial, real estate and mining schemes on the environment

and lead to an unhealthy competition amongst these agencies to swiftly clear projects without due diligence. There is huge concern among people and widespread criticisms against the way the EIA is being done.

Hence at a time when climate change is driving home the ecological fragility of large parts of India and pollution and water scarcity are taking a serious toll on the well-being of people in cities, towns, and villages,

Regulatory bodies require enabling policies to perform their task with riger. The grading exercise, Instead, reduces them to clearing houses. The Centre must rethink its move.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana:

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has also benefitted small farmers of this country. The issues being faced in the implementation of the scheme is that due to lack of awareness, several farmers do not submit declaration forms to opt out of the scheme and face mandatory deduction of premium from their bank accounts, and also there is inordinate delays in settlement of insurance claims. There is also delays in taking action against defaulting insurance companies by the government. Therefore, in order to address the problems, the government should use technology and the coordination of all institutional mechanisms.

One Nation, One Ration Card (ONORC) is implemented by the union government successfully to ensure pan-India availability of food grain entitlements to beneficiaries through portable ration cards and Aadhaar based authentication. 34 states and union territories have implemented the ONORC plan as of August 24, 2021.

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi :

In order to provide expenditure support to these farmers, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi is implemented. However, the scheme is being faced in the implementation of the scheme. They are mainly slow pace of identification of beneficiaries and uploading of data by states, and poor internet connectivity in rural areas hampering the uploading of data and some other issues. Therefore, I would like to suggest that the government enhance coordination with states where enrolment is slow and take corrective steps to ensure the poor farmers are benefitted from the scheme. With these words I conclude my speech. Thank you.

(ends)

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Sir, I would like to give my views on the Motion of Thanks on the President's Address delivered to both the Houses of Parliament on 31.01.2022.

In the wake of high price rise and the prices of petroleum products skyrocketing, there is not a word about it in the President's Address. The policy of the BJP Government, namely, one nation, one language, one culture, one registration, is highly condemnable. India is a secular democratic country having federal structure. You will find unity in diversity and that is the beauty of this nation. Therefore, we strongly oppose any move by the Union Government to thrust one culture, one language, one view on various States.

Similarly, of late, the names of all the schemes and development programmes are being given in Hindi language and no English translation is provided. With the result, the people from non-Hindi speaking areas, in fact, MPs also, are confused about the purpose of schemes. Though the Centre is spending crores of rupees on these schemes, hon. Members are not able to explain to the people about the aims and objectives of these schemes. Therefore, it is our demand that names of all the schemes and programmes should be given in the English language also so that the people in the South can understand and take benefit of these programmes.

According to estimates of Centre for Monitoring Indian Economy, two crore Indians lost their jobs in April-May, 2021. In October, 2021, at least, 5.46 million Indians lost their jobs and in November last year, six million salaried people lost their jobs. There is no mention in the President's Address about this alarming loss of jobs in the country due to policy paralysis of the Union Government. This Government assured before coming to power that there will be creation of jobs for two crore unemployed youth every year. This is the real picture that the Centre for Monitoring Indian Economy has assessed. This is the real picture of equality among the richest, rich, middle class, marginalised and the poorest of the poor of the country.

Similarly, the recent amendment proposed to IAS Cadre Rules is arbitrary and an attempt to undermine the executive powers of the States. Already nine Chief Ministers of our country, including our Chief Minister of Tamil Nadu have

---

* Laid on the Table

vehemently opposed this unilateral and arbitrary decision of the Union Government.

The Constitutional Heads in the Opposition-ruled States are behaving like political functionaries and interfering with the day-to-day administration of the States and challenging the policy decisions of the elected Governments of the Opposition-ruled States. NEET Exemption Bill passed by the Tamil Nadu State Assembly, is a glaring example. The Governor did not forward the Bill for the President's assent and he was sitting over all these months. Now, due to pressure from our side, the Governor has sent back the Bill to the State Assembly to reconsider the Bill with the remark that NEET examination is good for the people of State. It is nothing but an insult and a disrespect to the sentiments of the people of Tamil Nadu.

The farmers' unions have given a press statement exposing the empty promises of Government on MSP and doubling farmers' income. It is because the Government said that we would increase the farmers' income by 200 per cent but now it is not so. Their input costs have increased. The DAP and urea which was Rs. 1,300 is now Rs. 2000. There is no mention in the Address about fixing the Minimum Support Price of various agricultural products and also to provide legislative backing to Minimum Support Price mechanism. The MSP has not been increased. Basically, eighty per cent people of the country are agriculturalists. Even during the COVID pandemic, India had food sufficiency because of our agriculturists but you are destroying the efforts of the farmers.

You are giving 5G technology to the private sector but not even 4G to BSNL and MTNL. It is a silent way of killing the public sector undertakings like BSNL and MTNL.

The MSME sector is in a difficult position. First it suffered a severe blow because of demonetisation and the hasty implementation of GST. The States surrendered their sovereignty of collecting taxes but the promise that was given by the Union Government that it would give its due share to the State Governments has not yet been fulfilled. The due share has not been paid to many States. It is the States which are collecting the GST but you are simply taking that money and not re-distributing to the State Governments.

The attack on fishermen of Rameswaram and Nagapattinam while they were on high sea for fishing, by Sri Lankan Navy is continuing uninterrupted despite our protests and agitations. The Centre has not tried to bring any

permanent and effective mechanism to find a permanent solution. No steps have been taken for controlling and reducing the prices of petrol, diesel and other petroleum products. The workers have been demanding increasing the EPF minimum pension to Rs. 9000 by implementing the orders of the court for higher pension on the basis of actual wages. But this Government has not taken any step in this direction.

I highly condemn the attitude of the Government in rejecting the Republic Day Tableau depicting the portraits of freedom fighters from Tamil Nadu, as was proposed by the Government of Tamil Nadu, thereby hurting the sentiments and patriotic feelings of the people of Tamil Nadu.

The President's Address does not mention about the alleged purchase of Pegasus software for spying and unauthorised interception of messages and audio conversations by probing and investigating agencies, leading to manifestation of arbitrariness and violation of fundamental rights of citizens. The President's Address also does not mention about the need to provide ex-gratia compensation to the kin of all doctors, including private practitioners who lost their lives in the line of duty during the second COVID wave in the country. We have been demanding the Union Government to restore travel concessions to various categories of railway passengers in the Indian Railways but it has not been done.

The President's Address also does not refer to giving facilities for the upliftment of women belonging to the backward and rural areas of the country. There is no mention about the need to provide immediately all basic facilities like fixed wages, insurance, risk allowance to ASHA, Anganwadi workers and village health workers who worked as frontline workers during the pandemic.

In view of all these omissions and misgovernance, I strongly oppose the Motion of Thanks on the President's Address delivered to both the House of Parliament.

(ends)

*SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks moved by Shri Harish Dwivedi to President for his Address to Parliament.

Sir, it is a mandate under Article 87 given to the hon. President to Address both the Houses at the beginning of every year essentially to highlight the Government's policy priorities, what it had done the year gone by and what plans and programmes it has for the coming year. And, Sir, President Address is one unique instrument available to the Members of this House to speak their heart out and I am here to speak from the core of my heart on behalf of the people of AP and submit my views before the hon. Prime Minister, since he is the head of the executive, and appeal to him for sprinkling a few drops of 'Amrit' on AP as it swallowed 'Garala' in the form of bifurcation and has been suffering since then.

Hon. President has said and rightly so that we are into the third year of pandemic. And, one can imagine the plight of a State which was crushed in rush ruthlessly, further ruined by misgovernance for five years and devastated its economy by pandemic during the last more than two years. Sir, my State is in this state. The country is completing its Amrit Mahotsav and entering into Amrit Kaal. But, AP is still, as I said, screaming for a few drops of 'Amrit' that the PM is offering to the other parts of the country. So, I am deeply anguished, pained and frustrated that neither the President's Address nor the Budget has given a few drops of 'Amrit' to AP. Hence, I am standing here to pitch my voice, the voice of my party, the voice of the people of AP for AP.

Sir, I am deeply perplexed as to where should I start from; should I start from unscientific bifurcation made by Congress Party in 2014 or should I start from what this Government has been doing for the State of AP since June, 2014. Sir, Government is a continuum. It is like a relay race where batons change hands from one participant to another with an overall intent of reaching the destination. But, here, the baton is with 'Usain Bolt' of India and we expected that he alone is enough to take AP to its destination and no need to exchange the baton. And, this is precisely the reason why people of AP gave a thumping support to our hon. PM, Shri Modi, in 2014, anticipating that he and he alone can take the State to its destination. But, it appears that this 'Bolt' is not fixing the 'blots' of AP. Sir, AP is

---

* Laid on the Table

on the brink and if Union Government does not come to its rescue, it will be gloomed and doomed.

Sir, AP Reorganisation Act passed in 2014 and the Act given mandate to the GOI to implement certain provisions. I am not denying that GOI is not implementing them. It is implementing, but look at the pace with which things are moving. We are into 8th year of its implementation, but not even a single project has been completed, be it relating to educational institutions or Polavaram or Railway Zone or setting up of a major port or steel plant or crude oil refinery and petrochemical complex or industrial corridor on the lines of Delhi-Mumbai Industrial Corridor or metro and the list goes on. Not even a single project is completed. Why? I want answer to this from the hon. PM. The people of AP wanted answer from the hon. PM.

Sir, before touching other issues, I wish to first focus on issues plaguing the State of AP and appeal and pray with folded hands to the PM to, at least, now show your magnanimity and compassion towards the State of AP and don't add AP to BIMARU. Sir, when AP was divided, it was burdened with huge revenue deficit of Rs. 16,078 crores and it was assured on the Floor of Parliament on 20th February, 2014, by none other than the PM that the resource gap of AP would be compensated through regular Union Budget. And, if you look at the accounts for FY 2014 15, audited by CAG, the revenue deficit is Rs. 16,078 crores and, in addition to this, there are other financial obligations pertaining to that period that have not been discharged due to shortage of funds which has rightly been regarded as part of resource gap for 2014-15 and the total resource gap comes to Rs. 22,948 crores. This is the 8th Budget people of AP seen expecting that provision would be made in the Budget. But, the 'bahu' of Telugu States disappointed again. Secondly, in the recently held South Zone Council meeting, hon. Minister assured that he would reconsider the issue and resolve the matter and we were expecting that provision would be made in this Budget, but nothing has been provided for. So, I request the hon. PM to kindly intervene and see that the resource gap of Rs. 22,948 crores be paid to AP and don't wash away. by just paying Rs. 4,117 crores.

The next point is about Polavaram. Things are not moving smoothly since R&R package has to be executed and for this, we need money. Since it is the National Project, it is the responsibility of the GOI to release sufficient funds to complete the project which aims to be completed this year. Sir. Technical Advisory

Committee and the Revised Cost Committee - both are the Committees of the Government of India - have given their approval for revised cost estimate of Rs. 55,656 crores. People of AP were keenly looking at the Budget that the FM may approve the revised cost estimates. She again disappointed the people of AP. There are 2-3 issues relating to Polavaram and I wish to place them again before the hon. PM and request him to clear them. The first one is pending bills to the tune of Rs. 2,100 crores which are still pending for clearance by GOI. The second one is that the Ministry is hell-bent not recognizing supply of drinking water as part of irrigation component. Sir, we have had National Projects in the country earlier and take any project and see whether drinking water has been made part of irrigation component or not. Why are you separating drinking water with irrigation and how come that you are propounding a new theory that drinking water does not become part of irrigation component for Polavaram? So, Sir, don't do that. Secondly, the cost of the project has gone up, not because of AP. It is because of the Central legislation of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 since huge amount has to be paid to the project displaced families. So, Sir, don't negate what Section 90 of AP Reorganisation Act says and immediately approve the revised cost estimates and help State Government to complete the project this year.

Sir, the hon. President talked about giving free foodgrains to poor and migrant labour and we all welcome that since it is the need of the hour in the times of pandemic and we all welcome this. Sir, we have distributed nearly 700 lakh metric tons of rice with an estimated cost of Rs. 2.65 lakh crores in 5 phases under PMGKAY. But, I wish to point out here that there is a section of poor in AP who are left out under NFSA. Let me give the details. Sir, beneficiaries under TPDS are selected as per NFSA. And, if you look at the national average of beneficiaries covered under the TPDS, it is 75% of the rural population and 50% in urban population. But, when it comes to AP, the number of persons covered under TPDS is 2.68 crores which translate into 60% in rural areas and 40% in urban areas which is much below the national average of 75% and 50% respectively. And, Sir, surprisingly, the States which have higher GSDP than AP are given higher percentage of coverage! Let me give some examples. Sir, 76% of population is covered in Karnataka whose per capita GSDP is Rs. 2.27 lakhs. In Gujarat, 76.64% of population are covered under NFSA and its per capita GSDP is Rs. 2.22 lakhs. 62% is covered in Tamil Nadu and 76% population is covered in Maharashtra. But,

why coverage in my State is just 60% in rural areas and 41% in urban areas. This is gross injustice done to AP even in distribution of foodgrains. I request the Food Minister to look into this anomaly and see that 75% in rural areas and 50% population in urban areas are covered under NFSA. Along with this, there is one more issue of clearing dues by GOI to the tune of Rs. 1,700 crores to AP Civil Supplies Corporation for procurement of paddy. GoAP had submitted UCs in the prescribed format to the Ministry. Hence, kindly release this due forthwith.

Now that AP is at the receiving end, as I said, due to unscientific bifurcation and misgovernance between 2014 and 2019 and subsequent pandemic, and everybody started picking a stone and throwing at it. I will give another example, Sir.

Sir, at the behest of the GOI, in spite of AP decided to discontinue power supply to Telangana after June, 2014, AP had to supply power to Telangana. We have agreed and AP supplied power to Telangana DISCOMs till 10th June, 2017. And, an amount of Rs. 6,112 crores dues have to be paid by Telangana DISCOMs to AP. We have been repeatedly requesting for release of amount, but Telangana Government is not moved. Now that it is nearly five years, I appeal to the hon. PM to deduct the pending amount from the devolution of Telangana and adjust the same to AP.

Sir, Railway Zone is another important project to come up in AP and the then Railway Minister Shri Piyush Goyal announced setting up of Railway Zone in 2019, but the recent statement by the present Railway Minister, Shri Ashwini Vaishnaw has brought back the issue where it left. Sir, this is exactly is what is happening with AP, be it new Railway Zone or providing assistance to backward districts of AP. GOI has taken back 350 crores earlier already released for backward districts in AP. So, I ask: Why this apathy towards AP? Why this indifference towards AP? Is AP not part of this Indian Union? Are people of AP not Indians? So, Sir, I urge the hon. PM not to take things too long before they broken. Kindly do justice and be with AP.

Hon. PM may recall the hon. CM meeting him recently and submitted a Memorandum on various issues relating to AP. I am happy that there are some discussions taking place between officials of the GOI and the officials from GoAP. I appeal that let there be a timeline to clearing all issues and not to drag them further. Sir, I also appeal to the hon. Home Minister to release a White Paper on

implementation of AP Reorganisation Act, so that the country knows where the issues stand today and also know whether there is time and cost overrun.

Sir, don't think that we have forgotten SCS to AP. It is an inalienable part of our demands. Sir, the Union Government has again reiterated its earlier stand in reply to a question asked recently in this very House by saying that 'following the recommendations of the 14th Finance Commission, the class of Special Category Status ceased to exist." No one subscribes this argument and let me give a few examples which clearly demonstrate that the purported argument of the Government of India is far from truth.

1. There is Micro and Small Enterprises - Cluster Development Programme of MSME Ministry. Under this, GOI is supporting Common Facilities Centre by giving 90% of project cost to Special Category States (North-East, Hilly States, etc.) and ID 80% for SCSS.

2. The second one is 'Industrial Development Scheme. Under this, Special Category States are given 100% reimbursement of insurance premium on insurance of building, plant and machinery; 30% of investment in plant and machinery. Registration of new units under the above scheme is also granted after 2017 by Empowered Committee for Special Category States.

3. Apart from this, Sir, if you look at Article 4 of the Constitution, it says when any State is bifurcated under Article 3 - AP is divided under Article 3 - then supplemental, incidental and consequential measures can be taken by Government. Sir, the very bifurcation of my State is predicated upon assurance of Special Category Status. So, SCS is supplemental, incidental and consequential to bifurcation. And, to say that 14th FC has not recommended it is conceptually wrong.

All that we are demanding is to implement the decision of the Union Cabinet in March, 2014. So, kindly grant SCS to AP.

So, Sir, these are some of the issues which I thought that I should bring to the notice of the hon. PM with a hope that he would address all outstanding issues relating to AP and do justice to the State before becoming it too late.

With these observations, I support the Motion moved by Mr. Dwivedi. Thank you.

(ends)

*SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Hon. Speaker, Sir, atrocities against the minority communities have been on the rise in the country ever since the NDA Government under the leadership of Shri Narendra Modi assumed power in 2014. Christians residing in various States such as Madhya Pradesh, Karnataka and Uttar Pradesh have already become the target of fundamentalists. Institutions run by Christians are being vandalized. For instance, a church was demolished in Delhi. A school was vandalized in Madhya Pradesh when the students of that school were attending the 12th class CBSE Board Exam. Nuns were attacked by some extremists on board a train nearby Jhansi, Uttar Pradesh. Christmas Carol programmes were interrupted by some anti-social elements on the eve of Christmas. Several Muslim lynching cases reported in the country only because they ate beef or carrying beef. Dalits were brutally attacked and killed across the country. This Government is not taking adequate measures to contain such types of activities and even not condemning such activities. This will hurt our concept of unity in diversity.

After this Government came into power the co-operative federalism in the country is under threat. There is no consultation between the Centre and the States and Union Territories. The people of Lakshadweep are in deep distress due to the malicious intervention of the Government in their daily life to destroy their culture and tradition. The Government is trying to grab the powers of the States, especially in the education, health, and cooperative sectors. The introduction of a new Ministry for cooperation is an example of this move to bring the cooperative sector under the control of the Government.

Foreign policy of this Government is a failure in many aspects. Previous Governments at the Centre always had a good relationship with our neighbouring countries. Even during the period of the Vajpayee Government, India maintained cordial relations with our neighbouring countries. The Government has not taken any concrete steps to solve the issues with our neighbouring countries.

The economic sector in the country is on a downward trend even after the statistics of the Government is showing that the country is growing up. So, there is some lack of integrity in the statistics. The people of this great nation have the right to know about the actual economic situation prevailing in the country. This Government is always trying to hide actual facts before the country. The three black laws on agriculture are examples in this regard.

The average annual rate of growth of GDP under the Modi Government so far has been just 4.8 per cent compared to 8.4 per cent during the first seven years of the Manmohan Singh Government. Even if one excludes the year 2020-21 (FY 21) due to massive contraction caused by COVID-19, still the average of six years of Modi Government stands at 6.8 per cent, way below Manmohan Singh's 8.4 per cent.

---

* Laid on the Table

The Modi Government's decision to demonetise 86 per cent of India's currency overnight on November 8 is seen by many experts as the trigger that set India's growth into a downward spiral. As the ripples of demonetisation and a poorly designed and hastily implemented Goods and Services Tax (GST) spread through an economy that was already struggling with massive bad loans in the banking system, the GDP growth rate steadily fell from over 8 per cent in FY17 to about 4 per cent in FY20, just before COVID-19 hit.

In January 2020, as the GDP growth fell to a 42 years low (in terms of nominal GDP) before COVID was even declared a global pandemic – the fundamentals of the Indian economy were already quite weak. Overall, if one looks at the recent past India's GDP growth pattern resembled an `inverted V' even before COVID-19 hit the economy.

If this continues as business as usual, the dream of a $5 trillion economy by 2024-25 is not likely to be achieved. In fact, India's Gross Domestic Product in 2020, according to the World Bank, was just under $2.7 trillion, so the economy has been treading water rather than marching ahead.

Unemployment is another fundamental factor. Here the news is possibly the worst of all. First came the news that India's unemployment rate, even according to Government's own surveys was at a 45-year high in 2017-18 – the year after demonetisation and the one which saw the introduction of GST. Then in 2019 came the news that between 2012 and 2018, the total number of employed people fell by 9 million – the first such instance of total employment declining in independent India's history. As against the norm of 2 to 3 per cent unemployment rate, India started routinely witnessing unemployment rates close of 6 to 7 per cent in the years leading up to COVID-19. The pandemic, of course, made matters considerably worse.

As per the Oxfam report, the income of 84 per cent of households in the country declined in 2021, but at the same time, the number of Indian billionaires grew from 102 to 142 (39 per cent growth). The richest 98 Indians own the same wealth as the bottom 55.20 crore Indians. During the first two waves of the Pandemic (March 2020 to November 2021), the wealth of Indian billionaires increased from Rs. 23.14 lakh crore (USD 313 billion) to Rs. 53.16 lakh crore (USD 719 billion). This growth in the wealth of billionaires (Rs. 30.02 lakh crore) is 86 per cent of the Union Budget of FY 21-22 (Rs. 34.83 lakh crore).

(ends)

*SHRI B.N. BACHEGOWDA (CHIKKABALLAPUR): Thank you hon. Speaker Sir for giving me the opportunity to speak on Motin of Thanks on President's Address. I rise here in support of the President's Address.

Hon. Speaker Sir, the whole country is celebrating the 75th birth anniversary of Independence. Programs with the name of Azadi Ka Amrit Mahotsav are being organized to celebrate and commemorate 75 years of progressive independent India. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive independent India. Through Azadi Ka Amrit Mahotsav, India is celebrating the glorious history of its people, culture and achievements. It is an embodiment of all that is progressive about India's socio-cultural, political and economic identity. Azadi Ka Amrit Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India far evolutionary journey but also hold within them the power and potential to enable the vision of Prime Minister Modi's to activate India 2.0 which is fueled by the spirit of Atma Nirbhar Bharat.

Azadi Ka Amrit Mahotsav: It is the good fortune of all of us that we are witnessing this historic period of independent India in which Idia is touching new heights of progress. Today's India has got its name written in the front line in the world. On this virtuous occasion, we pay our homage at the feet of Bapu and bow down to the feet of all the great personalities who led the country, who sacrificed themselves in the freedom struggle of the country.

Azadi ka Amrit Mohotsav is an attempt to thank those people because of which we are breathing in independent India. It is time to remember that freedom is not to be taken lightly, the martyrs who sacrificed their lives to achieve it.

While India was flourishing and growing with its all might under the leadership of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, it was hit badly by Corona or COVID-19 and everything came to halt. This pandemic has taken away lot of things from us. People from all races, caste, creed and religion came out for help the needy and each other. When the virus attacked, it took away with it even the riches, the celebrities and the common man too. But yes, after helping out each other, and following all the safety protocols at the personal level, we have come up to the present day and still fighting Corona. The doctors,

---

* Laid on the Table

the police, the health care workers and many others lost their lives but none gave up. They worked even harder each time to keep the citizens safe, truly they are the super heroes of mankind. By the time second wave came, most of the citizens were getting vaccinated and as we all know, our country has always been a peaceful nation. The Government of India donated crores and crores of vaccines to other countries too as a token of goodwill under the Mission Vaccine Maitri. And for this, India has also come to be known as the producer of medicine. India has not just fought the pandemic within national boundaries but also helped fight against it internationally. As our ancestors have taught Vasudhaiv Kutumbakam which means the whole universe is a family, our country India has proved it correctly. Till date, we have administered more than 168 crores of COVID vaccine which is the highest amongst any country in the world.

COVID-19 was something which the world was unaware of. Many of the developed nations like America, Britain, Germany and Canada have seen major disasters in economy and human lives in their countries. It took time and is still taking but as we are developing natin, we have come a long way and we are successfully fighting with the third wave of COVID pandemic along with its variants.

PM Gati Shakti: Speaker Sir, our government aims to expand the National Highways network by 25,000 kilometers in the upcoming fiscal a part of PM Gati Shakti plan, a platform to track infrastructure projects. The master plan for expressways will be formulated in 2022-23 to facilitate faster movement of people and goods. Rs. 20,000 crores will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. Overall, the Gati Shakti plan encompasses seven engines – roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistics infrastructure.

Besides this, Rs. 1 lakh crore will be allocated to States to be used for PM Gati Shakti and other related productive capital investment. Which include components for: Supplemental funding for priority segments of PM Gram Sadak Yojana, including support for the State’s share, digitization of the economy, including digital payments and completion of fiber optic network and reforms related to building byelaws, town planning schemes, transit-oriented development and transferable development rights.

Sports: Speaker Sir, President Sir has mentioned about the achievements in Sports particularly about Olympic Games. I being a National Sports person in my past, it took a lot of efforts by my Government to promote sports in our country. Initiatives such as Fit India Movement, Khelo India Scheme (National Programme for Development of Sports Scheme) aims to achieve twin goals of mass participation and advancement of greatness in sports. The plan endeavours to advance Sports for All as well as Sports for Excellence, Sports Talent Search Portal, significant level committee to address complaints and issues of women sportspersons, Empowered Steering Committee on Sports, National Sports Awards Scheme, Sports and Games for Persons with Disabilities Scheme, Target Olympic Podium Scheme. The Sports Ministry released the Target Olympic Podium (TOP) Scheme in May, 2015 under the National Sports Development Fund (NSDF) to help the potential medal possibilities for the Olympic Games of 2016 and 2020. The main center is given to athletics, badminton, boxing, archery, wrestling and shooting sports.

Our Government has done it fair share to promote and encourage sports in India. Our beloved Prime Minister Modi himself is an epitome of fitness and someone who leads by example and suggests fellow citizens to adopt a healthy lifestyle. There is no debate on what more could have been done on the Government's part to encourage maximum participation of citizens in sports.

Hon. Speaker Sir, with these words, I would like to conclude my speech and once again thank you so much for allowing me to speak in this august House. Thank you.

(ends)

*SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. I would like to discuss about Tribals, Scheduled Tribes. The total population of Scheduled Tribes is 10.43 crore as per the Census 2011, which accounts for 8.6 per cent of the total population of the country. The share of the Scheduled Tribe population in urban areas is a meagre 2.8 per cent. For Scheduled Tribes, 47 seats are reserved in Lok Sabha. There are around 645 distinct tribes in India.

- Budgetary Provisions and effectiveness
- Displacement
- Disinvestment of PSUs

The Tribal Sub Plan (TSP) strategy is a Government of India initiative aimed for the rapid socio-economic development of tribal people. The funds provided under the Tribal Sub Plan of the State have to be at least equal in proportion to the ST population of each State or UTs.

Similarly, Central Ministries/Departments are also required to earmark funds out of their budget for the Tribal Sub-Plan. As per guidelines issued by the Planning Commission, the Tribal Sub Plan funds are to be non-divertible and non-lapsable. Expenditure on Schedule Tribe Sub Plans is budgeted at Rs. 89,265 crore an increase of a mere 2 per cent from RE 2021-22 to BE 2022-23.

From Sub Plan in Higher Education Department allocation, Rs. 240 crore is allocated for assistance to IITs. Regarding the money allocated under this scheme in the previous years, the report of the Comptroller General of India says that most of the seats for PG courses in these IITs remain vacant and in PhD, 95 per cent ST seats remain vacant in the course.

The percentage of shortfall in enrolment of PhD courses was very high in respect of ST category ranging from 73 per cent (IITH) to 100 per cent (IITJ). In the audit of budget for the year 2016-17, it was found that there are many departments, which do not have any plan for SC/ST, but they use their budget in large amounts.

Provisions made for them in the country's budget, and the reply to the questions placed in the House are proof of naked truths of justice denial.

---

* Laid on the Table

Through the budget, the whole country is being told that the Government follows the Constitution and is friendly to the Dalits and Adivasis. But in reality, all this is a game of numbers. Attempt is made to divert SC/ST welfare funds as 'deemed Expenditure'.

The National Commission for Scheduled Tribes is vested with the duty to participate and advise in the planning process of socio-economic development of STs, and to evaluate the progress of their development under the Union and any State. The approach of ongoing project model and cluster method must be relooked. In the changing condition slowly many of them are migrating from their homeland to outside in search of livelihood and mostly they get engaged in odd jobs, low paid works and join in slums as scavengers and housemaids in the cities.

Unfortunately for a long time, they are being exhibited as museum materials in most vulgar and undignified manner in the State-sponsored Adivasi exhibitions and melas, wall paintings in the cities and decorated as statues in traffic islands. Is it decent to show human beings – men, women and children – in such a fashion before others? How such exhibitions are going to help in building a positive image of such communities in public needs a pondering. They struggle to cope with external changing conditions which are quite challenging for them. The fact is mostly non-tribal actors play a major role in the development of PVTGs of the State. The over domination of non-tribals persistently continue in all spheres.

Forest clearances have got accelerated with alarming speed in last few years. Under the law, such diversion is only allowed with the consent of the concerned gram sabhas and with a certificate from these gram sabhas that all forest rights have been recognised.

Displacement is the biggest Challenge - Compensatory Afforestation Fund Act, Climate change related plantations - seriously threaten FRA, PESA.

i. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA in short), in section 4(5) states that save as otherwise provided, no member of a forest dwelling Scheduled Tribes or Other Traditional Forest Dweller shall be evicted or removed from the Forest Land under his occupation till the recognition and verification procedure is complete.

ii. Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act, 2013 in short). The purpose of the said Act is to ensure, in consultation with institutions of local self-government and Gram Sabhas established under the Constitution, a humane, participative, informed and transparent process for land acquisition with the least disturbance to the owners of the land and other affected families and provide just and fair compensation to the affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired.

iii. The Panchayats (Extension to Scheduled Area) Act, 1996, also provides that the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be consulted before making the acquisition of land in the Scheduled Areas or development projects and before resettling or rehabilitating persons affected by such projects in the Scheduled Areas. The actual planning and implementation of the projects in the Scheduled Areas shall be coordinated at the State Level.

iv. Constitutional provision under Schedule V also provides for safeguards against displacement of tribal population because of land acquisition etc. The Governor of the State which has scheduled Areas is empowered to prohibit or restrict transfer of land from tribals and regulate the allotment of land to members of the Scheduled Tribes in such cases. Land being a state subject, various provisions of rehabilitation and resettlement as per the RFCTLARR Act, 2013 are implemented by the concerned State Governments.

We condemn any attempt by Government in disinvesting any profit making PSUs, especially Nalco.

(ends)

*SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Mr. Speaker, Sir, I rise to support the Motion moved by Shri Harish Dwivedi to thank the hon. President for his Address to both the Houses of Parliament on 31st January, 2022.

Sir, though President's Address to both the Houses at the beginning of every year is a constitutional obligation and ritual through which the Government of the day informs what it has done during the previous year, be it relating to major policy achievements, programmes, schemes and other things, it also broadly outlines what it is going to do in the coming year. So, this broad outline gives an opportunity to the Members of both the Houses to ventilate our point of view and suggest how the goals, policy interventions, etc., proposed can be better achieved. So, I thank the hon. President for his Address not only on behalf of my Telugu Desam Party but also on my personal behalf.

Sir, hon. President has given details of the success story of India in controlling, containing Corona and also about our capability and capacity in the fight against COVID-19 through the on-going vaccination programme. Sir, it is a great achievement that we have been able to administer more than 150 crore doses in less than a year and so far, we have administered nearly 170 crore doses which is a record. No country out of 225 countries inflicted with COVID has achieved this enormous feat. So, I compliment the COVID warriors for this scintillating achievement and also the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for his intervention and guidance as to how to go about to deal with pandemic through innumerable virtual meetings, National Addresses, social media and how he motivated the people to follow COVID protocol to deal with this purported 'once in a Century' menace.

Sir, we have seen waves which have devastated every country, crushed every single economy and have their way in both waves. We ourselves have witnessed the devastation caused by 2 waves, with the country facing economic & humanitarian crisis in the first wave and during the second wave we saw the stress on our Healthcare system and a huge loss of life.

When Omicron was first reported in South Africa and spread to Europe and the US, economists, health and medical experts had warned that the third wave would be more disastrous than the previous two waves and predicted that at the peak we would see around 14 lakh new cases being every day. We were all

* Laid on the Table

worried, every citizen of this country was worried as to what to do and how to stop this menace. But, with guidance from the hon. PM, repeatedly asking the people of this country to follow COVID protocol and people, after learning lessons from the first two waves, following the COVID protocol with discipline, we have been able to control the 3rd wave, with the country seeing a decline in the daily cases being reported.

Sir, even after facing 2 huge waves, our country and its people have shown their resilience and emerged stronger. The results are before us to see - average GST collections of more than 1 lakh crores in the last few months and the record collections of 1.41 lakh crores in January, 2022; remarkable turnaround of the economy which is evident from the figures given in the Economic Survey and by the hon. Finance Minister while presenting her Budget on 1st February, 2022, and the list goes on. So, I compliment hon. PM for writing a success story of COVID and thank him for guiding the nation like a true leader who has concern for the people of his country.

The next point I would like to make is relating to hon. President's mention of celebrating the sacred occasions during this Amrit Mahotsav, be it 400th Prakash Parv of Guru Tegh Bahadurji or 125th birth anniversary of Subhas Chandra Bose or celebrating 15th November every year as Janjatiya Gaurav Diwas as a tribute to a great freedom fighter, Birsa Munda, on his birth anniversary. I welcome all this. But, taking advantage of this occasion, I also bring to the notice of the House that the Committee on Installation of Portraits and Status of National Leaders and Parliamentarians in Parliament House Complex approved installing the statue of another great freedom fighter and Tribal (Manyam) Leader from Andhra Pradesh, Shri Alluri Sitharama Raju, within the precincts of Parliament. It has been many years since approval given by the Committee, but so far it has not been installed. So, I appeal to the hon. Speaker and the hon. PM to see that this Telugu bidda and a great tribal freedom fighter from AP is also respected by installing his statue in Parliament without any further delay.

There is no doubt, as mentioned by hon. President in his Address at Para 42 that India again emerged as one of the fastest growing economies in the world and the Budget figures indicate that we are going to grow at 9.2% this fiscal and it would be around 8.0-8.5% in the coming fiscal substantiates that. Attracting nearly 48 billion FDA is another testimony to this achievement and sitting comfortably on 630 billions of foreign exchange is a proof of that. There are very many policy,

fiscal and monetary interventions of the GOI through which this has been possible. And, one such policy intervention is the Insolvency and Bankruptcy Code. Sir, IBC is one such Code which aims to resolve and help corporate entities, partnerships firms and individuals when they go bankrupt. It was a good move. But, my point is: When Government is extending a handholding for corporate, why cannot the same analogy be applied to States which are on the verge of going bankrupt.

I suggest that GOI should also intervene and protect the interests of the people and other stakeholders in those States which have gone bankrupt. Sir, AP is one such State which is on the verge of financial bankruptcy. So, I appeal to the hon. PM to intervene and see that my State does not become bankrupt and become and join BIMARU. So, kindly help AP.

Sir, Parliament is witness to the reply given by the hon. Minster of State, Home Affairs, in the Rajya Sabha a couple of days ago on Wednesday where he has made it clear that Amaravati is the capital of AP in response to a question asked in the Upper House. This substantiates my point, our party's point, the point of farmers from 29 villages who have given their 2-3 crop farm land for construction of the capital and have been agitating for more than two years now. It is not just Home Minister, but also High Court of AP is also supporting and stated that Amaravati would be the capital of AP.

I would also like to bring to the notice of the Hon PM and Hon Home Minster that the farmers and women of the Amaravati walked from the High Court in Amaravati to Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala, a distance of over 430 Kms over 45 days braving heat, rains and harassment from the police. And all through the walk these farmers and women were received in every village as heroes which shows the support of the people to have Amaravati as the sole capital.

So, without dwelling deep into the issue, since I have raised it many times, I request the hon.PM to take cognizance of the struggles and hardships faced by the Amaravati Farmers and women, and declare that Amaravati would be the capital of AP. I also urge him to talk to the farmers, convince them that Amaravati would be given every financial and other help and would be built, as assured by him, as a bigger capital than Delhi and it would be people's capital.

I also request the hon. PM to intervene and see those pending annuities be paid by GoAP to the farmers without any further delay.

Sir, one important announcement that was made during the budget was the 5 projects for inter-linking of rivers which include Krishna Godavari, Krishna-Penna and Penna-Cauvery. We welcome this announcement sir. I would like to remind this august House that the leader my party, Sri Chandrababu Naidu garu had already laid foundation to this idea in Andhra Pradesh when he was the Chief Minister of the state. And I would like to bring to your notice that the Polavaram is a critical component for the success of this inter-linking of rivers project in the State.

Sir, everyone is aware of the Polavaram issue which has been raised innumerable times not just by TDP but also by Members from the YSRCP and BJP. We are appealing to the hon. PM and the GOI to approve the 2nd revised cost estimates of Rs. 55,656.87 crores which has been approved by the Technical Advisory Committee and the Revised Cost Committee - both of which belongs to the Ministry of Jal Shakti. I also request that drinking water component be treated as part of irrigation component like any other National Project constructed so far. So, I appeal once again to do this so that project is completed as targeted.

My next point is relating to creation of new Railway Zone headquartering at Visakhapatnam. Sir, announcement for this was made just before the General Elections of 2019. People of AP felt happy that we are getting a new Zone, so that economic activity would gear up, get direct and indirect employment opportunities. But, the recent statement of the hon. Railway Minister that there is no proposal before the GOI to set up new Zones, apart from the existing 17 Zones, has created a flutter in the minds of the people of AP as to what is happening and why such statement was made by the Union Railway Minister.

Till today, this statement has not been clarified. So, Sir, I appeal to the hon.PM to clear the air while replying to the debate and also give timelines by when the new Zone will become operational.

Sir, I have been raising various issues relating to AP Reorganisation Act, be it relating to educational institutions or setting up of a major port or steel plant or crude oil refinery and petro-chemical complex or Vizag Chennai industrial corridor on the lines of Delhi-Mumbai Industrial Corridor or Metros and the list goes on. But, so far not even a single project has been completed totally and dedicated to the nation. We are only getting a standard reply that 'the work is in progress.' So, taking advantage of this, I appeal to the hon. PM and hon. Home Minister to release a White Paper on the AP Reorganisation Act, 2014, so that people of AP and the people of the country know where we stand today. So, kindly do that.

Sir, the next point I wish to make is about PM Garib Kalyan Anna Yojana. So far 4 phases have been completed and we are in the 5th phase of its implementation. There is no doubt that the hon. PM has so far given 700 lakh metric tons of rice/wheat to the poor and migrant labour by spending more than 2.6 lakh crores. Hon. President has also mentioned this in his Address at Para 15. It benefited 80 crore people and is no doubt the largest food distribution programme. But, Sir, I wish to bring to the notice of the hon. PM - I am sure, he must be aware of this that this scheme is going to expire next month and, as we know, pandemic is not yet over. A new Corona variant - NeoCoV has been identified and experts have termed it as the deadliest one, be it relating to rate of infection or mortality which are very high. I am told that it can cause 1 death in every 3 cases. Secondly, migrant labour is still struggling. So, I request for consideration of the hon. PM to extend PMGKAY for six more months which will help poor and migrant labour a lot.

Sir, another policy that is going to end this fiscal is GST compensation to be paid to States. As per the agreed scheme of things, compensation will have to be paid to States at 14% for five years from 2017 for the loss of revenue by States due to implementation of GST. This is going to expire in a few months from now. Pandemic has hit economy of every State and AP is no exception. So, every State, including BJP ruled States are demanding for extension of this for five more years. I find every justification in this and request the hon. PM to see that this is extended for five more years.

Petroleum prices is another contentious issue. It has become contentious since GOI is sharing only around 6% of revenue it is generating through petroleum prices. I am not going into why GOI has imposed so much excise duty, why some States have not reduced price on petrol and diesel when GOI reduced recently and all that.

All I appeal to the hon. PM is to share whatever Cesses, Addl. Excise Duty, Surcharge, Infrastructure Cess, etc., collected by GOI be shared with the States in the same percentage in which it is sharing the Excise Duty. It will help States financially, as they get some money.

Sir, hon. President talked about women empowerment from Paras 30 to 33. There is no doubt that we have to empower women, not only economically, socially but also politically. I compliment the hon. PM that he can walk the talk as far as empowering women is concerned. But, the political empowerment at the national

and State level is still eluding them. This can be achieved only when this House passes the Women Reservation Bill. So, I appeal to the hon. PM to make a pahal for this as well, the way he has done in other areas, and give the women of this country this legislation in this Session itself.

Sir, hon. President talked about MSMEs in Para 45 and 46. Under Atmanirbhar Bharat package MSMEs have been given collateral free loan of 3 lakh crores and in the Budget hon. FM made 8 MSME-related announcements. It is welcome. The Emergency Credit Line Guarantee has been extended to 5 lakh crores. It helps 130 lakh MSMES and extension till 2023 also helps them. FM also announced that Credit Guarantee Trust for MSMEs will be revamped, along with other steps. They are all good. But, they are demanding some fiscal stimulus. I will speak on this in detail during the discussion on the Budget. So, hon. PM may consider this.

So, Sir, these are some of the issues I wish to flag in the President's Address and request the hon. PM to reply to these while replying to the debate.

With these observations, I support the Motion moved to Thank the hon. President for his Address. (ends)

*SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Hon'ble Speaker Sir, I support the motion of thanks on President's address moved by Shri Harish Dwivedi.

Speaker Sir, this year we are celebrating the true spirit of 75 years of a progressive India. Furthering the spirit of pride and Atmanirbharta with the celebrations of Azadi ka Amrit Mahotsav, we have laid the foundation for an exemplary future under the leadership of Hon'ble PM Shri Narendra Modi ji.

On this day, remembering the words of Atal Bihari Vajpayee Ji, **"सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए।".** Since the country is paramount and a politician should work with full devotion for his country first. The nation resounds with the idea of contributing to the evolutionary path the country is set on. The people of India hold the power and potential to enable the vision of a New India, fuelled by the spirit of 'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas'.

Speaker Sir, a proud moment for India was the country reaching the milestone of 100 crores COVID-19 vaccination. Not only have we achieved a remarkable feat but we have also been successful in becoming one of the leading countries in the world to administer doses to adolescents, booster doses to the front-line workers, senior citizens with comorbidities and reaching out to each and every citizen through the "Har Ghar Dastak" campaign. The relentless spirit of the healthcare workers paid off and with mutual trust and coordination between the government, citizens and every healthcare worker, we have achieved this milestone.

I would like to highlight here how India's vaccination program is a story of an extraordinary journey of more than 135 crore people encountering and fighting the challenges posed by a highly infectious coronavirus. This is indeed a true example of "Jan Bhagidari" under the leadership of our Prime Minister who helped us formulate a Proactive, Pre-emptive and a graded approach.

India now realizes the importance of traditional medicines and the global attention that Ayurveda and Yoga have gained in the past few years. With the successful efforts of the AYUSH ministry, the exports of such traditional products have increased. To promote cost-effective alternatives to the people, funds have been sanctioned for research and development in the traditional medicine sector.

Speaker Sir, in the unprecedented times of the COVID-19 pandemic, in order to prevent hunger, help and aid the people of the country, the Government of India ran the world's largest food distribution program. The Department of Food and Public Distribution (DFPD) started distribution of 'additional' and 'free-of-cost' food grains (Rice/Wheat) to around 80 Crore National Food Security Act (NFSA) beneficiaries in the country under the "Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PM-GKAY)". What merits the most praise is

---

* Laid on the Table

the government's initiative to not only ensure food security for its citizens but also generate economic benefits for them that were beyond preventing hunger.

Under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, as a tribute to our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modiji's service to the nation, I distributed more than 10,000 Ration Bags to the beneficiaries of the scheme in my Parliamentary Constituency, Pali. To ensure that no citizen lacks the accessibility and affordability for sufficient nutritious food, the Government led awareness campaigns for the beneficiaries in the remotest parts of the country.

Under the PM-GKAY scheme, the Government has so far awarded a total of over 759 lakh MT food grains to the States/UTs under the PM-GKAY plan (Phase I to V) for free distribution to around 80 crore NFSA beneficiaries, which is equivalent to about Rs. 2.6 lakh crore in food subsidy. According to the phase-by-phase distribution reports available from the States/UTs, a total of nearly 580 million metric tonnes of food grains had been distributed to the beneficiaries.

Speaker Sir, with the aim of uplifting the socio-economic conditions of rural population, under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, 36 thousand 5 hundred kilometres of roads have been built in rural areas, at the rate of more than 100 km per day, and thousands of habitations have been connected with all-weather roads. In my Parliamentary constituency, Pali, many roads were constructed under PMGSY for the well-being of the people. These endeavours of the Government have helped in the development of rural areas. The Government's aim is to uplift the rural population by providing them access to world-class roads, infrastructure, and job opportunities and under its various schemes, the Government is tirelessly working to achieve the same.

Further with the idea of 'Har Ghar Jal', the Jal Jeevan Mission has brought about a huge difference in the lives of the people. Nearly six crore rural households have been provided tap water connection despite the constraints imposed by the pandemic. It has been of huge benefit for the women, sisters and daughters in our villages.

Jal Jeevan Mission, is envisioned to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connections by 2024 to all households in rural India. The programme will also implement source sustainability measures as mandatory elements, such as recharge and reuse through grey water management, water conservation, rain water harvesting. The Jal Jeevan Mission will be based on a community approach to water and will include extensive Information, Education and communication as a key component of the mission. The Jal Jeevan Mission will be based on a community approach to water and will include extensive Information, Education and communication as a key component of the mission. Jal Jeevan Mission looks to create a Jan Andolan for water, thereby making it everyone's priority.

"Digital India" Mission: - what started out as a regular initiative to digitize and bring technology to efficient use of the citizens has now become a way of life as rightly pointed out by our Hon'ble PM. Just a couple years ago, when this mission was launched, people would often raise questions at the Government and would doubt the intent of the schemes. There was a constant fear that how would technology penetrate in a country with such high rural population. I would like to bring to your notice that not only have we been successful in providing digital access to the citizens but we have also successfully transformed India into a digitally empowered society.

We can see the impact of Jan Dhan-Aadhaar-Mobile or JAM trinity which the government has leveraged for the empowerment of citizens. With more than 44 crore poor people joining the banking system, crores of people benefitted from direct cash transfer during the pandemic.

Amidst the progress made in respect of Digital India and Digital Economy, the government's vision for the success of the country's UPI platform is also appreciated. Transactions worth more than Rupees 8 lakh crore have taken place in the country through UPI in December 2021. This is a clear example of how fast our people are adopting technology and rapid change.

Our physical infrastructure was shut down in most places during the pandemic, and during those times, we efficiently learned lessons and reaped the benefits of having a reliable digital infrastructure that ensured our survival. The remote working and learning from home trend have been gaining hold prior to the Covid-19 era. However, the events of the pandemic demonstrated that, with the correct technologies and techniques, we can rely on technology and the vision of digital transformation can be proven to be more productive in many circumstances.

Outlining a new approach to data governance in the world's largest digital democracy, India came up with its own Personal Data Protection Bill, 2019. The Personal Data Protection Bill, 2019 lays down the mechanism for the protection of personal data of the citizens. With the idea of Nation is first, the bill seeks to achieve data sovereignty and tends to focus and prioritize on the individual rights of the citizens. Personal Data Protection Bill, 2019 is going to help boost the digital economy, generate employment and enhance the ease of doing business. The bill is set to create a fine balance in maintaining the privacy and helping government provide the services and benefits to the citizens. In the interest of integrity, sovereignty and security of India, the authorities under the Personal Data Protection Bill, 2019 have been assigned to process and regulate the laws fairly and justly for the larger benefit of the community.

On the eve of 75th Independence Day, Prime Minister Narendra Modi announced from the Red Fort that the government will launch 'PM Gati Shakti Master Plan', an INR 100 lakh-crore project for building 'holistic infrastructure' in India. The idea behind 'Gati

Shakti' scheme is that, we aim to create a digital platform promising the “integrated planning and coordinated execution” by sixteen ministries. Each ministry and government department will be able to access information about the ongoing and upcoming projects us for a balanced and synchronised approach.

The Gati-Shakti programme is structured to prioritise all–mega infrastructure and connectivity targets by 2024-2025. In economics parlance, this would have multiplier effects in the economy by saving public revenue and taxes. The immediate effect would be seen through increased demand for construction materials, demand for labour and second order effects by better reach and connectivity.

In the last seven years, under PM Modi, the union government has ensured an unprecedented focus on infrastructure through holistic outlook. Now with Gati Shakti, this umbrella scheme is going to undertake various infrastructural projects under distinct ministries like Bharatmala, Sagarmala, inland waterways, land ports, UDAN etc.

The PM Gati Shakti master plan for expressways will facilitate faster movements of People and goods. It is set to encompass 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency. The national highway network will increase by 25,000 Km in 2022-23. Rs20,000 Crores will be mobilised to complement public resources. The contracts for the implementation of multimodal logistics park in four Locations through PPP model will also be given in the current Year. 400 new generation Vande Bharat trains with better efficiency to be brought in during the next 3 years; 100 PM Gati Shakti Cargo terminals to be developed during next 3 years and implementation of innovative ways for building metro systems.

PM GatiShakti is the result of Prime Minister’s constant endeavour to build Next Generation Infrastructure which improves Ease of Living as well as Ease of Doing Business. The multi-modal connectivity will provide integrated and seamless connectivity for movement of people, goods and services from one mode of transport to another. It will facilitate the last mile connectivity of infrastructure and also reduce travel time for people.

PM GatiShakti will provide the public and business community information regarding the upcoming connectivity projects, other business hubs, industrial areas and surrounding environment. This will enable the investors to plan their businesses at suitable locations leading to enhanced synergies. It will create multiple employment opportunities and give a boost to the economy. It will improve the global competitiveness of local products by cutting down the logistics costs and improving the supply chains, and also ensure proper linkages for local industry & consumers.

Thank You.

(ends)

*__श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा):__ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी 2022 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।

इससे पूर्व भी 17 वीं लोक सभा में महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुनने को मिला और सरकार की बहुत सारी बातें सुनने, जानने और देश के सामने रखने को मिलीं।

पूर्व की सरकारों के समय भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और तरह-तरह की समस्याएं सामने थीं। लेकिन आशा की किरण इस देश की महान जनता ने आदरणीय मोदी जी में देखी। सन् 2014 एवं 2019 के लोक सभा के चुनाव में 30 वर्षों के बाद अगर किसी एक राजनैतिक दल को पूर्ण बहुमत मिला तो वह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिला। लोगों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया और जो आशा हमारी पार्टी से हिंदुस्तान की महान जनता को है, पिछले सालों में हमारे काम-काज को देखकर यह स्पष्ट दीखता है कि हमने उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया है। पिछली सरकार में शायद कहीं न कहीं जनता के साथ संवाद की कमी थी और माननीय प्रधान मंत्री जी ने आते ही उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। जनता और सरकार के बीच में जो एक दूरी नजर आती थी, सरकार ने उस दूरी को कम करने का काम किया। शायद इस देश के लोग और हमारी नई पीढ़ी रेडियों को भूल चुकी थी। लेकिन देश की जनता से बात करने का उसे भी एक माध्यम बनाया गया। आज अगर भारत में लोगों से जुड़ने के लिए सबसे सफल कार्यक्रम कोई रेडियो पर देखा जाए तो 'मन की बात' के माध्यम से प्रधान मंत्री जी ने उसकी भी शुरूआत की। हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि भारत की छवि जो पिछले कुछ वर्षों में बन गई थी, उसे कैसे बदला जाए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगातार जिस तरह से भारत की नियति बनते जा रहे थे, उसे बदलने के लिए देश के सामने सरकार का अच्छा काम करना बहुत जरूरी था और सत्ता में आते ही जिस बात के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी जाने जाते थे, सुशासन और विकास की राजनीति के लिए, देश को उसका लाभ मिले, जिस तरह से देश की जनता ने सोचा था, उसी तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी जरूरत छवि और सोच को बदलने की थी। मैं यही कहना चाहूंगा –**"सोच को बदलो तो सितारे बदल जायेंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जायेंगे, मंजिल पानी हो तो किश्तियां मत बदलना, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जायेंगे।"**

70 वर्षों में हिन्दुस्तान की गरीब जनता, आधे से ज्यादा आबादी और परिवारों के बैंक खाते तक नहीं थे, अर्थव्यवस्था के साथ उनके जुड़ने का कोई माध्यम तक नहीं था। शायद उन्हें आजादी के जो सपने दिखाये गये थे, उन्हें 70 वर्षों में पूरा नहीं किया गया। लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री जी ने जब निर्धनता उन्मूलन के लिए वित्तीय समावेश की बात कही, तब शायद हममे से अधिकतर लोग समझ नहीं पाये, लेकिन चंद ही दिनों में जब प्रधान मंत्री ने 'जन-धन योजना की शुरूआत की, तब भी लोगों को लगता था कि क्या यह हो पायेगा, क्या यह संभव होगा? लेकिन छ: महीने का समय भी उसके लिए ज्यादा

---

* Laid on the Table

समय था, हमारी सरकार ने विश्व रिकार्ड बनाया, छः महीने से कम समय में 13.2 करोड़ नये बैंक खाते खोलकर हिंदुस्तान में लगभग हर परिवार को बैंक के साथ जोड़ा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वित्त मंत्रालय के लोगों ने माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाकर उस लक्ष्य को पूरा किया है। सरकार ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही उन गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का कार्य किया, जो स्वप्न में भी बैंकों तक जाने की नहीं सोच पाते थे। जिसका सीधा फायदा कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रान्सफर पहुंचाया गया।

कोरोना काल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर द्वारा किया गया प्रयास बहुत ही सराहनीय है। उस समय विश्व के सभी विकसित देश चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो अथवा अन्य देश, सभी यह सोच रहे थे कि भारत जैसा विशाल आबादी वाला विकासशील देश इस आपदा से कैसे निपटेगा? उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को लग रहा था कि जब हमारे जैसे विकसित देश इस महामारी के सामने नतमस्तक हो गये तो भारत में भयावह स्थिति होगी। डब्ल्यूएचओ द्वारा भी समय-समय पर भारत को चेताया गया। लेकिन कोविड-19 को लेकर भारत की जो रणनीति रही, उसे डब्ल्यूएचओ सहित विश्व के लगभग सभी विकसित देशों ने सराहा। भारत ने न सिर्फ समय पर वैक्सीन बनायी बल्कि उसने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज़ लगाने का रिकार्ड भी बनाया। आज देश में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की पहली डोज़ मिल चुकी है जबकि 70 प्रतिशत से अधिक लोग दोनों डोज़ लगवा चुके हैं। छूटे हुए लोगों को **'हर घर दस्तक अभियान'** के माध्यम से सरकार उन तक पहुँचने का प्रयास कर रही है।

इसी वर्ष, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर-किशोरियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए Precautionary डोज़ लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है।

भारत में बन रही वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। अब तक देश में कुल 8 वैक्सीनों को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। भारत में बन रही वैक्सीन पूरी दुनिया को महामारी मुक्त करने और करोड़ों लोगों के जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

केन्द्र सरकार माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में 'प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना' के माध्यम से गरीब लोगों को निजी एवं सरकारी सभी अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा प्रदान कर रही है। अब स्वास्थ्य सेवाएँ जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 80 हजार से अधिक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स और करोड़ों की संख्या में 'आयुष्मान भारत कार्ड' से गरीबों को इलाज में बहुत मदद मिल रही है। साथ ही सरकार ने 8 हजार से अधिक 'जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से कम कीमत में दवाइयां उपलब्ध कराकर, इलाज पर होने वाले खर्च को कम किया है।

सरकार ने योग, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भी लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इन उत्पादों का निर्यात वर्ष 2014 से 6600 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 11 हजार करोड़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

महोदय, हमारी सरकार ने न सिर्फ स्वास्थ्य को ध्यान में रखा है अपितु कोरोना काल में उन ग्रामीण गरीबों एवं गैर संगठित रोजगार से जुड़े लोगों का भी विशेष ख्याल रखा है जिनके रोजगार नहीं रहे।

80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को विगत 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित कर दुनिया का सबसे बड़ा भोजन वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

जिस भारत देश में डिजिटल के बारे में बात तक नहीं होती थी, वहाँ UPI Platform के माध्यम से ही दिसम्बर 2021 में, देश में 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन हुआ। यह डिजिटल के क्षेत्र में क्रान्ति का आगाज है।

गरीब सरकार की प्राथमिकता में प्रारम्भ से ही रहे हैं। माननीय मोदी जी के अनवरत प्रयासों का ही सुफल है कि **'प्रधानमंत्री आवास योजना'** में अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर बनाकर गरीबों में वितरित किये जा चुके हैं। **'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण'** के तहत विगत तीन वर्षों में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये की लागत से एक करोड़ सत्रह लाख घर स्वीकृत किए गए हैं।

माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में सरकार बनते ही यह महसूस किया गया कि देश का एक बड़ा वर्ग आज भी पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए **'हर घर जल'** पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए **'जल जीवन मिशन'** की शुरूआत की गयी । महामारी की बाधाओं के बावजूद भी करीब 6 करोड़ ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ा गया। इसका बहुत बड़ा लाभ आज गाँव की महिलाओं, बहनों और बेटियों को मिलना प्रारम्भ हो गया है। जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है।

किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान लॉक डाउन के कारण जब हमारे सभी उद्योग-धन्धे बन्द हो गये, तब विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय कृषि ने अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखा। किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए ही सरकार ने किसानों से रबी एवं खरीफ की क्रमशः 433 लाख एवं लगभग 900 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड सरकारी खरीद की है जिससे लगभग 1 करोड़ 30 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्ष 2020-2021 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।

महोदय, इतना ही नहीं, **"किसान सम्मान निधि"** गरीब किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इसके माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अभी तक एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में प्रदान किए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं।

मुस्लिम समाज की महिलाओं को **"तीन तालक"** की कुप्रथा के तहत वर्षों से चले आ रहे दुःखदायी एवं पीड़ादायक कानून को झेलना पड़ रहा था। हमारी सरकार ने मुस्लिम समाज की महिलाओं को इज्जत एवं सम्मान का जीवन जीने के लिए **"तीन तलाक"** को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने का काम किया है। साथ ही मुस्लिम महिलाओं को केवल अपने पति के साथ हज यात्रा करने जैसे प्रतिबन्धों को भी हटाया है।

सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा वृद्धि की है तथा मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों ने भी बालिकाओं को प्रवेश देना शुरू कर दिया, साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भी महिला कैडेट के प्रवेश की मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने बेटा एवं बेटी को समानता का दर्जा देते हुए महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरूषों के समान 21 वर्ष करने का प्रस्ताव संसद के समक्ष रखा है।

अक्सर राज्यों, विशेषकर दक्षिण-पूर्वी राज्यों द्वारा उनकी स्थानीय भाषाओं को उचित प्रोत्साहन न मिलने का आरोप लगाया केन्द्र पर लगाया जाता रहा है। स्थानीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्नातक पाठयक्रमों की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं स्थानीय भाषाओं में भी संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो रही है।

हमारी सरकार की नीतियों के कारण ही आज भारत उन देश्यों में शामिल हो गया है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्ट फोन की कीमत भी सबसे निचले स्तर पर है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है। आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है। देश में मोबाइल उत्पादन की सफलता Make in India का एक बड़ा उदाहरण है।

'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' की उपलब्धियां गर्व करने योग्य हैं। वर्ष 2020-2021 में ग्रामीण इलाकों में 100 किलोमीटर प्रतिदिन से अधिक की रफ्तार से 36 हजार 500 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं और हजारों रिहायशी क्षेत्रों को All weather road connectivity से जोड़ा गया है।

मार्च 2014 में हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 90 हजार किलोमीटर थी, जबकि आज उनकी लंबाई बढ़कर एक लाख चालीस हजार किलोमीटर से अधिक हो गई है। **"भारतमाला परियोजना"** के अंतर्गत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से 20 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई के राजमार्गों पर काम किया जा रहा है। इनमें 23 ग्रीन एक्सप्रेस फील्ड कॉरीडोर्स का विकास भी शामिल है।

यदि यह कहा जाए कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश न सिर्फ सड़क, महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, शिक्षा बल्कि विकास के प्रत्येक क्षेत्र में नए सोपान गढ़ रहा है, तो यह अतिश्योक्ति नहीं बल्कि सच्चाई को स्वीकारने वाला वह सच है जिसके लिए भारतीय जनता वर्षों से सरकार से उम्मीद लगाए हुए थी। आज सरकार भारतीय जनता, महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वप्नों को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। हम विश्व में सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता।

(इति)

*__श्री सुरेश कश्यप (शिमला):__ नमस्कार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पे बोलने का मौका दिया।

मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए आपके सामने उपसिथत हुआ हूँ और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सदन में उपस्थित बहुत से वरिष्ठ महानुभावों ने चर्चा को प्राणवान बनाया। कई पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है। हम सभी जानते हैं कि 2021 में भारत की आजादी को 75 साल पूरे कर लिए है, जो कि किसी भी भारतवासी के लिए गौरव की बात है इसलिए इस महोत्सव को मनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है ताकि हम अपने अंदर के देश प्रेम को जागरूक कर सके और एक समझदार नागरिक के तौर पर भारत का विकास कर सके।

हम सभी जानते हैं कि भारत को बहुत ज्यादा संघर्ष और बलिदान के बाद आजादी प्राप्त हुई 100 वर्ष से ज्यादा लंबे चले संघर्ष के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इसके लिए बहुत से लोगों ने शहीद होकर इस देश को आजाद कराया।

आजाद भारत में तीन पीढ़ियां जन्म ले चुकी है, जिनमें पहली पीढ़ी तो वही है जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया और बहुत कुर्बानियां दी और दूसरी पीढ़ी वह रही जिन्होंने अपने दादा या अपने पिता से आजादी की कहानियां सुनी और इस संघर्ष के बारे में करीब से जाना, लेकिन वर्तमान समय मे जो तीसरी पीढ़ी है उन्हें आजादी के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है उन्हें नहीं पता है कि भारत को आजाद कराने में कितना संघर्ष करना पड़ा है और लोगों ने कितने ज्यादा कुर्बानियां दी हैं।

"जिन वीरों पर हमें गर्व है आजादी होनी है का पर्व है, कहती भारत की आबादी है जान से भी प्यारी आजादी है, स्वतंत्रता अधूरी जिनके बिन है यह उन्हीं शहीदों का दिन है, गांधी सुभाष और भगत सिंह यही है आजादी के चिन्ह"

यह मात्र एक अभिभाषण नहीं है बल्कि वह सरकार की नीतियों व योजनाओ का दर्पण होता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओ को बताते हुए एवं आगामी वर्ष में सरकार द्वारा किये जाने वाले योजनाओ के लिए मिल का पत्थर स्थापित किया है। सरकार को पूरा सफर तय करते हुए वहा तक जाना है और मुझे और हमसबको पूर्ण विश्वास है कि देश के यशश्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निर्णयों को पूर्ण करने में सफल होग। आज हम सब देख रहें है कि भारत किस तेजी से बदल रहा है।

हमारी सरकार ने सबका साथ,सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए 5, नहीं 10 नहीं बल्कि आगामी 25 वर्षों के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रही है। देश अत्तंनिर्भर के संकल्प से साथ आगे बढ़ रहा है।

---

* Laid on the Table

"हम रहे या न रहे यह देश रहना चाहिए, देश से है प्रेम तो हर वक़्त यह कहना चाहिए, हम रहे या न रहे यह देश रहना चाहिए"

महोदय, आज भारत ही नहीं पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। 27 जनवरी 2020 भारत के केरला राज्य में कोरोना का पहला केस सामने आया। देश को एक ऐसे दुश्मन से जंग लड़नी थी जिसको न तो देखा गया न ही उसके बारे में जानकारी थी। परन्तु जिस तरह से हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह पुरे देश ने मिलकर इस महामारी का सामना किया आज पूरा विश्व जानता है और पुरे विश्व ने यह देखा। इस महामारी ने हमारे बहुत से प्रियजनों को हमसे छीना है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह उनकी नीतियों के साथ राज्य सरकारों स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे देश के डॉक्टर्स , नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स , हमारे वैज्ञानिक और उद्यमिओ ने एक साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम किया है। जो कि बहुत ही सराहनीय है। प्रधान मंत्री जी ने समय समय पर देश के नागरिको के बीच संवाद बनाये रखा और सबको विश्वास में रख सही कदम उठाये जिसके परिणाम आज हम सब देख रहे है। बहुत से लोगो ने समय समय पर नीतियों पर कटाक्ष की परन्तु वह भी आज उठाये गए सारे कदमो और नीतियों को मानने लगे है।

हमने देखा माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और नागरिको के बीच विश्वास समन्वय और सहयोग किस तरह का रहा है।

आज भारत में 150 करोड़ से अधिक नागरिको को वैक्सीन के डोज़ लग चुके है। जो की अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत पूरी दुनिया में सबसे जायदा वैक्सीन डोज़ देने वाले अग्रणी देशो में से एक है। और हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए।

देश में निर्मित वैक्सीन एक जीता जगता उदारण है की किस प्रकार देश आतम निर्भर भारत के और बढ़ रहा है। मोदी जी का हमारे विज्ञानिको पर विश्वास और उनके द्वारा देश में ही निर्मित वैक्सीन ने देश को रक्षा कवच दिया है।

यह हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हमारे देश में 90 % से अधिक वयस्क नागरिको को टीके कि पहली डोज़ मिल चुकी है। जबकि 70% से अधिक लोगो ने दोनों डोज़ लगवा ली है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में चलाया गया 'घर दस्तक अभियान' जोश और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। श्रीमान में हिमचाल प्रदेश के शिमला लोकसभा से आता हूँ हम सब जानते है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण घर घर पहुंचने पर काफी समस्या आती है आज भी काफी मार्ग कठनाई भरे होते है। परन्तु मुझे गर्व है अपने प्रधान मंत्री जी पर हमारे नेता पर कि उनके द्वारा दिए गए सन्देश से आज हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स पुरे जोश के साथ घर घर जाकर बचे हुए लोगो को वैक्सीन लगा रहे है।। ऐसा पहली बार देखा गया कि इतनी तेज़ी के साथ यह सब कार्य हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सबसे पहले अपने प्रदेश के नागरिको को दोनों डोज़ देने का कार्य किया है। जिसके लिए में प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ।

मुझे यह भी बताते हुए गर्व है कि आज वैक्सीन प्रोग्राम में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को भी शामिल कर लिया गया है और उनके लिए भी वक्सीनशन प्रोग्राम बहुत ही गति से

चल रहा है। और इसके साथ साथ सभा फ्रंट लाइन वर्कर्स और जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिको के लिए PRECAUTIONARY डोज़ कि शुरूवात कर दी गयी है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में सरकार द्वारा 64 हज़ार करोड़ की लगत से शुरू किया गया है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थय सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि आने वाले संकट के लिए भी देश को तैयार किया जायेगा। ऐसे समय में आज हर गरीब के ज़िम्मेदारी को लेते हुए 80 हज़ार से अधिक हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स और करोड़ो की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से मदद मिले है। हमसबको पता है पहले देश में विदेशी दवाइयों के दाम किस प्रकार थे बहुत से लोग दवाइयों का खर्चा भी व्यय नहीं कर पाते थे परन्तु देश में ही निर्मित दवाइया जेनेरिक मेडिसन अब जन आयुषी केंद्रो पर उपलब्ध है यहाँ पर काम कीमत पर दवाइया उपलब्ध कराकर इलाज़ पर होने वाले खर्च को कम किया है।

हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने 157 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है. जिससे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीटें करीब दोगुनी हो जाएंगी. हमारी सरकार की कोशिश रही है कि लोगों को किफायती इलाज दिया जाए. उन्होंने कहा कि कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज और जांच प्राइमरी लेवल पर हो सकेगा. इसके लिए 1.50 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का फैसला किया गया है. इनमें करीब 79,000 सेंटर्स की शुरुआत हो चुकी है. मैं प्रधान मंत्री एवं स्वस्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ की आज AIIMS बिलासपुर बन कर तैयार हो चूका है और वह OPD भी शुरू हो चुकी है।

महोदय आज मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी के नेतृत्व में स्वामित्व योजना जिसके अंतर्गत अब तक 27 हज़ार गाँवों में 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके है। किसान रेल योजना से आज हिमाचल का सेब समय रहते देश के कोने कोने में भेजा जा रहा है। इससे किसानो की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया है। ऐसा देश में पहली बार हुआ है की किसान रेल के माध्यम से 150 से अधिक मार्गो पर 1900 से जायदा किसान रेल चलाई गयी और करीब 6 लाख मेट्रिक टन कृषि उत्पादों की ढुलाई की गयी। इस नयी सोच के साथ आज किसान उन्नति की और बढ़ रहा है। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1 लाख 80,000 करोड़ रूपये दिए गए जो सीधा किसान के खाते में डाले गए। आज देश के किसानो को ख़राब मौसम या अन्य कारणों से होने वाले नुक्सानो से निपटने के लिए किसान फसल बिमा योजना के अनर्तगत 1 लाख करोड़ रूपये से जायदा की राशि दी जा चुकी है। यह नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है जो किसानो, मजदूरों का दुःख दर्द समझती है और उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलती है।

पराम् आदरणीय भारत रतन पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपयी जी के सपनो और लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए आज देश में सड़को का जाल बिछ रहा है।स्वर्गीय अटल जी का सपना अटल टनल का निर्माण पूरा हो चूका है और देश के नागरिको को समर्पित किया जा चूका है। यह भी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज ग्रामीण इलाको में 100 किलोमीटर प्रति दिन से अधिक की रफ़्तार से 36 हज़ार 500 किलोमीटर सड़के

बनायीं गयी और हज़ारो रिहायशी क्षेत्रों को ALL WHEATHER CONNECTIVITY से जोड़ा गया है। आज हम देख सकते है पुरे देश के साथ साथ किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सडको का जाल तीर्व गति से बनाया जा रहा है शायद ही कोई ऐसा गाँव है जो सड़क से न जुड़ा हुआ हो। मैं इस पर माननीय प्रधान मंत्री जी , माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी जी और सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

“हर क्षेत्र में आज भारत नया भारत बनकर उभरा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्टर हो परिवहन हो, नयी शिक्षा निति”

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में आज सशस्त्र बलो के आधुनिकीकरण के लिए 87 % स्वीकृत्या 'मेक इन इंडिया ' श्रेणी से थी। आज 209 उपकरणों की सूचि जारी की गयी है जिन्हे विदेश से नहीं ख़रीदा जायेगा तथा 2800 से अधिक रक्षा उपकरण की घरेलू स्तर पर निर्माण किया जायेगा। यह सब नए भारत , आतम निर्भर भारत की पहचान बनेगे।

समय के अभाव को देखते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा की आज पूरा देश हमारे यशश्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करता है उन साथ चलता है उनकी नीतियों को समझता है। और उनके दिए गए मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ।

(इति)

*__श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली):__ आदरणीय अध्यक्ष / सभापति महोदय मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ की आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद् प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

अमत महोत्सव: आज देश एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में होने के कारण भारत में अपनी सामर्थ्य शक्ति अब परिलक्षित हो रही है। देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष को अमतृ महोत्सव के रूप में मना रहा है। हमारा देश यह वर्ष गुरुतेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, श्री अरबिंदो जी की 150वीं जयंती, श्री वी.ओ.चिदंबरम पिल्लई जी का 150वां जन्म और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे पुण्य अवसरों को सरकार बड़े धूम धाम से मना रहा है, साथ ही हमारे प्रधानमन्त्री जी ने साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसम्बर को बीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। देश में जनजातीय समाज को गौरवान्वित करने के लिए 15 नवम्बर को भगवान् बिरसा मुंडा के श्रधांजलि स्वरुप जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह हमारी सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आगामी 25 वर्षों के लिए संकल्पों को आकार दिया जा रहा है। इससे साफ़ स्पष्ट होता है की हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के पथ पर चलकर देश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का कार्य बहुत तेज गति से कर रही है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

कोविड-19 : हमारी सरकार ने कोविड-19 जैसे आपदा को भी अवसर में बदलने का कार्य किया है। कोविड-19 की महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हमारे देश में भी कोविड-19 के दुसरे लहर में देश के अधिकतम परिवारों ने अपने सगे सम्बन्धियों को खोया है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी सरकार ने मजबूती से इस विकट परिस्थिति का सामना किया और हमारे देश ने 2-2 वेक्सीन बनाने का काम किया और देश वासियों को सुरक्षित करने का कार्य किया। हम सभी ने देखा की महामारी के दौरान देश में ऑक्सीजन की कितनी कमी आ गयी थी, हर तरफ भय का वातावरण बन रहा था परन्तु आदरणीय प्रधानमन्त्री जी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए देश में न केवल कई ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करवाई अपितु यह भी सुनिश्चित किया की आगे किसी भी आपदा में देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत एक साल से कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वेक्सीन की डोज लगाने का रिकॉर्ड बना चूका है जिसमे 90% से अधिक व्यस्क नागरिक टिके की **1**st डोज और 70% से अधिक अपनी दोनों डोज ले चुके है और अब देश में आठ वेक्सीन की स्वीकृति मिल चुकी है। WHO ने तीन वेक्सीन को मंजूरी भी दे दी है। हमारे यशश्वी प्रधानमंत्री जी की इस दूरदर्शिता से पूरा देश कृतज्ञ है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: हमारी सरकार तत्काल के चुनौतियों तक ही सिमित नहीं है बल्कि दूरदर्शी समाधान तैयार कर रही है जो भविष्य के लिए प्रभावी और उपयोगी

* Laid on the Table

रहेगी चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो या जन औषधि केंद्र हो या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो यह स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सराहनीय उदाहरण है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: कोरोना के इस महासंकट में देश में कोई भी भूखा न रहे इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कर गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन देने का काम किया है। इसके साथ गरीबों के स्वाभिमान एवं रोजगार की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चला रही है और श्रमिकों की रक्षा के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल भी शुरू किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना: मेरी सरकार मूलभूत सुविधाओं को गरीबों के सशक्तिकरण और गरीब की गरिमा को बढाने का माध्यम मानती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को दिए गए है।

जल जीवन मिशन: हर घर जल पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू किये गए जल जीवन मिशन ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। महामारी की ऐसी बाधाओं के बावजूद भी करीब 6 करोड़ ग्रामीण घरों को पेयजल से जोड़ा गया है।

किसान रेल सेवा: हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है, इस वैश्विक महामारी के समय में भी वर्ष 2020-21 में किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान और 33 करोड़ से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदवार की है। इस रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। सरकार के प्रयास से देश में कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। हमारे किसान भाइयों की फसल के अधिक दाम मिले इसके लिए उनके उत्पादों को बाजार तक पहुँचाना जरुरी होता है, इसके लिए सरकार ने किसान रेल सेवा शुरू कर देश के किसानों के खुशहाली के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोरोना काल में जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री के परिवहन के लिए 150 से अधिक मार्गों पर 1900 से ज्यादा किसान रेल चलायी गयी जिससे करीब 6 लाख मेट्रिक टन कृषि उत्पादों की ढुलाई हुई।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: हमारी सरकार ने देश के किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 180,000 करोड़ रूपये दिए हैं इस निवेश से आज कृषि क्षेत्र में कई बड़े बदलाव दिखाई दे रहें है। फसल बिमा योजना में नए बदलाओं का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। अब तक 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को मुवावजे के तौर पर एक लाख करोड़ रूपये से अधिक राशी दी जा चुकी है।

महिला सशक्तिकरण: हमारी सरकार में महिला सशक्तिकरण उच्च प्राथमिकताओं से एक है। मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे देश की माताओं बहनों की उदमिता और कौशल को बढ़ावा मिला है। सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प group सदस्यों को ट्रेनिंग देकर उन्हें बैंकिंग सखी के रूप में भागिदार भी बनाया है ये महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को घर घर पहुंचाने का माध्यम बन रही है।

देश में बेटियों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा निति में जेंडर इन्क्लूजन फण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

स्किल इंडिया मिशन: देश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को भी अनेक प्रोत्साहन दिया जा रहा है । स्किल इंडिया मिशन के तहत, आईटीआई, जन शिक्षण संस्थान और प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों के जरिये पूरे देश में सवा दो करोड़ से अधिक युवाओं का कौशल विकास हुआ है।

राष्ट्रीय शिक्षा निति: साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा निति में भी सरकार द्वारा व्यापक बदलाव किये गए हैं । इसके माध्यम से स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है । स्नातक पाठयकर्मो की महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में भी संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए इस वर्ष से 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढाई भी शुरू की जा चुकी है।

जनजातीय समाज के कल्याण हेतु एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल: जनजातीय समाज के कल्याण के लिए एवं जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए हर आदिवासी बाहुल ब्लॉक तक एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के विस्तार का काम किया जा रहा है । ये स्कूल लगभग साढ़े तीन लाख जनजातीय युवाओं को सशक्त बनायें जायेंगे ।

खेलो इंडिया: केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर देश में सैकड़ों खेलो इंडिया केंद्र स्थापित कर रही है जिसका निश्चित लाभ देश की युवा प्रतिभाओं को मिलेगा।

स्टार्टअप इको सिस्टम: स्टार्टअप इको सिस्टम हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रहा है । वर्ष 2016 से हमारे देश में 56 अलग अलग सेक्टर में 60 हजार नए स्टार्टअप बने हैं इन स्टार्टअप के जरिये 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योग(MSME): महोदय, भारत की समृधि में बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है । हम सभी को ज्ञात है की हमारे MSME's आत्मनिर्भर भारत को गति प्रदान करते हैं | MSME यूनिट्स को संकट से बचने और जरुरी क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने 3 लाख करोड़ रूपये के कोलैटरल फ्री लोन्स व्यवस्था भी की है । इस योजना की सहायता से साढ़े 13 लाख MSME यूनिट को जीवनदान दिया गया है और डेढ़ करोड़ रोजगार भी सृजित किये गए है । इसके अतिरिक्त MSME सेक्टर को विस्तार प्रदान करने तथा इस सेक्टर के लिए अवसर बढ़ाने हेतु हमारी सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: जैसा की हम सभी को ज्ञात है की हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर- विकास के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों के काम काज को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में एक साथ जोड़ने का कार्य कर रही है । ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों,संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से देश की उन संभावनाओं को उड़ान मिल रही है जो दशकों से उपेक्षित पड़ी थी । आज देश के नेशनल हाइवेज पूरे देश को एक साथ जोड़ने का कार्य कर रहें हैं । मार्च 2014 में हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 90 हजार किमी थी जबकि आज उनकी लम्बाई बढ़कर एक लाख चालीस हजार किमी से अधिक हो गयी है । भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख करोड़ रूपये की लागत से 20,000 किमी से अधिक लम्बाई के

राजमार्गों पर कार्य किया जा रहा है।

हमारी सरकार में भारतीय रेलवे का भी तेजी से आधुनिकीकरण हो रही है। नई वन्दे भारत ट्रेने तथा नए विस्टाडॉम कोच भारतीय रेल की आभा में वृद्धि कर रहें हैं। बीते सात वर्षों में 24 हजार किमी रेलवे रूट का विधुतीकरण हुआ है। गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन और मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आज आधुनिक भारत की नई तस्वीर के रूप में उदहारण हैं। हमारी सरकार ने रेलवे के साथ साथ बंदरगाहों एवं एअरपोर्ट पर भी कई कार्य किये है।

हमारी सरकार ने देश में 21 ग्रीनफ़ील्ड एअरपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी देकर यह सन्देश दे दिया है की विकास हर क्षेत्र में हो रहा है। इसके साथ ही देश के कई महत्वपूर्ण कारोबारी क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 80 से अधिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है। अब तक 24 राज्यों में 5 मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों और 106 नए जलमार्गों सहित कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है, इनमे से 23 जलमार्गों के जरिये माल परिवहन भी हो सकेगा।

अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ की उन्होंने देश के समक्ष सरकार के विकास कार्यों का अपने अभिभाषण में पूर्ण उल्लेख किया। मैं महामहिम के द्वारा दिए गए अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(इति)

***श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर)**: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संसद के दोनों सदनों की साझा बैठक के समक्ष दिनांक ३१ जनवरी २०२२ को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आज सदन में माननीय सदस्य श्री हरीश द्विवेदी जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करती हूँ।

हम इस वर्ष भारत की आजादी का ७५वां साल पर अमृत महोत्सव मना रहे है, बीते तीन साल से पूरा विश्व वैश्विक महामारी का सामना कर रहा है ऐसी स्थिति में भी भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्य-परायणता से एकजुटता दिखाकर इस महामारी का सामना बढ़ा धैर्य से किया है अपितु इस महामारी को बाकी देशो से हमारे देश में तुलनात्मक कम असर होता हुआ नजर आ रहा है और विश्व की अर्थव्यवस्था जो बड़े बड़े विकसित देशों में अस्तव्यस्त स्थिति में है हम भारतीय व्यक्तियों ने सरकार के सारे दिखाए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस महामारी का सामना किया और धीरे-धीरे व् निरंतर तरीकेसे इस अपूर्वानुमेय स्थिति पर विजय भी प्राप्त किई ऐसा नजर आ रहा है| महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने सारे भारतीय लोगों की एकजुटता की प्रशंसा की और सभी भारतीयों का इस साहस, सयम, अनुशासन एवं सेवाभाव के प्रति सराहना की।

यह वर्ष भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का वर्ष रहा है जिसमे काशी विश्वनाथ धाम व केदारनाथ धाम का सौंदर्गीकरण व विकास, आदि शंकराचार्य की समाधी का जीर्णोद्धार, देवी अन्नपूर्णा की चोरी हुई मूर्ति का जीर्णोद्धार, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और धोलवीरा एवं दुर्गा पूजा उत्सव के लिए विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त करने जैसी पहल भारत की विरासत मजबूत करने हेतु किये हुए प्रयास व् प्राप्ति के लिए मै तथा भारत के समस्त देशवासी हमारे आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को इस महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसने न केवल सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, बल्कि विश्व में भारत के तीर्थयात्रा व पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूत करने का कार्य किया है।

कोरोना महामारी में लिप्त दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इस से प्रभावित हुआ इस स्थिति में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने देशको सामर्थ्यशाली बनाने के लिए सरकार के समय समय पर दिए फैसलों एवं कोविड-१९ से संबधित सभी प्रोटोकोल का पालन करते हुए देश को एक नये शक्तिशाली नव भारत के रूप में खड़ा किया है। आज भी विश्व के हर देश को अभीभी ओमिक्रोन व् डेल्टा वायरस से झुंझने के लिए कोशिश लगातार करनी पड़ रही है तथा इस वायरस की महामारी का संक्रमण रोकने एवं इससे बाहर निकलने के लिए बहुत कठिन परिश्रमों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे देशमें हमने इस महामारी का सामना हर सफल कोशिश करते हुए पीड़ितों की संख्या कम से कम रखने और कुछ संक्रमित मरीजों की ठीक होनेकी संख्या भी बहुत अधिक बढ़ाने में कामयाब हुए है, मै देशके महामहिम राष्ट्रपति और देश के सफल प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्रभाई मोदीजी को बहुत बहुत धन्यवाद् देना चाहती हूँ जिनकी प्रेरणा व् सतत मार्गदर्शन में हमने यह सफलता पाई है।

* Laid on the Table

इस महामारी को रोकने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दीन रात मेहनत कर के कोरोना **टी**काकरण यशस्वी करने का काम किया है और इस कोरोना महामारी का विश्व का सबसे बड़ा **टी**काकरण प्रोग्राम देश भर में १६ जनवरी से आरंभ हुआ था तबसे २०२२ वर्ष के जनवरी माह के पहिले सप्ताह तक १५० करोड़ कोविड टीकाकरण की खुराक लगानेका ऐतिहासिक आकड़ा पार किया है व अहम उपलब्धि हासिल कियी है। देशके डॉक्टरों, विज्ञानिकों, नवोन्मेषकों और टीका लगने वाले **स्वास्थ्य** कर्मियों **से** यह टीकाकरण अभियान सफल करने मे योगदान मिला और भारत के देशवासियों ने इस विश्व के सबसे टीकाकरण को यशस्वी बनाते हुए कोविड महामारी को रोकने में सफलता पाई है इसलिए देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने प्रत्येक हेल्थ व फ्रंट लाइन वर्कर के कार्य की सराहना करते हुए उन सभी का अभिनंदन भी किया है। मैं इस देश में यशस्वी टीकाकरण के लिए ही नहीं, अपितु विश्व के ऐसे सभी गरीब व पिछड़े देश जो कोरोना महामारी से त्रस्त थे और उसे रोकने के लिए इन देशों में प्रतिकूल परिस्थितियां होने से साधन सामग्री की कमी महसूस हो रही थी। ऐसे लगभग सभी देशों में वैक्सीन डोसेज की आपूर्ति करने का मानवीय संवेदना का एक चेहरा सामने आया। इसलिए मैं विश्व में भारत की एक नई छवि निर्माणकर्ता देश के सफल प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से देती हूं।

आयुर्वेद और योग, भारत की अति प्राचीन संस्कृति को हमारी सरकारने जो बढ़ावा दिया उससे इस महामारी से डट कर लड्नेका साहस हमारे देशवासियों को मिला है इस योग विद्या का अनुकरण विश्व भर किया जा रहा है जिसके चलते इस योग विद्या सिखाने के लिए विश्व के अनेक देश से मांग है एक नये रोजगार निर्माण की शुरुवात इससे हुयी है, बड़े पैमाने में युवक और युवतियाँ यह योग विद्या सिखने के लिए आगे बढ़ रहे है। दुनिया के सबसे पहले WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ़ ट्रेडिशन मेडिसिन की स्थापना हमारे देश भारत में हो रही है यह एक हमरे प्राचीन योग, आयुर्वेद एवं भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए गौरवपूर्वक है। मेरे रावेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कृषि क्षेत्रसे जुडा ज्यादातर व्यापार व् रोजगार है कृषि क्षेत्र की उपजाऊ जमीन व् साधन सामुग्री की उपलब्धता भी है इसलिये आयुर्वेद वनस्पति के निर्माण के लिए एक सरकारी योग एवं आयुर्वेद विद्या अभ्यास संस्था गठित करने का मै सरकारसे निवेदन करती हूँ।

किसानों को अपनी फसल के अधिक दाम मिले इसलिये किसान जहाँ चाहे और उसे जहाँ उचित भाव मिले इसलिये देश में किसान रेल सेवा शुरू कियी जिससे अबतक १५० से अधिक मार्गों पर यह रेल चलाई यह सराहनीय कदम है। मेरे रावेर लोकसभा क्षेत्र में केले का सर्वाधिक उत्पादन होने से रावेर व सावदा इन स्टेशन से दिल्ली से आगे फूट मंडी आदर्शनगर के लिए एक किसान रेल सेवा शुरू करने की मांग करती हूँ जिससे हमारे केले उत्पादन लेने वाले किसान भाई को अपनी केले की फसल को मेट्रो सिटीज में डायरेक्ट केले पहुचाने और उचित भाव काम ट्रांसपोर्ट खर्चे से हो यह सुविधा उपलब्ध होगी।

वर्षा जल संरक्षण के लिए गंभीरता से काम कर रही हमारी सरकार रेन हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण व पारंपरिक जल-स्त्रोतों के जीर्णोद्धार के विशेष अभियान का काम चल रहा है, मेरे रावेर

लोकसभा क्षेत्र में जमीन को आर्टिफीसियली रिचार्ज करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड (CGWB) के माध्यमसे मेगा रिचार्ज स्कीम जो देशमें स्थापित होनेवाली अपनी तरह की पहली एवं पायलट परियोजना है जिसमे सातपुडा की कछार में बज़ाडा नामक झरने वाले क्षेत्रमें तापी नदी के बाढ़ नहर निर्माण करके जमीन रिचार्ज कराना प्रस्तावित है| इस परियोजना की विस्तृत कार्ययोजना (DPR) का कार्य कार्यान्वित है, मै इस महामहिम राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद् प्रस्ताव के माध्यम से ऐसे पायलट परियोजना मेगा रिचार्ज को सरकार रेन हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर व् अटल भू-जल योजना की मदद से बहुत हेक्टर सिंचाई क्षमता का विकास होगा इसलिये अति शिघ इस योजना को गति देनेके लिए फंड्स आवंटित करने की मांग करती हूँ जिससे से बाढ़ नहर निर्माण करनेका कार्य जल्द शुरू हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने तथा जमीन रिचार्ज एवं जल संवर्धन/संरक्षण का कार्य भी होगा।

कृषि क्षेत्र को और लाभदायी बनाने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हमारी सरकार ने एक लाख करोड़ रूपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को स्थापित किया है इस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मेरे क्षेत्र में केले की खेती करनेवाले किसानों को कोल्ड स्टोरेज, रायपेनिंग सेंटर का निर्माण करनेके लिए और केले के क्षय (Waistage) होनेवाले स्कंध/डंडी (Banana Pseudostem) से धागा निर्माण करनेके लिए एवं निष्कर्षण के तुरंत बाद निकलनेवाले रंगहीन साफ पानी (Banana PseudoStem SAP) को आर्गेनिक बायो फ़र्टिलाइझर के माध्यम से लगभग सभी फसलों को लिए उपयोग किया जा सकता है। बीपीएस मिट्टी को ठीक करने और पत्तेदार सब्जियों की उपज, पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करता है। बीपीएस में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं, इसलिए इसका उपयोग खिलाड़ियों के लिए ऊर्जा बूस्टर के रूप में या समान अनुप्रयोगों के लिए ऊर्जा पेय के रूप में किया जा सकता है। बीपीएस का उपयोग औषधीय उद्देश्य के लिए रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, त्वचा पोषण को कम करने और डंक या काटने की बीमारी के रूप में भी किया जा सकता है। Banana Pseudostem का निपटान किसनों के लिए एक समस्या है जिसका उपयोग स्थायी कृषि, खाद्य प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सौंदर्य प्रसाधन और वस्त्र के संदर्भ में बीपीएस के मूल्यवान कपड़ा और गैर-कपड़ा अनुप्रयोग पर हाल की झलक का प्रतिनिधित्व कर सकता है, इसलिये मै इस महामहिम राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद् प्रस्ताव के माध्यम से Banana PseudoStem प्रोसेसिंग के उद्योग का निर्माण मेरे रावेर लोकसभा क्षेत्र में करने केलिए सरकार से मांग करती हूँ जिससे किसान भी लाभान्वित होगा और इस हाल ही में क्षय (Waistage) होनेवाले बनाना stem से कई फायदेमंद चीजों का निर्माण हो सकता है।

जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने आदिवासी बहुल ब्लॉक्स में नये आवासीय मॉडल स्कूल खोलने का काम प्रगतिशील है। मेरे रावेर क्षेत्र में तीन ब्लॉक्स में आदिवासी बहुल जनजातीय क्षेत्र हैं, इसलिएय हां एक एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के निर्माण के लिए इस महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूं, जिसमें निर्माण से इस क्षेत्र के जनजातीय बालक व युवाओं को शिक्षा का अवसर मिल सके।

प्रधान**मं**त्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत कई गरीब परिवारों को पक्का मकान का आवंटन हुआ है जिससे गरीब सशक्तिकरण और गरीब की बढ़ावा मिला है। यह आवंटन प्रक्रिया Socio-Economic Caste Survey २०११ के आधार पर हर ग्राम स्तर पर प्राथमिकता से गठित कियी जिसमें SC/ST केटेगरी को पहले शामिल किया है। मेरे क्षेत्र में २०११ के सेन्सस के माध्यमसे गठित २०१८ को लाभार्थियों की सूचि में इन तीन वर्षों में एक करोड़ सत्रह लाख आवास को स्वीकृति मिली है अपितु अभीभी जरूरतमंद और कई गरीब परिवारों के नाम २०११ के सेन्सस को ध्यान में रखते हुए शामिल होना अभीभी बाकी है और बहुतांश ग्रामीण स्तर पर यह कार्य केंद्र व राज्य सरकार की अनुदान से लंबित है, जिल्हे के पीएम आवास ग्रामीण योजना की २०१८ की सूचि का एक बार फिरसे अवलोकन करने की तथा नये रूप से यह सूचि बनानेका आग्रह मै इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से रखती हूँ जिससे गरीब व वंचित परिवारों के नाम देशके हर ग्रामीण क्षेत्र से शामिल हो और इन परिवारों को उनका अपना एक आवास आवंटित हो और ऐसे आवास के निर्माण हेतु जिनको सरकार के माध्यमसे मंजूरी मिली है उस आवास के काम के लिए लंबित अनुदान की राशि उन्हें जल्द से जल्द अनुदान वितरित करने का मै सरकार से निवेदन करती हूँ। ऐसे ही पीएम आवास शहरी योजना के लिए भी अनुदान भुगतान मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सभी नगर परिषद बाकी है उन्हें तुरंत रिलीज करने का भी निवेदन सरकार से करती हूँ।

सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि क्षेत्र जगत के हित के लिए, देश के हित में, गांव गरीब के उज्वल भविष्य के लिए पूरी निष्ठा से, कि**सा**नों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत के साथ किसानों के लिए तीन कानून लाये, जिसका उदे**श्य** किसानों को खासकर छोटे किसानों को ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही क़ीमत किसानों को खासकर छोटे किसानों को ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत तथा उपज बेचनेके लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले जिससे किसान को अपनी उपज के सही दाम मिले लेकिन यह सब पुर्ण रूप से शुद्ध हेतु, किसानों की हित की बात कई प्रयासों के बावजूद कुछ किसनों को सरकार समझा नहीं पाई इसलिये एक साहसपूर्ण निर्णय, यह तीन कृषि कानूनों को निरस्त करनेकी प्रक्रिया भी आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी ने पूरी कियी जिससे उनकी कृषि विकास और किसान कल्याण की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदर्शित होती है, राष्ट्रहित के लिए पुर्ण प्रतिबद्ध एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर अटूट आस्था, "राष्ट्र सर्वोपरि" के मंत्र को चरितार्थ करते हुए दिखती है जिससे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का एक अद्भुत मानवीय, लोकतांत्रिक, विश्वसनीय एवं कर्तव्यनिष्ठ चेहरा पुरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में सामने आया है जो पुनः एक बार हमारे पंतप्रधान माननीय श्री नरेन्द्र मोदीजी को सर्वाधिक प्रभावशाली नेता के रूप में दर्शाता है।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से ऐसा परिलक्षित होता है की सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, अल्पसंख्यांकों और युवाओं के प्रति समर्पित तथा हाल ही में कोरोना कोव्हिड-१९ वैश्विक महामारी से हर भारतीय को जहाँ तक हो सके हर एक व्यक्ति तक टीकाकरण पहुंचे, उसी तरह हर प्रकार की मेडिकल सुविधा पहुचाने और उनको स्वास्थ्य अच्छा रखने के एवं इस प्रति**कू**ल परिस्थितियों ने आर्थिक उन्नति के लिए लगातार प्रयत्नशील है। मेरी सरकार आदरणीय प्रधान मंत्री

श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी संविधान की मूलभावना का आदर करते हुये देशमे सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने औए आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने और हर भारतीय को जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी बचाव के लिए हर आयु के भारतीय नागरिक को वॅक्सिन मिलने हेतु कटिबद्ध है। इसी श्रद्धा के साथ यह वर्ष हम आजादी की ७५वां वर्ष अमृत महोत्सव से हर्ष से मनाते हुए देश के हर नागरिक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए एवं विश्व के सभी को एकजुट होकर कोरोना टीकाकरण प्रोग्राम की सफलता को प्राप्त करते और बढाते हुये **भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण** पर आज सदन में माननीय सदस्य श्री हरीश द्विवेदी जी जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका पुनः समर्थन करती हूं।

(इति)

*__श्री जनार्दन मिश्र (रीवा)__: अध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों से हम कोरोना महामारी की विभीपिका झेल रहे है। एकाएक आयी इस महामारी का सामना करने के लिए प्रारम्भ काल में हमारे पास मूलभूत आवश्यकताओ की भारी कमी थी। परंतु तेजी के साथ केंद्र सरकार ने उन कमियों को दूर किया वह गति अभूतपूर्व थी।

इस महामारी से लड़ने के लिए दवाइयाँ, वेंटिलेटर, ओक्सीजन की आपूर्ति जिस तेजी से की गयी उससे हम काफ़ी हद तक नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहे। यही नहीं थोड़े से काल खंड में जिस तत्परता के साथ हमारे वेज्ञानिको डाक्टरों ने कोरोना वेक्सीन इजाद की तथा बल्कि एक व्यापक वेक्सिनेशन कार्यक्रम चलाया गया और लगभग 70% नागरिकों को की दो डोज़ लगाई जा चुकी है।

यह अभियान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज अभियान सिद्ध हुआ है। इस अभियान ने देश के नागरिकों को कोरोना से रक्षा का एक कवच प्रदान किया। यही कारण है कि आज जब देश कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावित है परंतु उसकी भयावहता काफ़ी हद तक कम हुई है। इसके लिए केंद्र सरकार की स्पष्ट और दूर दर्शी नितियो के साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़े सभी घटक धन्यवाद के पात्र है देश उन सबका आभारी है।

देश में निर्मित कोरोना वेक्सिनो का लाभ केवल भारतवासियो को ही नही बल्कि पूरी दुनिया को प्राप्त हो रहा है। सरकार ने तात्कालिक चुनोतियों से निपटने के साथ ही साथ दूरगामी समाधान तेयार कर रही है। जिससे भविष्य में एक मजबूत स्वास्थ्य शृंखला तैयार होगी। 64 हज़ार करोड़ रुपयों से प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक प्रमाण है। देश में गरीब भी गंभीरतम बीमारियों की चिकित्सा करा पा रहा है इसमें आयुष्मान कार्ड योजना से मदद मिल रही है।

केंद्र सरकार ने भारतीय पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को बढ़ावा दिया और पूरी दुनिया में कोरोना काल में भारतीय चिकित्सा पद्धति योग, आयुर्वेद के महत्व को समझा और अपनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा का केंद्र भारत में स्थापित करने जा रहा है। इन सारी उपलब्धियों के पीछे हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी की दूरदृष्टि साफ़-2 परिलक्षित होती है।

कोराना महामारी का संकट 100 वर्षों के काल के सबसे भयावह काल रहा है परंतु इस विपत्ति के समय कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाये , 80 करोड़ गरीबों को लगातार हर महीने मुफ्त में राशन दिया जा रहा है जिसमें अभी तक 2 लाख 60 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे है। यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान वितरण कार्यक्रम है। कोरोना काल में जिन रेहड़ी पटरी वालो का रोज़गार संकट में फस गया था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 28 लाख लोगों को 29 सौ करोड़ रुपयों से ज़्यादा राशि प्रदान की गई है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए ई-श्रम पोर्टल प्रारम्भ किया गया है जिसमें अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके है। ग़रीबों को भी सम्माजनक आवास सुविधा उपलब्ध हो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक घर मिल चुके है।

---

* Laid on the Table

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए भी डेढ़ सौ करोड़ रुपयों की लागत से 1 करोड़ 17 लाख घर स्वीकृत किए जा चुके हैं।

हर घर जल योजना के तहत कोरोना काल में भी 6 करोड़ ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ा गया है। इससे माताओं-बहनों को बड़ी राहत मिली है। स्वामित्व योजना के तहत 27 हज़ार गावों में 40 लाख से अधिक प्रोपर्टी कार्ड दिये जा चुके है जिससे गाँव के लोगों को बेंको से मदद आसान हो गई है।

सरकार किसान और किसानी को अधिक मजबूत करने में जुटी है। पिछले वर्ष 30 करोड़ टन से अधिक अनाज व 33 करोड़ टन से अधिक बाग़वानी उत्पादों की पैदावार की है। इसे देखते हुये रबी की फसल के दौरान 433 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गयी जिससे 50 लाख किसानो को फ़ायदा हुआ ख़रीफ़ में 900 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की जिससे 1 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित हुए। यह एक रिकार्ड है। जो दर्शाता है कि सरकार किसानो के उत्पाद को MSP के तहत खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है।

फसल का अधिक दाम किसानो को मिल सके इसके लिए किसान रेल सेवा प्रारम्भ की गई। 1900 से ज़्यादा किसान रेल चलाई गई। जिससे फल, सब्ज़ी, दूध जैसी जल्दी ख़राब होने वाली सामग्री को बचाया गया। इन सारे प्रयासों के कारण कृषि निर्यात में 25% से ज़्यादा वृद्धि हुई है। निर्यात की क़ीमत लगभग 3 लाख करोड़ पहुँच गई है।

देश के छोटे किसान ज़्यादा मजबूत हो उनकी कृषि उत्पाद क्षमता में वृद्धि हो इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपए दिए गए है। सरकार प्राकृतिक खेती, आर्गेनिक खेती एवं फ़सलो के विविधिकरण के माध्यम से किसानो को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है।

महोदय, वर्षा जल सरंक्षण के साथ ही साथ सिचाई के क्षेत्र में 64 लाख हेक्टर सिचाई क्षमता विकसित की गई है। बहुत प्रतीक्षित नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत 45 हजार करोड़ रूपये की केन-बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इससे पूरे बुन्देल खंड को कृषि एवं पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध होगी।

महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका को रेखांकित किया जा रहा हैं। मुद्रा योजना से महिला उद्यमियों की व्यापारिक गतिविधियों का फायदा हुआ है।

शादी की उम्र 21 वर्ष की जा रही है, तीन तलाक को कानूनी अपराध घोषित किया गया है। रोजगार सृजन के लिए स्टार्ट अप, ईको-सिस्टम के माध्यम से युवाओ के लिए अनंत सम्भावनाओ के द्वार खुले है। स्टार्ट अप के माध्यम से 2016 से अब तक लगभग 60 लाख से अधिक रोजगार सृजित किये गए है। कोरोना काल में 40 से अधिक युनीकोर्न अस्तित्व में आये है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 7400 करोड़ रूपये के लगभग है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रिय मास्टर प्लान के माथ जोड़ा गया है।

ग्रामीण इलाको में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100 किमी सड़के प्रतिदिन की रफ़्तार से 36 हजार 500 किमी सड़के बनायीं गयी है। 6 लाख करोड़ की लागत से 20,000 किमी के राजमार्गों पर काम चल रहा है।

BRO ने लदाख उमलिंग ला दर्रा पर 19 हजार मीटर की उचाई पर विश्व की सबसे ऊँची परिवहन योग्य सड़क का निर्माण किया है।

ड्रोन टेक्नोलोजी पर सरकार काफी गंभीर है इस दिशा में सिम्पली फाईड ड्रोन रूल्स 2021 को अधिसूचित किया गया है।

सैन्य बलों का आधुनिकरण किया जा रहा है इसके लिए जो स्वीकृतिया दी गई है उनमे 87% उत्पादों में मेक इन इण्डिया को प्राथमिकता दी गई है । 209 साजो सामानों को विदेशो से नहीं खरीदने की सूची बनाई गई है।

भारत ने विश्व समुदाय के समक्ष जलवायु परिवर्तन की चिन्ताओ में भारत की भूमिका को जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करने का संकल्प व्यक्त किया है।

COP-26 शिखर सम्मलेन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि भारत 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन डालर तक घटा देगा, भारत 2070 तक नेट जीरो बाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। भारत विश्व समुदाय को साथ लेकर ग्रीन ग्रिड एनिशिएटीव वन मन - वन वर्ल्ड - बन ग्रिड की पहल की है।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छता से प्रारम्भ की गई पहल से लेकर आज आधुनिकतम तकनीक अपना कर देश ने नई ऊंचाई प्रदान की है। निश्चित रूप से देश इन्ही नीतियों पर चल कर दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता विकशित कर रहा है।

महोदय, में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद

(इति)

*__श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र):__ अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

यह प्रस्ताव कल मेरे सहयोगी श्री हरीश द्विवेदी द्वारा उपस्थित किया गया और मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, वास्तव में देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए तैयार किया गया ब्लू प्रिंट है। इसमें ना केवल भारत के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का जिक्र किया गया है बल्कि इससे हमारी सरकार और हमारे देश के 130 करोड़ लोगों के दृढ़ आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति एक सजग एवं आशावादी दृष्टिकोण का भी पता चलता है।

इस अभिभाषण के आरंभ में ही इस बात का उल्लेख हुआ है कि भारत ने कोरोना जैसी भयंकर विश्व महामारी से निपटने में जो अग्रणी भूमिका निभाई है, वह बेजोड़ है। हमारी सरकार ने ना केवल अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा की बल्कि संकट की इस घड़ी में दुनिया के अधिकांश देशों को सहायता प्रदान की। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि कोरोना के उपचार हेतु, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित 8 टीकों में से 3 का निर्माण भारत में होता है।

आज देश के 90% से अधिक व्यस्त नागरिकों को टीके की एक खुराक लगाई जा चुकी है जबकि 70% से अधिक लोग दोनों खुराक ले चुके हैं। उक्त टीकाकरण के संबंध में, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया है, जोकि अमेरिका जैसे विकसित देश भी नहीं कर पाए हैं।

तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ, सरकार ने भविष्य में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 80 हजार से अधिक स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की स्थापना की है, 8 हजार से अधिक नए जन-औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। सुलभ और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आरंभ किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में, विश्व का पहला पारंपरिक चिकित्सा केंद्र भारत में स्थापित होने जा रहा है।

महोदय, पिछले 19 महीनों के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान वितरण कार्यक्रम चलाया गया। रेहड़ी-पटरी वाले भाई-बहनों के लिए प्रधानमंत्री स्व निधि योजना चलाई गई । श्रमिकों के लिए, ई श्रम पोर्टल आरम्भ किया गया, जिसमें 23 करोड़ श्रमिक जुड़ चुके हैं। जन- कल्याण के कार्यों को व्यवहारिक बनाने और बिना देरी लागू करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना और जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, सरकार ने 150 रेलमार्गों पर, 1900 से ज्यादा किसान रेल चलाई है जिनसे करीब 6 लाख मैट्रिक टन कृषि उत्पादों की ढुलाई की गई, 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए।

देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सरकार जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और फसलों के विविधीकरण पर जोर दे रही है। देश की समृद्ध कृषि परंपरा को सम्मान देते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

---

* Laid on the Table

सरकार ने उज्जवला योजना, मुद्रा योजना, तीन तलाक कुप्रथा को समाप्त करना, देश के सभी 33 सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश को सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं को भर्ती करना इत्यादि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम उठाए गए हैं। साथ ही, देश के जनजातीय युवाओं और दिव्यांग जनों के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई गई हैं।

महोदय, निर्विवाद रुप से, आज भारत, विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी विकास दर लगभग 9.5 प्रतिशत है। जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है तथा विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ रहा है।

हम आयातक की बजाय निर्यातक बनने की राह पर हैं। हमारा दवा, कृषि उत्पाद रक्षा सामग्री, वस्त्रों व वैज्ञानिक उपकरणों का निर्यात बढ़ा है। हमारा देश दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब और प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जहां इंटरनेट और मोबाइल फोन की कीमत सबसे कम है। ड्रोन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सैन्य सामान की जरूरतों को आत्म निर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी आपूर्ति से पूरा किया जा रहा है। आज हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट, तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल सहित रक्षा उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी मांग है और भारत इसका निर्यात कर रहा है।

दूसरी और, देश के बुनियादी ढांचे को तेज गति से एकीकृत व मजबूत करने के लिए रोडवेज, रेलवेज, वाटर वेज, एयरवेज को " प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान" के अंतर्गत लाया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र व पहाड़ी इलाकों को रेल और हवाई नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।

देश की प्राचीन विरासतों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार की जन कल्याण को समर्पित उपलब्धियों और महत्वाकांक्षा को माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैरा 79 में रेखांकित किया है। साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है।

महोदय, मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि निस्संदेह, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, हमारा देश अपने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सहित सभी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को गरिमा पूर्ण ढंग से प्राप्त कर लेगा। जय हिंद, वंदेमातरम।

(इति)

*लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे

2141 बजे

माननीय अध्यक्ष: महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिला है। अब शून्य काल में जो माननीय सदस्य राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल चुके हैं, उनको शून्य काल के अंदर मौका नहीं मिलेगा। क्या सदन इस पर सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

माननीय अध्यक्ष: अब शून्य काल के लिए बैलेट में जो नाम आए हैं, उन्हे बुला देंगे। आप सब अब एक-एक मिनट में बोलिए।

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Respected Speaker, Sir, although the PMNRF is not supported by any budgetary allocation, I would like to raise an issue pertaining to it because our hon. Prime Minister is the Chairman of the PMNRF. I request the hon. Prime Minister to enhance the sanction from 35 to a minimum of 100 cases per Member of Parliament per year under PMNRF to defray the medical expenses for patients, as the present limit is creating huge discontent among the constituents. Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the ESI Corporation has handed over the ESIC Medical College, Parippally in my Constituency to the Government of Kerala on the basis of a Memorandum of Understanding on 12th October, 2015. As per Clause 4 of the Memorandum of Understanding between ESI Corporation and the Government of Kerala, a clear-cut provision was there that all the benefits available to the insured persons under the ESI Scheme should be given to the insured persons, especially the cashew workers, similar to that of the ESI Scheme. But unfortunately, the Government of Kerala is not providing cashless treatment and no facilities are being provided to them. Therefore, the poor cashew workers and the insured persons are not getting better treatment in the Government Medical College, Parippally which has been handed over by the ESI Corporation after spending Rs.560 crore. So, I urge upon the Labour Ministry as well as the ESI Corporation to give a specific direction to the Government of Kerala, especially the Health Department, to provide sufficient treatment facilities, which are all available; and a separate

---

* Pl. see p. 471 for the list of Members who have associated.

block also be allotted to the insured persons in the Government Medical College, Parippally. This is my submission. With these words I conclude. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत जी।

आप सीनियर सदस्य हैं तो मैं आपको टोकूंगा नहीं। आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि जब मुम्बई में टैक्सटाइल्स मिल्स थीं और जब मुम्बई की बंदरगाह पर मुंबई पोर्टर्स का काम होता था तो मुम्बई शहर एक फुर्तीला शहर था। पिछले कई सालों से टैक्सटाइल्स मिल्स की हड़ताल क्या हुई कि सारी टैक्सटाइल्स मिल्स ध्वस्त हो गईं सन् 1995 में केन्द्र सरकार ने कानून बदलकर इसके रिवाइवल की बात की थी। मैं उस क्लॉज को आपके सामने पढ़ता हूँ। The Act was amended in 1995 to allow NTC to transfer, mortgage or dispose of land, plant, machinery or other assets for better management, modernisation, restructuring or revival of sick undertakings. अब ये सारी 77 कंपनीज़ बंद हैं, यानी मुम्बई की सारी मिल्स बंद है, लेकिन कुछ चालू हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ। कि अब हमारी नई सरकार आई है। इनको रिवाइव करने के लिए पूरे देश के एनटीसी के लोग आए थे। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि आप एक कंपोजिट बिल बनाइए। यहां पर एक प्लांट चालू है, वहां एक प्लांट चालू है तो मैं कहना चाहता हूँ कि सभी मिलकर एक जगह आ जाएं और वहां गारमेंट्स लाएं, जिससे जो बेरोजगारी बढ़ रही है, वह भी खत्म हो जाएगी, काम भी बनेगा और जो उपर्युक्त जमीन खाली पड़ी है, उससे सरकार पैसा भी खड़ा कर सकेगी।

(2145/RPS/RCP)

उससे बाकी लोगों का रिवाइवल कर सकती है। यह काम जल्दी से जल्दी करिए ताकि रोजगार भी उपलब्ध हो और जो काम कर रहे हैं, उनका भी काम आगे बढ़े। आपके माध्यम से मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ कदम उठाए।

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Thank you, hon. Speaker, Sir. Around 10 States have communicated to the Union Government of India protesting the proposal to amend the IAS (Cadre) Rules, 1954. These States include West Bengal, Rajasthan, Chhattisgarh, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Jharkhand and yesterday even the State of Odisha has voiced its concern to the Union Government of India.

Now, the Union Government's argument is that there is a shortage of officers under Central deputation. But during the last two years when the entire country has been fighting COVID-19, nowhere it has been recorded that had there been more officers under Central deputation, the response of the Union Government would have been better. So, this argument is totally flimsy. Rather we have seen that in the last two years, through the coordinated efforts of both

the Union and the State Governments, we have fought COVID-19 and we have implemented the vaccination programme at such a scale. Therefore, this new proposal to amend the Rules of the three AIS Cadres is a move which is a violation of the fundamentals of cooperative federalism. This is an attempt to influence IAS workers working in State Governments and prevent them from discharging their duties in an impartial and professional manner.

Knowing the tendency of the Union Government of manipulating law enforcement agencies during elections, the bureaucracy will become another tool in the hands of the Union Government to influence Assembly elections in the future.

Hon. Chief Minister of Rajasthan in his letter to the Union Government, as quoted in the media, has himself quoted late Sardar Patel who said: “A good All-India Service would be the one that has the freedom to speak their mind, which has a sense of security that you can stick to your word and where their rights and privileges are protected.”

Therefore, the Union Government must go back on his proposal to amend the IAS (Cadre) Rules, 1954. Thank you.

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): अध्यक्ष जी, रीवा लोक सभा क्षेत्र के उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज-इलाहाबाद मण्डल के तहत आने वाले डभोरा रेलवे स्टेशन पर लॉक डाउन से बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस, काशी एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, क्षिप्रा एक्सप्रेस आदि सभी गाड़ियों का ठहराव कई वर्षों से हो रहा था। अब इन गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है, परन्तु उपरोक्त गाड़ियों का ठहराव नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही, डभोरा रेलवे स्टेशन से अम्बेडकरनगर-प्रयागराज एक्सप्रेस को दोनों दिशाओं में दो-दो मिनट का ठहराव दिया जाए। साथ ही, पूर्व में इन गाड़ियों का जो ठहराव निर्धारित था, वह ठहराव फिर से प्रारम्भ किया जाए, जिससे रीवा जिले की 40 प्रतिशत आबादी के मरीजों, यात्रियों को आने-जाने की सुविधा प्राप्त हो सके।

LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Shri Janardan Mishra	Shri P. P. Chaudhary Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Nama Nageswara Rao Shrimati Supriya Sadanand Sule Shri Bhartruhari Mahtab Shri Jayadev Galla Shri Adhir Ranjan Chowdhury Shri Sudip Bandyopadhyay Shri A. Raja Dr. Farooq Abdullah Shri Ritesh Pandey	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri N.K. Premachandran	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar
Shri V. K. Sreekandan	Dr. DNV Senthilkumar S.
Shri Gaurav Gogoi	Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar
Shri Arvind Sawant	Shri Malook Nagar Dr. DNV Senthilkumar S. Kunwar Pushpendra Singh Chandel

माननीय अध्यक्ष: आज शून्य काल के लिए लिस्टेड के अलावा किसी माननीय सदस्य को मैंने नहीं बुलाया है, लेकिन जो माननीय सदस्य देर रात्रि तक बैठे हैं, मेरा प्रयास होगा कि जब भी शून्य काल होगा और और उस शून्य काल के अन्दर लिस्टेड के अलावा एक्स्ट्रा सदस्यों को बुलाऊंगा, मैंने उन सबके नाम नोट कर लिए हैं तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

सभा की कार्यवाही सोमवार, 7 फरवरी, 2022 को सायं 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

2149 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 7 फरवरी, 2022 / 18 माघ 1943 (शक)
के सोलह बजे तक के लिए स्थगित हुई।